IV वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और प्रदर्शन

वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र मजबूत रहा, जिसमें ऋण और जमाराशि दोनों में निरंतर वृद्धि उल्लेखनीय है। सभी बैंक समूहों में आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि देखी गई। पूंजी और चलनिधि बफर, विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे और लाभप्रदता में लगातार छठे वर्ष सुधार हुआ।

1. परिचय

IV.1 भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र ने 2023-24 और 2024-25 की पहली छमाही के दौरान निरंतर मजबूती दिखाई। मजबूत ऋण वृद्धि[1] के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन पत्र में द्विअंकीय विस्तार हुआ। बैंकों की लाभप्रदता लगातार छठे वर्ष बढ़ी और सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात के मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में न्यूनतम 2.7 प्रतिशत पर आने के कारण आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। बैंकों की पूंजीगत स्थिति संतोषजनक रही, जैसा कि उनके लीवरेज और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से परिलक्षित होता है। सभी बैंक समूहों ने उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बनाए रखते हुए चलनिधि से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया।

IV.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय को 17 खंडों में संयोजित किया गया है। खंड 2 में तुलन पत्र से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, इसके बाद खंड 3 और 4 में क्रमशः बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन किया गया है। खंड 5 बैंक ऋण और इसकी क्षेत्रक-वार गतिशीलता पर केंद्रित है। खंड 6 में वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व के स्वरूप पर चर्चा की गई है। कॉरपोरेट अभिशासन और मुआवजा प्रथाओं को खंड 7 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन को खंड 8 में शामिल किया गया है। इसके बाद भुगतान प्रणालियों (खंड 9), बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (खंड 10), उपभोक्ता संरक्षण (खंड 11) और वित्तीय समावेशन (खंड 12) से संबंधित घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) से संबंधित गतिविधियों की चर्चा खंड 13 से 16 तक में की गई है। खंड 17 में घरेलू वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

2. तुलन पत्र का विश्लेषण

IV.3 मार्च 2024 के अंत में, भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 21 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), 45 विदेशी बैंक (एफबी), 12 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), छः भुगतान बैंक (पीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और दो स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) शामिल थे। इन 141 वाणिज्यिक बैंकों में से 137 को अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि चार गैर-अनुसूचित थे[2]।

[1] इस पूरे अध्याय में, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा जाए, जुलाई 2023 से सभी वाणिज्यिक बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के डेटा में एक गैर-बैंक का एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय शामिल है और इसलिए डेटा पिछली अवधियों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हो सकता है।

[2] एससीबी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या अन्यथा के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2024 के अंत में, दो पीबी- जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दो एलएबी- कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भीमा समृद्धि एलएबी लिमिटेड गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे।

IV.4 आरआरबी को छोड़कर एससीबी के समेकित तुलन पत्र में 2023-24 के दौरान 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (विलय के प्रभाव सहित[3]), जबकि 2022-23 के दौरान यह 12.2 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी IV.1)। आस्तियों के मामले में, यह विस्तार बैंक ऋण में वृद्धि के कारण हुआ, जो एक साल पहले 17.4 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 2023-24 में 16.0 प्रतिशत बढ़ा (विलय के प्रभाव को छोड़कर)। एससीबी के निवेश में 2023-24 में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (विलय के प्रभाव को छोड़कर) जबकि एक साल पहले यह 11.4 प्रतिशत थी[4] (चार्ट IV.1)।

IV.5 एससीबी की समेकित तुलन पत्र में पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 57.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 55.2 प्रतिशत हो गई, जबकि पीवीबी की हिस्सेदारी 34.7 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई। एससीबी की कुल जमाराशियों में पीएसबी की हिस्सेदारी 59.3 प्रतिशत और कुल अग्रिमों में 55.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.1)।

IV.6 एससीबी की कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिमों की हिस्सेदारी 2023-24 के दौरान 2.2 प्रतिशत अंक बढ़ गई (चार्ट IV.2)।

2.1 देयताएं

IV.7 वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि वृद्धि 2023-24 में 13.4 प्रतिशत हो गई (विलय प्रभाव को छोड़कर)[5] जो एक साल पहले 11.0 प्रतिशत थी। पीवीबी के नई जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मार्च 2022 के अंत में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 6.6 प्रतिशत हो गई। उच्च सावधि जमा दरों ने चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों के

चार्ट IV.1: एससीबी की चुनिंदा समग्र राशियां
(मार्च के अंत में)

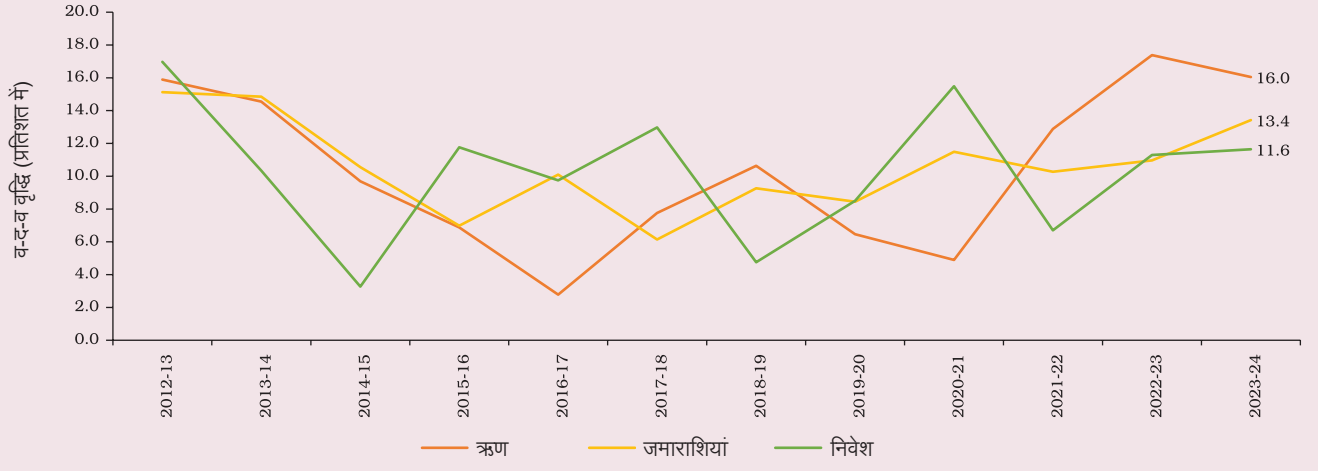

टिप्पणी: 2023-24 के लिए ऋण, जमाराशि और निवेश वृद्धि में किसी गैर-बैंक का निजी बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

[3] इस पूरे अध्याय में, विलय का तात्पर्य एक गैर-बैंक के एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय से है।

[4] विलय के प्रभाव को शामिल करते हुए, 2023-24 में बैंक ऋण और निवेश में क्रमशः 19.7 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[5] विलय के प्रभाव को शामिल करते हुए 14.0 प्रतिशत।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1. पूंजी	71,176	72,877	32,468	32,832	1,11,612	1,18,603	7,811	7,844	4,512	5,001	2,27,580	2,37,158
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,24,250	9,56,917	9,34,791	12,14,082	1,60,606	1,80,023	23,557	32,957	-2,404	-2,365	19,40,800	23,81,614
3. जमाराशियां	1,17,09,581	1,28,96,766	62,99,318	75,61,502	8,55,825	10,08,095	1,91,340	2,50,896	12,174	16,184	1,90,68,238	2,17,33,443
				(74,51,388)								(2,16,23,329)
3.1. मांग जमाराशियां	7,48,951	8,00,416	8,85,492	9,88,296	2,89,545	3,46,863	7,429	10,895	393	76	19,31,810	21,46,546
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	39,79,202	41,83,455	18,89,846	20,23,962	56,931	57,827	54,668	59,691	11,781	16,108	59,92,427	63,41,043
3.3. मीयादी जमा	69,81,428	79,12,895	35,23,981	45,49,244	5,09,349	6,03,405	1,29,243	1,80,310	-	-	1,11,44,001	1,32,45,854
4. उधारियां	9,03,824	10,24,003	8,12,969	12,84,429	2,08,739	2,03,073	31,190	28,255	519	713	19,57,241	25,40,474
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	5,05,949	5,42,671	3,65,924	4,28,526	2,30,921	1,96,198	13,619	15,331	8,156	5,135	11,24,570	11,87,862
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,40,14,781**	**1,54,93,234**	**84,45,470**	**1,05,21,372**	**15,67,704**	**17,05,993**	**2,67,517**	**3,35,284**	**22,957**	**24,668**	**2,43,18,429**	**2,80,80,550**
1. आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	6,41,731	6,18,769	4,13,201	5,32,690	93,411	1,05,980	17,840	17,503	2,295	3,004	11,68,479	12,77,947
2. बैंकों के पास जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4,23,343	4,34,252	2,36,116	1,89,051	1,19,332	74,865	4,530	6,305	4,963	4,313	7,88,284	7,08,785
3. निवेश	38,17,201	40,50,865	18,75,137	23,23,647	6,74,077	8,07,328	58,062	74,239	12,064	14,286	64,36,540	72,70,365
				(22,33,887)								(71,80,604)
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	32,22,899	34,84,382	15,87,677	19,88,718	6,31,129	7,33,803	52,137	63,824	12,049	14,271	55,05,891	62,84,999
ए) भारत में	31,65,076	34,23,192	15,73,022	19,73,422	5,88,166	7,25,476	52,137	63,824	12,049	14,271	53,90,449	62,00,185
बी) भारत के बाहर	57,824	61,190	14,655	15,296	42,963	8,327	-	-	-	-	1,15,442	84,814
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3.3 गैर-स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5,94,296	5,66,477	2,87,460	3,34,929	42,948	73,525	5,925	10,415	15	15	9,30,644	9,85,361
4. ऋण और अग्रिम	82,83,763	95,06,329	53,66,673	68,61,388	4,91,029	5,48,474	1,77,887	2,26,148	-	-	1,43,19,353	1,71,42,340
				(63,36,115)								(1,66,17,066)
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	2,84,863	3,57,393	1,34,836	1,50,780	65,506	84,506	872	1,444	-	-	4,86,077	5,94,124
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, *आदि*	29,10,286	33,64,717	16,98,188	19,67,085	2,07,287	2,39,685	18,266	26,966	-	-	48,34,027	55,98,453
4.3 मीयादी ऋण	50,88,614	57,84,218	35,33,648	47,43,524	2,18,236	2,24,283	1,58,750	1,97,738	-	-	89,99,248	1,09,49,763
5. अचल आस्तियां	1,15,288	1,18,864	49,347	56,755	5,624	5,956	2,735	3,353	564	1,189	1,73,558	1,86,117
6. अन्य आस्तियां	7,33,456	7,64,154	5,04,997	5,57,840	1,84,230	1,63,390	6,463	7,736	3,070	1,876	14,32,216	14,94,997

टिप्पणियां : 1. -: शून्य/ नगण्य।

2. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा एकत्र कर 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' प्रकाशित की जाती हैं, जो https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

3. कोष्ठक में दिए गए डेटा में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। अन्य सभी डेटा में विलय के प्रभाव को शामिल किया गया है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.2 : तुलन पत्र की संरचना

(मार्च के अंत में)

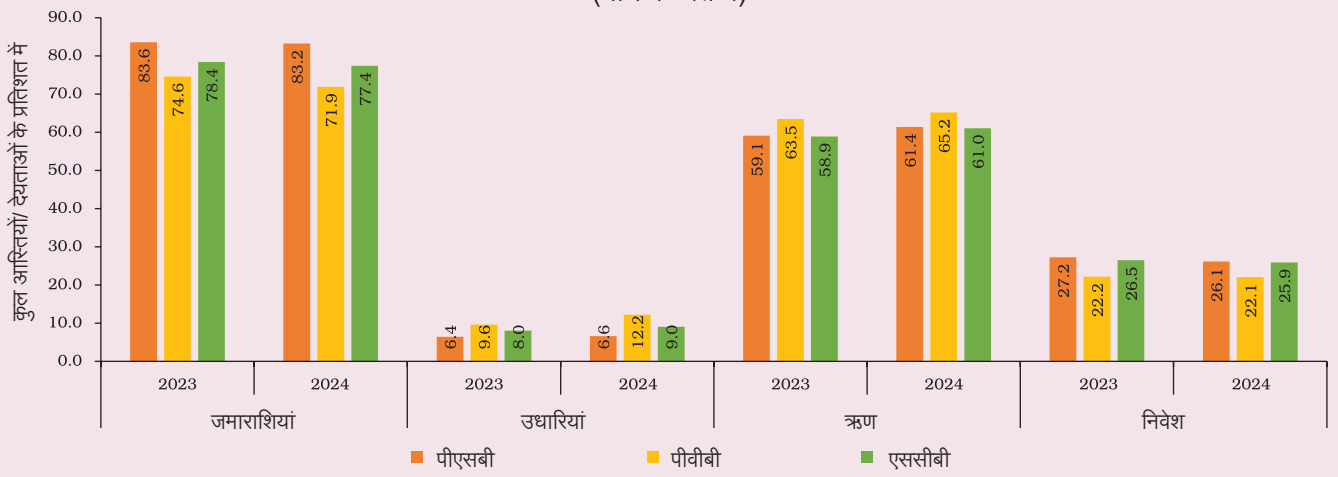

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

सापेक्ष सावधि जमाओं में वृद्धि की गति को तेज़ कर दिया (चार्ट IV.3)। लंबी अवधि में ब्याज दरों के बजाय आर्थिक गतिविधि का समग्र स्तर जमाराशि वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है (बॉक्स IV.1)।

2.2 *आस्तियां*

IV.8 आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण 2023-24 के दौरान ऋण वृद्धि मजबूत रही[6] (चार्ट IV.4ए)। मौद्रिक नीति रुख को दर्शाते हुए भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) वर्ष के दौरान स्थिर रही। नए ऋणों पर उधार दर में संचरण सामान्यत: पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए अधिक था (चार्ट IV.4बी)।

चार्ट IV.3 : जमाराशि वृद्धि

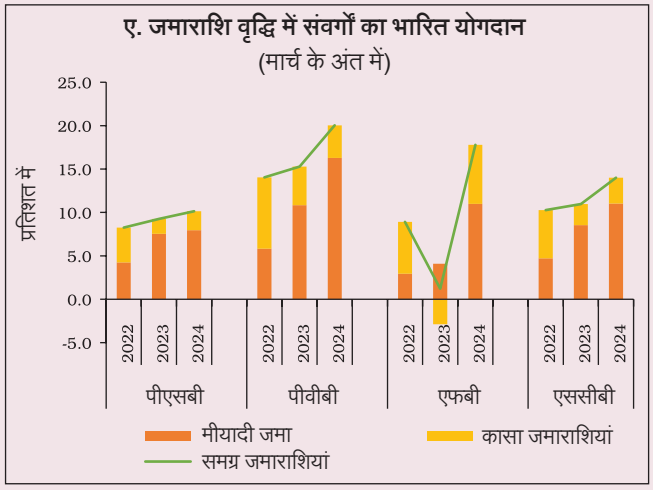

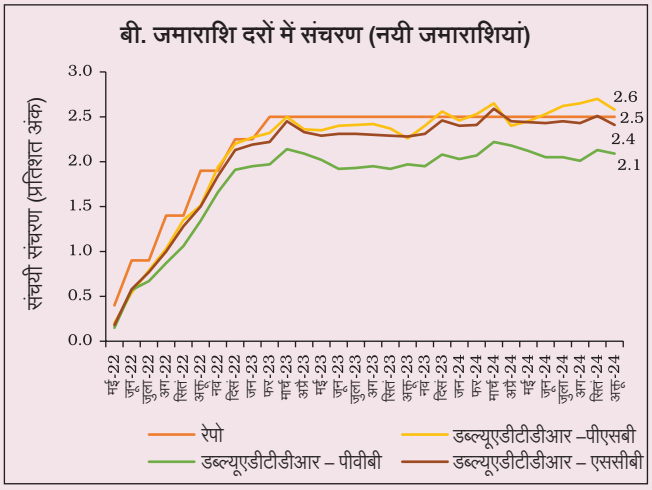

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

[6] 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 में यह 7.0 प्रतिशत थी।

बॉक्स IV.1: वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशि वृद्धि के निर्धारक तत्व

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशि वृद्धि के निर्धारकों का मूल्यांकन जून 2012-मार्च 2024 की अवधि के लिए ऑटोरिग्रैसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल (पेसरन और शिन, 1999) में किया गया है। साहित्य में आम सहमति के अनुसार (सालेह एम. और अन्य, 2023 और एस. ए. एस. अली और अन्य, 2019), प्रतिगमन परिणाम बताते हैं कि आय के संबंध में बैंक जमाराशि की दीर्घकालिक लोच [नॉमिनल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा अनुमानित] यूनिटी (1.1) के करीब है, यानी आय में एक प्रतिशत की वृद्धि, अन्य सभी चीजें समान रहने पर, दीर्घ अवधि में बैंक जमाराशि वृद्धि में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी है। उच्चतर जमाराशि ब्याज दरें (डबल्यूएडीटीडीआर) बैंक जमाराशि में बढ़ोत्तरी लाती है, लेकिन उनका प्रभाव दीर्घ अवधि में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। त्रुटि सुधार टर्म (ईसीएम) का ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक यह दर्शाता है कि किसी भी आघात के कारण जमाराशि और आय वृद्धि के बीच किसी भी असंतुलन का लगभग 17 प्रतिशत प्रत्येक तिमाही में सुधार किया जाता है (सारणी IV.1.1)।

संदर्भ:

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium*, 371–413. Cambridge: Cambridge University Press.

Saleh, M., *et al.* (2023). The Impact of Financial Determinants on Bank Deposits Using ARDL Model. *Journal of Statistics Applications & Probability 12(2)*: 441-452. DOI: https://doi.org/10.18576/jsap/120210.

S. A. S. Ali, *et al.* (2019). Determinants of Deposit of Commercial Banks in Sudan: an Empirical Investigation (1970-2012). *International Journal of Electronic Finance* (9), 230-255.

सारणी IV.1.1: समग्र जमाराशि के निर्धारक तत्व : एआरडीएल मॉडल

आश्रित चर: लॉग समग्र जमाराशि	
लॉन्ग रन	
लॉग जीवीए (-1)	1.083***
	(0.360)
डबल्यूएडीटीडीआर आउटस्टैंडिंग (-1)	0.0458
	(0.0603)
लॉग बीएसई (-1)	-0.0155
	(0.211)
ईसीएम	-0.166**
	(0.0801)
शॉर्ट रन	
डी.लॉग जीवीए	-0.0420
	(0.0678)
डी.डब्ल्यूएडीटीडीआर आउटस्टैंडिंग	0.0479*
	(0.0267)
डी.डब्ल्यूएडीटीडीआर आउटस्टैंडिंग (-1)	-0.0312
	(0.0273)
डी.लॉग बीएसई	0.0716
	(0.0427)
डी.लॉग बीएसई (-1)	-0.0916**
	(0.0403)
विमुद्रीकरण डमी	0.0244*
	(0.0121)
कोविड डमी	0.0299**
	(0.0117)
तिमाही 2 डमी	-0.00352
	(0.00787)
तिमाही 3 डमी	0.00396
	(0.00719)
तिमाही 4 डमी	0.00643
	(0.00792)
स्थिरांक	-0.0420
	(0.742)
प्रेक्षण	39
आर-स्क्वायर	0.468

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

IV.9 2023-24 में ऋण वृद्धि में महानगरीय क्षेत्र की प्रभुता, जैसा कि पहले हुआ था। ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों का योगदान मोटे तौर पर स्थिर रहा (चार्ट IV.5)।

चार्ट IV.4 : ऋण वृद्धि

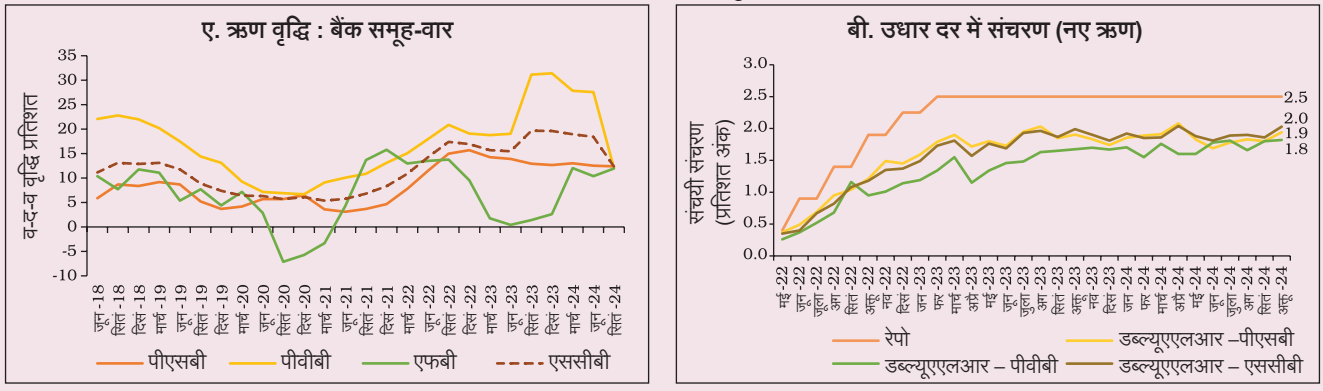

टिप्पणियां: 1. एससीबी डेटा में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
2. 21 जनवरी 2019 से एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 से उस बैंक को पीएसबी समूह से बाहर रखा गया है और पीवीबी समूह में शामिल किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 से सार्वजनिक और निजी बैंक-समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक-समूह योग पर आधारित हैं।
3. 27 नवंबर 2020 से एक निजी क्षेत्र के बैंक को एक विदेशी बैंक के साथ समामेलित किया गया। इसलिए, दिसंबर 2020 से निजी और विदेशी बैंक-समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक-समूह योग पर आधारित हैं।
4. क्रेडिट डेटा में अंतर-बैंक अग्रिम शामिल नहीं हैं।

स्रोत: जमा और ऋण का स्थानिक वितरण और आरबीआई।

चार्ट IV.5 ऋण वृद्धि में जनसंख्या समूहों का योगदान

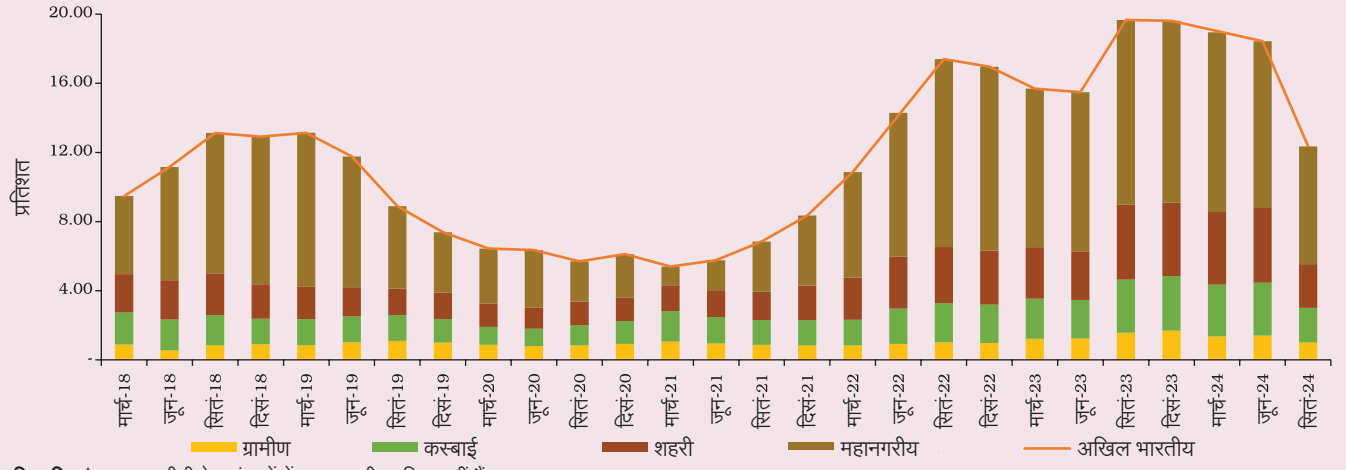

टिप्पणियां: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।

2. सभी केंद्रों को जनगणना 2011 में उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित चार जनसंख्या समूहों में वर्गीकृत किया गया है: ए) 'ग्रामीण' समूह में 10,000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। बी) 'अर्ध-शहरी' समूह में 10,000 और उससे अधिक लेकिन 1,00,000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सी) 'शहरी' समूह में 1,00,000 और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। डी) 'महानगरीय' समूह में दस लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी केंद्र शामिल हैं।

स्रोत: जमाराशि और ऋण का स्थानिक वितरण।

IV.10 मार्च 2024 के अंत तक, एससीबी के 83.1 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में थे। गैर-एसएलआर निवेशों में, डेट का हिस्सा लगभग 95 प्रतिशत था (सारणी IV.2)।

IV.11 जमाराशि वृद्धि में तेजी के कारण, ऋण की तुलना में जमाराशि वृद्धि का अंतराल 2023-24 के दौरान घटकर 3.4 प्रतिशत अंक (विलय प्रभाव को छोड़कर) हो गया (चार्ट IV.6ए)। वर्ष के दौरान निवेश की तुलना में जमाराशि वृद्धि का अंतराल भी कम हुआ (चार्ट IV.6बी)।

2.3 आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.12 आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता में बेमेल बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्वाभाविक है क्योंकि जमाराशि, जो उनके निधियों का प्राथमिक स्रोत है, की लघु से मध्यम अवधि की परिपक्वता होती है, जबकि उनके ऋणों की चुकौती की समय-

सारणी IV.2: एससीबी के निवेश
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल निवेश (ए+बी)	**38,33,030**	**40,54,445**	**18,81,756**	**23,11,707**	**6,55,830**	**8,01,533**	**58,244**	**74,508**	**64,28,860**	**72,42,193**
ए. एसएलआर निवेश (I+ II+III)	30,07,757	32,62,932	15,62,365	19,61,384	5,99,061	7,27,546	52,151	63,873	52,21,335	60,15,735
I. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	17,45,055	18,36,240	13,10,477	16,23,034	5,93,438	7,17,980	40,013	47,494	36,88,983	42,24,748
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	12,60,787	14,22,323	2,51,889	3,38,350	5,623	9,566	12,139	16,379	15,30,437	17,86,618
III. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	1,916	4,369	0	0	0	0	0	0	1,916	4,369
बी. एसएलआर से इतर निवेश (I+II)	8,25,273	7,91,513	3,19,390	3,50,323	56,769	73,987	6,093	10,634	12,07,525	12,26,458
I. ऋण प्रतिभूतियाँ	7,68,545	7,49,178	3,03,474	3,32,937	56,404	73,691	6,016	10,555	11,34,439	11,66,361
II. इक्विटी	56,728	42,335	15,916	17,386	365	297	77	79	73,087	60,097

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.6 : ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि अंतराल

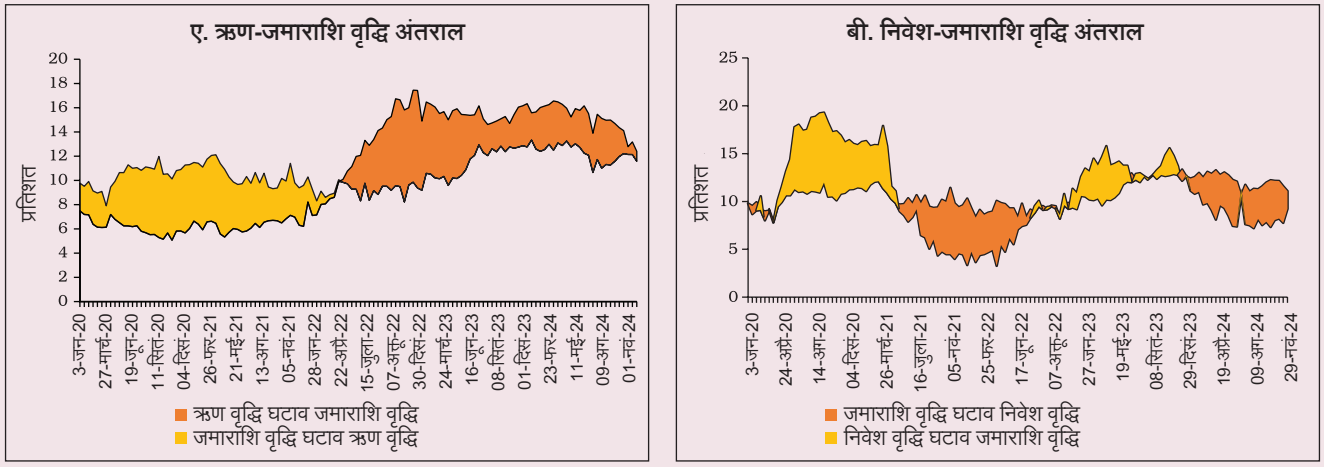

टिप्पणी : ऋण, जमाराशि और निवेश वृद्धि के आंकड़ों में विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत : आरबीआई।

सीमा आमतौर पर मध्यम अवधि तक विस्तारित होती है। 2023-24 के दौरान, अल्पावधि बकेट में परिपक्वता बेमेल एक साल पहले की तुलना में बढ़ गया, हालांकि यह महामारी-पूर्व स्तरों के सापेक्ष कम रहा। अन्य बकेट[7] में यह अंतराल धनात्मक रहा (चार्ट IV.7)। यह मुख्य रूप से बैंकों द्वारा जुटाई गई अल्पावधिक परिपक्वता जमाराशि में वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट IV.7 : परिपक्वता कोष्ठकवार आस्तियों और देयताओं के अंतराल

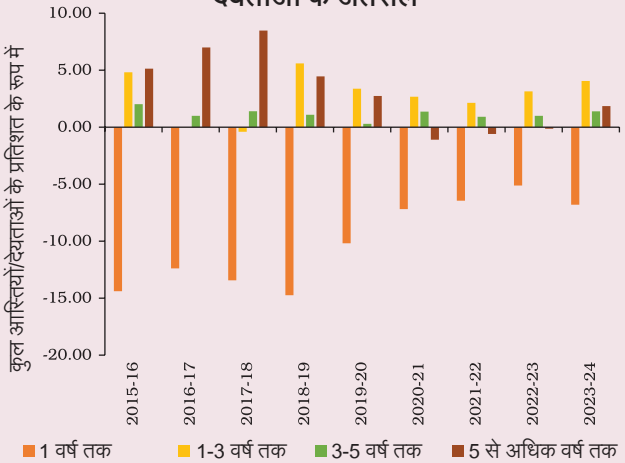

टिप्पणियां : 1. आस्तियों में ऋण और अग्रिम और निवेश शामिल हैं। देयताओं में जमाराशि एवं उधार शामिल हैं।
2. अंतराल की गणना आस्तियों से देयताओं को घटा कर की जाती है।
स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.13 एफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशि में अल्पकालिक जमाराशि की हिस्सेदारी बढ़ी। दूसरी ओर, एसएफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों के लिए अल्पकालिक उधार की हिस्सेदारी में गिरावट आई। एफबी के सभी परिचालन – जमाराशि, उधार लेना, उधार देना और निवेश अल्पकालिक बकेट में संकेंद्रित थे। पीएसबी के निवेश आम तौर पर दीर्घकालिक लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) में होते हैं, जबकि अन्य सभी बैंक समूह अल्पकालिक जोखिम को प्राथमिकता देते हैं (सारणी IV.3)।

2.4 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.14 वर्ष 2023-24 में, सभी प्रकार के अनिवासी जमाराशियों, अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)], अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया में वृद्धि ने भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में तेजी लाने में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी IV.2)। उनके 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में 23.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो एक साल पहले 13.1 प्रतिशत के संकुचन के शीर्ष पर थी, जो कि नोस्ट्रो जमाशेष और विदेशों

[7] अल्पावधि को एक वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, मध्यम अवधि को एक से पांच वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि दीर्घावधि को पांच वर्ष से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

सारणी IV.3 : चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएँ	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एसएफ़बी		पीबी		सभी एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियां												
ए) 1 वर्ष तक	36.4	38.3	33.0	39.2	65.7	62.2	42.2	49.0	15.5	22.6	36.7	39.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21.1	22.0	31.2	27.9	26.1	30.7	54.9	44.8	84.5	77.4	25.0	24.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.8	11.0	9.1	8.3	8.1	7.1	1.8	4.5	0.0	0.0	11.2	9.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	29.7	28.7	26.7	24.6	0.0	0.0	1.1	1.7	0.0	0.0	27.1	25.6
II. उधारियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	60.8	58.1	45.9	33.8	90.5	82.8	38.8	51.3	100.0	100.0	57.4	47.7
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.7	32.6	37.8	7.6	16.2	50.6	35.7	0.0	0.0	22.9	27.5
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	8.5	6.9	10.3	9.9	0.7	0.4	5.4	7.3	0.0	0.0	8.3	7.9
डी) 5 वर्ष से अधिक	14.0	18.3	11.2	18.6	1.2	0.6	5.2	5.8	0.0	0.0	11.3	16.9
III. ऋण और अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	28.3	28.0	28.4	27.3	56.2	59.5	36.5	37.7	100.0	100.0	29.4	28.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	34.3	36.5	36.7	34.6	23.9	23.8	36.0	36.0	0.0	0.0	34.9	35.3
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.1	12.1	12.5	12.5	10.0	8.2	10.5	10.1	0.0	0.0	13.3	12.1
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.3	23.4	22.4	25.6	9.9	8.5	17.1	16.3	0.0	0.0	22.4	23.7
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	26.0	22.4	55.3	58.6	86.4	83.9	61.6	68.6	99.5	99.2	41.3	41.4
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	14.6	16.3	19.1	17.2	8.2	10.4	27.0	25.9	0.1	0.4	15.3	16.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.9	11.9	7.1	6.1	1.3	1.6	5.5	4.0	0.0	0.1	9.9	8.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	46.4	49.4	18.5	18.1	4.2	4.1	5.9	1.5	0.4	0.3	33.4	33.8

टिप्पणी : आंकड़े तुलन पत्र के प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता बकेट की हिस्सेदारी दर्शाते हैं।
स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

में जमा रखे जाने के साथ-साथ अनिवासियों को दिए जाने वाले ऋणों में कमी के कारण हुई थी (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

चार्ट IV.8: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

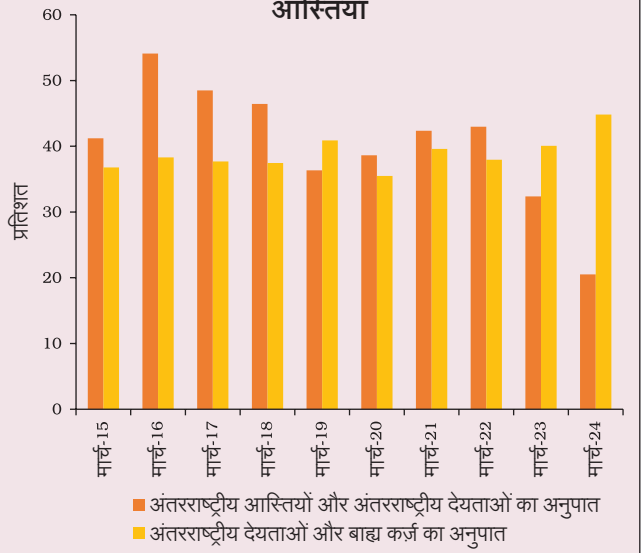

स्रोत : डीबीआईई और बैंकों के वार्षिक लेखा।

नतीजतन, भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में देयताओं का अनुपात 2023-24 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष घटा (चार्ट IV.8)।

IV.15 वर्ष 2023-24 में अमेरिका और यूएई को छोड़कर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.4); इसके विपरीत, पिछले वर्ष में, सिंगापुर को छोड़कर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में कमी आई थी। मार्च 2024 के अंत में, भारतीय बैंकों के दावे अन्य क्षेत्राधिकारों में अपने समकक्षों से हटकर गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र की ओर चले गए (चार्ट IV.9ए)। कम परिपक्वता अवधि वाले दावों का अनुपात बढ़ा और प्रभावशाली कोटि का बना रहा (परिशिष्ट सारणी IV.5 और चार्ट IV.9बी)।

चार्ट IV.9 : भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे
(मार्च के अंत में)

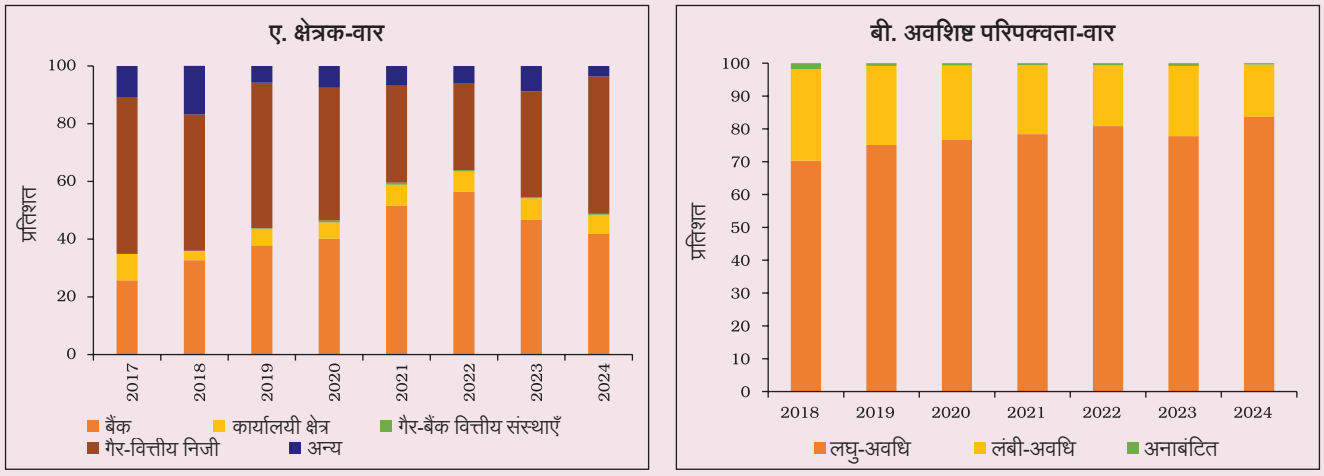

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा और डीबीआईई।

2.5 तुलन पत्र से इतर परिचालन

IV.16 मार्च 2024 के अंत में एससीबी की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि धीमी हो गई, जिसका नेतृत्व वायदा विनिमय संविदा (फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स) ने किया (चार्ट IV.10ए और परिशिष्ट सारणी IV.6)। तुलन पत्र के आकार के अनुपात के रूप में, एससीबी का तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर मार्च 2023 के अंत में 144.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 138.6 प्रतिशत हो गया। बैंकिंग क्षेत्र की आकस्मिक देयताओं में पीवीबी की हिस्सेदारी मार्च 2014 के अंत में 20.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 32.9 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में पीएसबी की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से घटकर 13.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.10बी)।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.17 वर्ष 2023-24 में लगातार छठे वर्ष बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ। वर्ष 2023-24 में पीएसबी और पीवीबी दोनों ने आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में वृद्धि प्रदर्शित की (चार्ट IV.11)।

चार्ट IV.10 : बैंकों की तुलन पत्र से इतर देयताएं

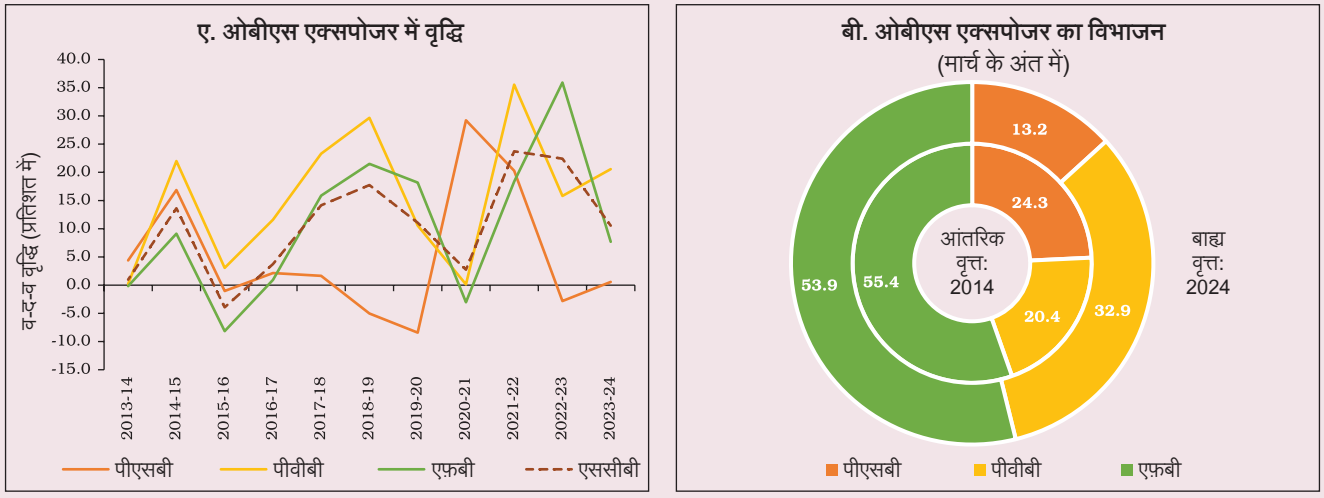

स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.11 : लाभप्रदता अनुपात
(मार्च अंत में)

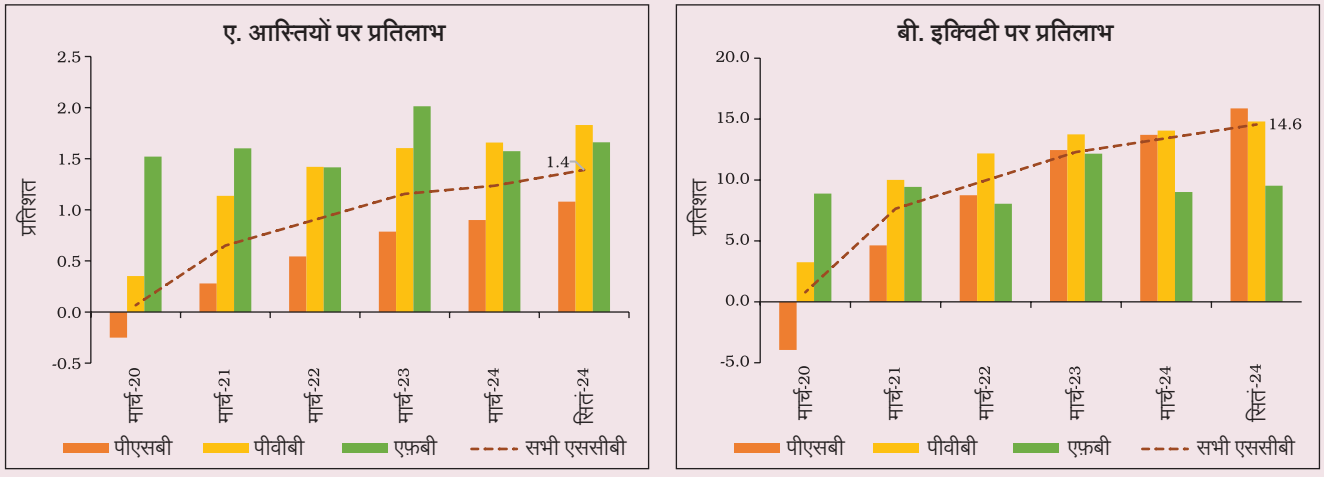

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलु परिचालन), आरबीआई।

वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एससीबी की लाभप्रदता में वृद्धि जारी रही, जिसमें आरओए 1.4 प्रतिशत और आरओई 14.6 प्रतिशत रहा।

IV.18 वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों ने उच्च ब्याज दरों पर उधार लेना शुरु किया और ऋण की तुलना में जमाराशि वृद्धि अंतराल को पाटने के लिए अपनी जमाराशि दरों में वृद्धि की। नतीजतन, उनके ब्याज व्यय की गति उनकी ब्याज आय से अधिक हो गई जिसके परिणामस्वरूप परिचालन और निवल लाभ वृद्धि, दोनों में धीमापन आया (सारणी IV.4 और चार्ट IV.12ए)।

IV.19 ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय का अनुपात 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 57.4 प्रतिशत हो गया। औसत निवल मार्जिन ब्याज (एनआईएम) पीवीबी के लिए सबसे अधिक था, उसके बाद एफबी और पीएसबी थे। एफबी का एनआईएम अत्यधिक विस्तारित है, उसके बाद पीवीबी और पीएसबी (चार्ट IV.12बी) हैं।

चार्ट IV.12: निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन

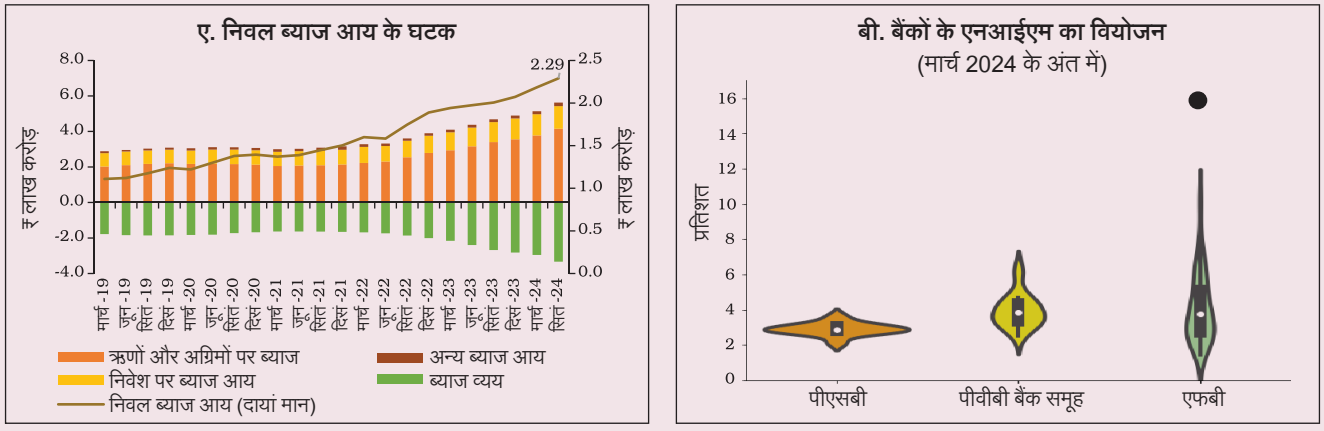

टिप्पणी : वायलिन चार्ट मार्च 2024 के अंत में बैंक-वार एनआईएम का उपयोग करके बनाया गया है। चार्ट में सफ़ेद बिंदु माध्यिका को दर्शाता है, बीच में काली पट्टी का आधार प्रथम चतुर्थक को दर्शाता है, जबकि शीर्ष तृतीय चतुर्थक को दर्शाता है। वायलिन प्लॉट के चौड़े हिस्से वितरण की उच्च आवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि पतले हिस्से कम आवृत्ति को दर्शाते हैं। काला बिंदु बहिस्थ (आउटलायर) एफबी को दर्शाता है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां, आरबीआई और बैंकों के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय के रुझान

(राशि ₹ करोड़ में)

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आय	9,71,421 (16.8)	12,12,665 (24.8)	6,90,504 (20.7)	9,41,864 (36.4)	1,08,132 (36.0)	1,29,870 (20.1)	33,806 (34.6)	45,449 (34.4)	5,965 (20.5)	7,102 (19.0)	18,09,829 (19.6)	23,36,949 (29.1)
ए) ब्याज आय	8,51,078 (20.0)	10,66,243 (25.3)	5,82,278 (23.6)	7,96,569 (36.8)	83,315 (26.5)	1,06,032 (27.3)	29,806 (34.7)	39,646 (33.0)	860 (92.7)	1,416 (64.6)	15,47,337 (22.0)	20,09,907 (29.9)
बी) अन्य आय	1,20,343 (-2.0)	1,46,422 (21.7)	1,08,226 (6.8)	1,45,295 (34.3)	24,817 (81.9)	23,838 (-3.9)	4,000 (34.0)	5,803 (45.1)	5,105 (13.3)	5,686 (11.4)	2,62,492 (7.0)	3,27,043 (24.6)
2. व्यय	8,66,772 (13.3)	10,71,463 (23.6)	5,66,369 (19.0)	7,66,567 (35.3)	77,987 (27.6)	1,02,984 (32.1)	29,644 (22.8)	39,230 (32.3)	5,844 (15.9)	7,103 (21.5)	15,46,615 (16.1)	19,87,346 (28.5)
ए) खर्च किया गया ब्याज	4,87,690 (18.6)	6,58,611 (35.0)	2,75,391 (22.8)	4,29,732 (56.0)	31,678 (47.5)	46,996 (48.4)	12,140 (27.6)	17,474 (43.9)	246 (57.5)	353 (43.8)	8,07,144 (21.1)	11,53,167 (42.9)
बी) परिचालन व्यय	2,44,064 (10.9)	2,95,090 (20.9)	2,02,563 (29.3)	2,39,146 (18.1)	27,958 (12.0)	34,789 (24.4)	13,150 (34.0)	17,189 (30.7)	5,579 (14.3)	6,634 (18.9)	4,93,314 (18.5)	5,92,848 (20.2)
जिनमें से : वेतन बिल	1,44,690 (9.0)	1,84,025 (27.2)	70,605 (20.0)	90,284 (27.9)	10,065 (9.6)	10,460 (3.9)	6,705 (26.4)	8,504 (26.8)	914 (15.9)	1,215 (32.9)	2,32,978 (12.6)	2,94,488 (26.4)
c) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,35,018 (0.7)	1,17,761 (-12.8)	88,415 (-7.1)	97,688 (10.5)	18,351 (25.3)	21,200 (15.5)	4,354 (-9.4)	4,567 (4.9)	20 (556.9)	116 (488.4)	2,46,158 (-1.0)	2,41,332 (-2.0)
3. परिचालन लाभ	2,39,667 (19.5)	2,58,964 (8.1)	2,12,551 (11.0)	2,72,986 (28.4)	48,496 (46.8)	48,085 (-0.8)	8,516 (47.3)	10,786 (26.6)	141 (-263.0)	114 (-18.9)	5,09,371 (18.2)	5,90,935 (16.0)
4. निवल लाभ	1,04,649 (57.3)	1,41,202 (34.9)	1,24,136 (29.0)	1,75,297 (41.2)	30,145 (64.0)	26,886 (-10.8)	4,162 (327.6)	6,219 (49.4)	121 (-235.6)	-1 (-101.0)	2,63,214 (44.6)	3,49,603 (32.8)
5. निवल ब्याज आय (एनआईआई)	3,63,388 (22.0)	4,07,632 (12.2)	3,06,888 (24.4)	3,66,836 (19.5)	51,637 (16.4)	59,036 (14.3)	17,666 (40.1)	22,172 (25.5)	615 (111.7)	1,063 (72.9)	7,40,193 (23.0)	8,56,740 (15.7)
6. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.7	2.8	3.9	3.9	3.5	3.6	7.5	7.4	3.0	4.5	3.2	3.3

टिप्पणी : 1. एनआईएम को औसत आस्तियों के प्रतिशत में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नताओं को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पीसीआर (बट्टे खाते में डालने के लिए समायोजित किए बिना) वर्ष-दर-वर्ष 210 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 76.2 प्रतिशत पर पहुंच गया जो मुख्य रूप से कम गिरावट को दर्शाता है। सितंबर 2024 के अंत में यह और सुधरकर 76.7 प्रतिशत हो गया जिसका श्रेय मुख्य रूप से पीएसबी को जाता है (चार्ट IV.13)।

IV.21 निधियों की लागत में 104 बीपीएस की वृद्धि और आस्तियों पर प्रतिफल में 89 बीपीएस की वृद्धि ने 2023-24 के दौरान एससीबी के स्प्रेड को कम कर दिया। एसएफबी में

चार्ट IV.13 : प्रावधान व्याप्ति अनुपात

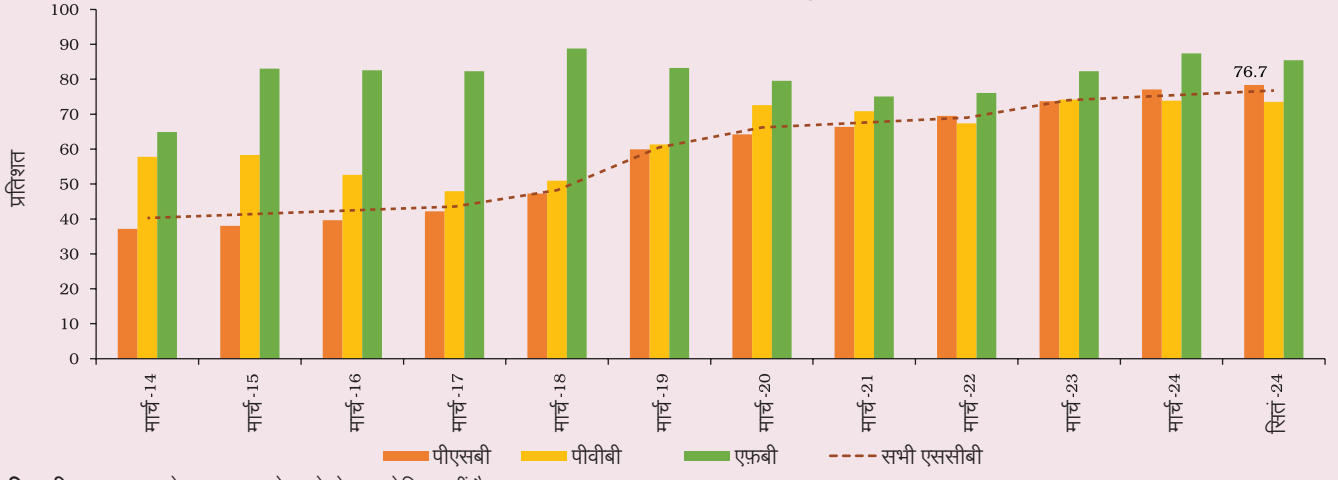

टिप्पणी: प्रावधान कवरेज अनुपात बट्टे खाते से समायोजित नहीं है।
स्रोत: परोक्ष विवरणियां, (घरेलु परिचालन) आरबीआई।

सारणी IV.5: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	वर्ष	जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिलाभ	निवेशों पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड (कॉलम 8 - कॉलम 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	2022-23	3.9	6.2	4.1	7.5	6.5	7.1	3.1
	2023-24	4.8	7.3	5.0	8.4	6.9	7.9	2.9
पीवीबी	2022-23	3.8	6.4	4.1	9.2	6.3	8.4	4.3
	2023-24	4.8	9.2	5.4	10.4	6.8	9.5	4.1
एफ़बी	2022-23	2.9	4.0	3.1	8.2	5.8	6.9	3.8
	2023-24	3.8	5.6	4.1	8.7	6.8	7.6	3.5
एसएफ़बी	2022-23	5.9	7.3	6.1	16.5	6.7	14.2	8.0
	2023-24	6.8	8.2	7.0	17.0	6.9	14.5	7.5
पीबी	2022-23	2.1	7.8	2.4	6.0	5.6	5.6	3.3
	2023-24	2.0	11.2	2.4	10.0	7.6	7.6	5.2
सभी एससीबी	2022-23	3.8	6.1	4.0	8.2	6.3	7.6	3.6
	2023-24	4.8	8.1	5.1	9.3	6.9	8.5	3.4

टिप्पणियां: 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत।
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज – जमाराशि पर ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्षों की उधारियों का औसत।
3. निधियों की लागत = खर्च किया गया ब्याज / (वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत + उधारियाँ)।
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत।
5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के निवेशों का औसत।
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत + निवेश)।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र से की गई गणना।

स्प्रेड सबसे व्यापक था जो उनके अग्रिमों पर अपेक्षाकृत उच्चतर ब्याज दरों को दर्शाता है (सारणी IV.5)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.22 भारत में बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकता 9 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 11.5 प्रतिशत) निर्धारित की गई है और टियर 1 पूंजी आवश्यकता 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है जो दोनों बेसल III अपेक्षाओं से एक प्रतिशत अधिक है। मार्च 2024 के अंत में, सभी बैंक समूह अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, हालांकि एससीबी का सीआरएआर 30 बीपीएस की गिरावट के साथ 16.9 प्रतिशत हो गया, जबकि टियर1 पूंजी 14.8 प्रतिशत पर थी (सारणी IV.6)। सीआरएआर में गिरावट जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के कारण हुई जो उनके पूंजी निधियों में वृद्धि से अधिक थी। पर्यवेक्षी आँकड़ों से संकेत मिलता है कि सितंबर 2024 के अंत में एससीबी का सीआरएआर 16.8 प्रतिशत था।

IV.23 घटक बैंकों के बीच सीआरएआर और सीईटी1 का विस्तार पीवीबी के लिए पीएसबी की तुलना में अधिक था (चार्ट IV.14ए और बी)। पीवीबी के लिए सीआरएआर और सीईटी1 दोनों के माध्य और माध्यिका पीएसबी की तुलना में अधिक था।

सारणी IV.6: एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पूंजीगत निधियां	**10,16,789**	**11,74,245**	**10,20,953**	**12,83,455**	**2,43,096**	**2,70,646**	**23,15,358**	**27,69,950**
i) टीयर 1 पूंजी	8,47,783	9,94,510	9,11,271	11,55,051	2,20,746	2,43,842	20,10,443	24,30,733
ii) टीयर 2 पूंजी	1,69,006	1,79,735	1,09,681	1,28,404	22,350	26,804	3,04,915	3,39,217
2. जोखिम भारित आस्तियां	**65,48,771**	**75,59,396**	**54,85,172**	**72,14,513**	**12,50,775**	**14,18,639**	**1,34,38,317**	**1,63,84,879**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**15.5**	**15.5**	**18.6**	**17.8**	**19.4**	**19.1**	**17.2**	**16.9**
जिनमें से : टीयर 1	12.9	13.2	16.6	16.0	17.6	17.2	15.0	14.8
टीयर 2	2.6	2.4	2.0	1.8	1.8	1.9	2.3	2.1

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट IV.14: बैंक समूहवार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात
(मार्च के अंत तक)

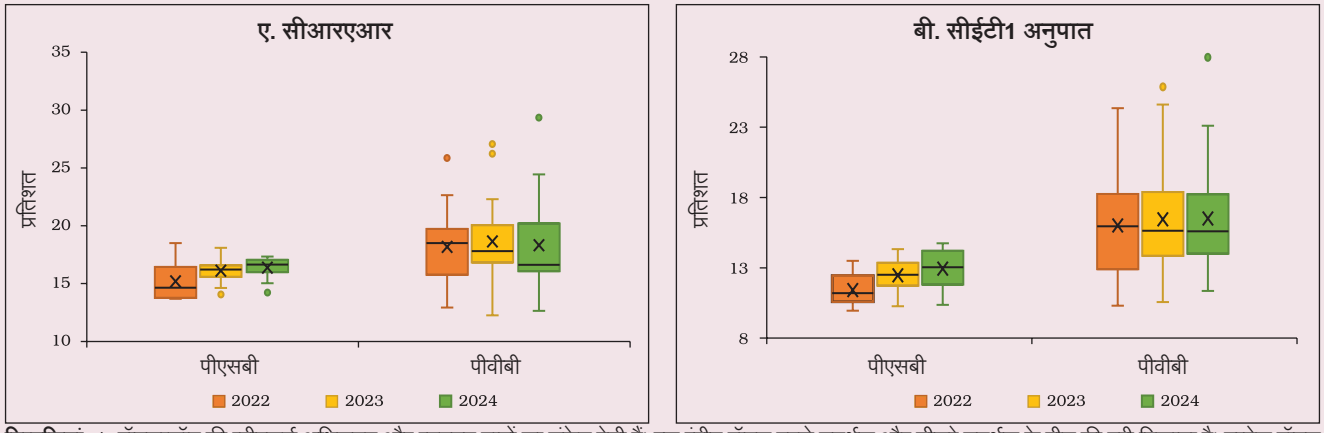

टिप्पणियां: 1. बॉक्सप्लॉट की व्हीस्कर्स अधिकतम और न्यूनतम मानों का संकेत देती हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका को दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य को दर्शाता है।
स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

IV.24 सभी समूह और आकार के बैंकों ने लगातार विनियामक न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊपर सीआरएआर बनाए रखा है (चार्ट IV.15)। सीसीबी को भारतीय बैंकों पर 2016 से कई चरणों में लागू किया गया था। अधिशेष सीआरएआर, जो सीसीबी सहित तत्कालीन लागू सीआरएआर से अधिशेष पर आकलित होता है, कई कारकों से प्रभावित होता है (बॉक्स IV.2)।

चार्ट IV.15 : अधिशेष सीआरएआर

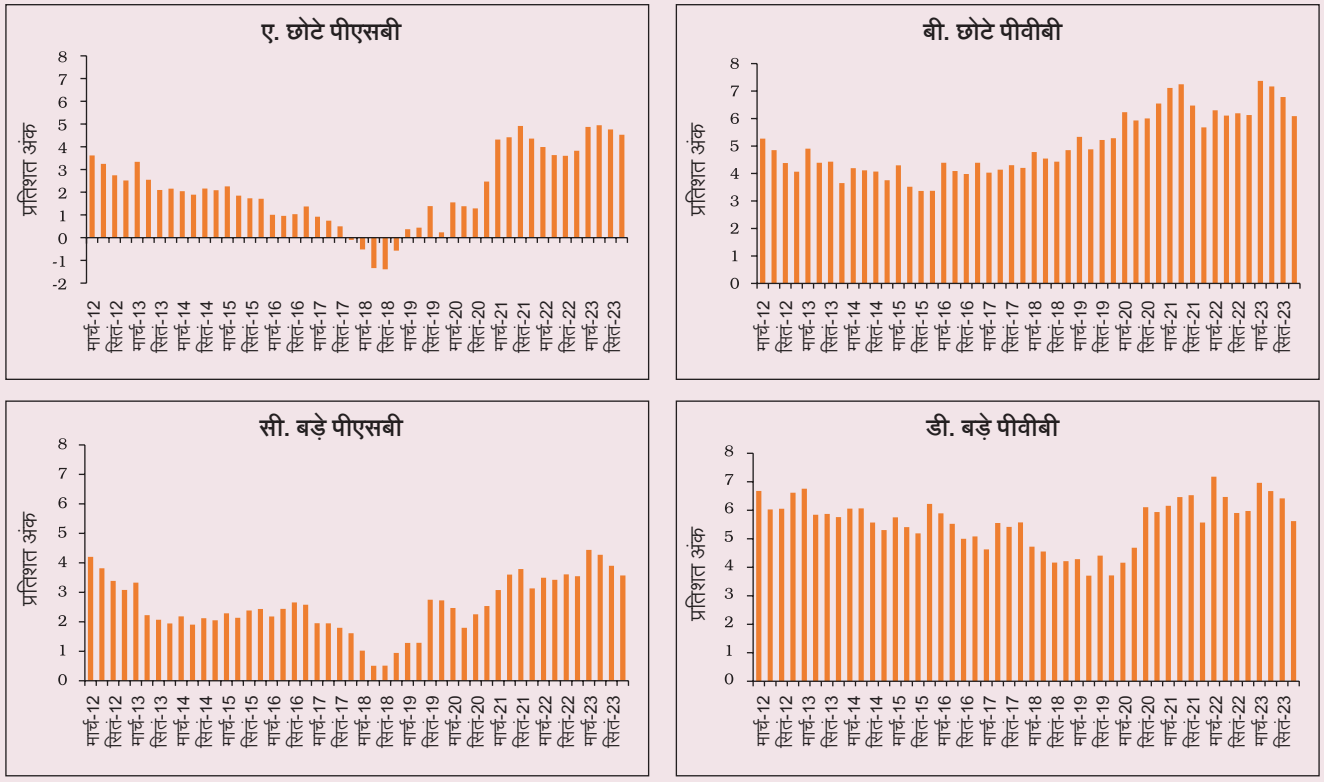

टिप्पणी: किसी भी तिमाही के लिए, समूह औसत से नीचे (ऊपर) आस्ति आकार वाला बैंक छोटा (बड़ा) माना जाता है।
स्रोत: आरबीआई

बॉक्स IV.2: बैंक अधिशेष सीआरएआर क्यों रखते हैं?

बैंक अप्रत्याशित घाटे एवं आर्थिक मंदी का सामना करने, और अपनी बाज़ार प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अधिशेष सीआरएआर को बफर के रूप में रखते हैं (लिंडक्विस्ट, 2004)। विनियामकीय आवश्यकताओं से ऊपर के सीआरएआर, बैंकों के लिए विकल्पगत हानि हो सकती है क्योंकि अधिशेष पूंजी को उच्चतर-प्रतिफल देने वाली वाली आस्तियों में निवेश किया जा सकता है, जिसमें ऋण देना भी शामिल है (कश्यप, राजन और स्टीन, 2002)।

अधिशेष सीआरएआर के संभावित चालकों का अनुमान मार्च 2012 से दिसंबर 2023 तक 33 पीएसबी और पीवीबी के पर्यवेक्षी तिमाही पैनल डेटा का उपयोग करके फिक्स्ड इफ़ेक्ट रिग्रेशन मॉडल से लगाया जाता है।

परिणामों से संकेत मिलता है कि आरओए या एनआईएम जैसे लाभप्रदता संकेतक अधिशेष सीआरएआर पर धनात्मक प्रभाव डालते है. (सारणी IV.2.1)। इसके विपरीत, पिछले सकल जीएनपीए अनुपात या निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात द्वारा मापा गया बैंकों का पूर्व-पश्चात ऋण जोखिम, अधिशेष सीआरएआर को कम करता है क्योंकि कमजोर आस्ति गुणवत्ता वाले बैंक उच्च प्रावधानों का अनुमान लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, एक बड़ा ऋण पोर्टफोलियो (ऋण से आस्ति अनुपात द्वारा मापा जाता है) या उच्चतर ऋण वृद्धि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष सीआरएआर के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। कुल आस्तियों के लॉग द्वारा मापा गया बैंक का आकार, अधिशेष सीआरएआर से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है - बड़े बैंकों को पोर्टफोलियो विविधीकरण, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच का लाभ हो सकता है (बर्जर और बाउमन, 2009)।

अधिशेष पूंजी रखने का निर्णय समकक्ष के व्यवहार से भी प्रभावित हो सकता है (अंगोरा, डिस्टिंगुइन और रुगेमिंटवारी, 2009)। भारतीय परिपेक्ष्य में, एक समान श्रेणी (पीएसबी और पीवीबी के आकार-वार समूह) के बैंकों द्वारा धारित औसत अधिशेष पूंजी, बैंक के स्वयं के अधिशेष सीआरएआर के साथ एक महत्वपूर्ण और धनात्मक संबंध दर्शाता है। भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर), जो अधिशेष पूंजी रखने की विकल्पगत हानि का प्रतिनिधित्व करता है, वह अधिशेष पूंजी होल्डिंग को कम करती है। अधिशेष सीआरएआर भी चक्रीय प्रतीत होता है, जैसा कि जीडीपी वृद्धि के साथ इसके धनात्मक और महत्वपूर्ण संबंध से स्पष्ट है।

निष्कर्षतः बैंकों द्वारा अधिशेष सीआरएआर बनाए रखना, समष्टि-आर्थिक स्थितियों के अलावा उनकी अपनी वित्तीय स्थितियों तथा समकक्षों के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है।

सारणी IV.2.1: प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर: अधिशेष सीआरएआर			
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
लैग (आरओए)	0.865***		1.115***
	(0.0673)		(0.0754)
लैग (एनआईएम)		1.091***	
		(0.0859)	
लैग (एनएनपीए अनुपात)	-0.0783***		
	(0.0262)		
लैग (जीएनपीए अनुपात)		-0.197***	-0.0935***
		(0.0140)	(0.0162)
लैग (ऋण से आस्तियां)	-0.0339***		-0.0274**
	(0.0102)		(0.0118)
लैग (ऋण वृद्धि)		0.00347	
		(0.00475)	
समूह अधिशेष सीआरएआर	0.649***		
	(0.0474)		
लॉग (कुल आस्तियां)		-0.676***	-0.315*
		(0.160)	(0.165)
डब्ल्यूएसीआर	-0.116***	-0.439***	-0.411***
	(0.0305)	(0.0397)	(0.0405)
जीडीपी वृद्धि	0.00120	0.0334***	0.0243***
	(0.00792)	(0.00848)	(0.00845)
स्थिरांक	3.892***	12.21***	11.86***
	(0.689)	(2.084)	(2.027)
प्रेक्षण	1,518	1,509	1,518
स्थिर प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
आर-स्क्वायर	0.394	0.267	0.289
बैंकों की संख्या	33	33	33

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक स्तर पर एकत्रित मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. *** , ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

Angora, A., Distinguin, I., and Rugemintwari, C. (2009). Excess Capital of European Banks: Does Bank Heterogeneity Matter? Working paper. University of Limoges.

Berger, A. N., and Bouwman, C. H. (2009). Bank Liquidity Creation. *The Review of Financial Studies*, 22(9), 3779-3837.

Kashyap, A. K., Rajan, R. G., and Stein, J. C. (2002). Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-taking. *Journal of Finance*, 57(1), 33-73.

Lindquist, K.-G. (2004). Banks' Buffer Capital: How Important is Risk. *Journal of International Money and Finance*, 23(3), 493-513.

IV.25 बैंकों द्वारा कर्ज़ के निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और इक्विटी के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में 2023-24 के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई। पीएसबी द्वारा जुटाई गई कुल राशि में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 38.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.7)।

सारणी IV.7: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्तूबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	34	70,719	27	70,260	26	97,380	17	90,811
पीवीबी	16	40,034	14	52,903	14	33,426	6	14,519
एफबी	0	0	2	224	0	0	0	0
कुल	**50**	**1,10,753**	**43**	**1,23,387**	**40**	**1,30,806**	**23**	**1,05,330**

टिप्पणियां: 1. इसमें कर्ज़ का निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमानी आबंटन शामिल हैं।
2. वर्ष 2024-25 के आँकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : सेबी, बीएसई और एनएसई।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.26 लीवरेज अनुपात एक गैर-जोखिम आधारित बैकस्टॉप उपाय है जो बेसल III जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे का पूरक है। लीवरेज अनुपात (एलआर) - कुल जोखिमों के लिए टियर1 पूंजी का अनुपात – वर्ष 2023-24 के दौरान सिवाय एफबी के सभी बैंक समूहों में बेहतर हुआ (सारणी IV.8)।

IV.27 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - जिसे अल्पावधि में बैंकों को चलनिधि दबावों का सामना करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - के लिए बैंकों को दबावग्रस्त स्थितियों के 30 दिनों के निवल व्यय को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मार्च 2024 के अंत में, वर्ष के दौरान मामूली कमी के बावजूद, एलसीआर 130.3 प्रतिशत था जो आवश्यक 100 प्रतिशत से अधिक था। (सारणी IV.8)

IV.28 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) – आवश्यक स्थिर निधीयन की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन का अनुपात - बैंकों की अल्पकालिक थोक निधीयन पर अत्यधिक निर्भरता को सीमित करता है और सभी तुलन पत्र और उससे इतर मदों में निधीयन जोखिम के बेहतर आकलन को प्रोत्साहित करता है, जिससे निधीयन स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, भारत में बैंकों को न्यूनतम एनएसएफआर बनाए रखने की आवश्यकता 100 प्रतिशत है। मार्च 2024 के अंत तक, सभी बैंक समूहों ने इस लक्ष्य को पूरा किया (सारणी IV.9)।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.29 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार, जिसे उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपातों द्वारा मापा जाता है, 2018-19 में शुरू हुआ। एससीबी के जीएनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 15.9 प्रतिशत की कमी आई और 31 मार्च 2024 तक यह ₹4.8 लाख करोड़ रह गया। जीएनपीए अनुपात मार्च

सारणी IV.8: लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(प्रतिशत)

	लीवरेज अनुपात				चलनिधि व्याप्ति अनुपात			
	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-24	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	सितं-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	5.1	5.5	6.0	6.0	155.8	153.5	129.3	127.4
पीवीबी	9.7	9.6	9.7	10.0	127.7	127.9	127.1	126.1
एफबी	11.0	11.0	10.8	10.6	171.0	154.6	145.0	142.6
सभी एससीबी	**7.2**	**7.4**	**7.8**	**7.9**	**147.1**	**144.6**	**130.3**	**128.6**

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.9: निवल स्थिर निधीयन अनुपात
(मार्च 2024 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	उपलब्ध स्थिर निधीयन	आवश्यक स्थिर निधीयन	एनएसएफआर (प्रतिशत)
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1,11,95,611	88,65,493	126.3
निजी क्षेत्र के बैंक	77,28,087	60,47,820	127.8
विदेशी बैंक	6,78,655	5,34,056	127.1
लघु वित्त बैंक	2,04,965	1,63,860	125.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**1,98,07,318**	**1,56,11,229**	**126.9**

स्रोत : परोक्ष विवरणियां, (वैश्विक परिचालन) आरबीआई।

2024[8] के अंत में घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो 13 वर्षों में सबसे कम है, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 3.9 प्रतिशत था। बेहतर वसूली और उन्नयन के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान जीएनपीए में लगभग 44.4 प्रतिशत की कमी आयी।

IV.30 मार्च 2024 के अंत में, निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) भी घटकर दशक के निचले स्तर 0.62 प्रतिशत पर आ गईं जो कि मजबूत प्रावधान बफर के कारण संभव हुआ (सारणी IV.10)। सितंबर 2024 के अंत में एनएनपीए अनुपात सुधर कर 0.57 प्रतिशत हो गया।

IV.31 गिरावट अनुपात, जो वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापता है, 2023-24 के दौरान बेहतर हुआ (चार्ट IV.16ए)। लगातार तीसरे वर्ष, पीवीबी का गिरावट अनुपात पीएसबी की तुलना में अधिक रहा क्योंकि पीवीबी के एनपीए में नई वृद्धि अधिक रही (चार्ट IV.16बी)।

IV.32 आस्ति गुणवत्ता में इन लाभों को दर्शाते हुए, मार्च 2024 के अंत में सभी बैंक समूहों में कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात एक वर्ष पहले की तुलना में बढ़ गया। अमानक अग्रिमों (जिसमें अवमानक, संदिग्ध और घाटे वाले अग्रिम शामिल हैं) की हिस्सेदारी में कमी संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण हुआ (सारणी IV.11)।

IV.33 एससीबी के कुल अग्रिमों में बड़े उधार खातों[9] की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के अंत में 46.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 43.9 प्रतिशत रह गई। विशेष उल्लेख खाता-1 (एसएमए-1)[10] अनुपात में, कुल मिलाकर पीवीबी और

चार्ट IV.16: जीएनपीए में कमी

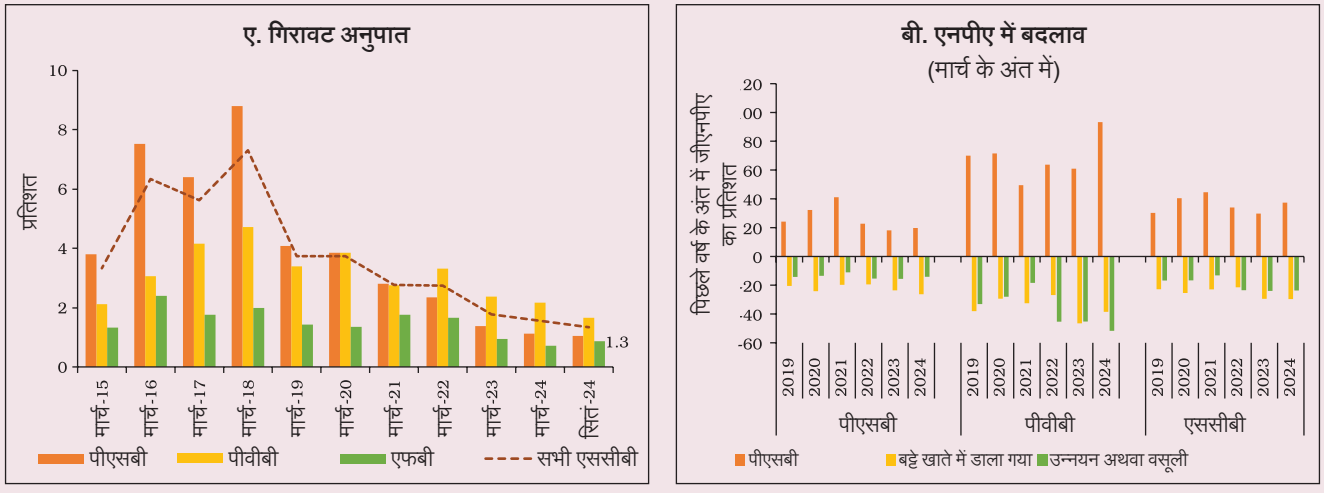

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन) और बैंकों के वार्षिक लेखा।

[8] नवीनतम उपलब्ध पर्यवेक्षी आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2024 के अंत तक जीएनपीए अनुपात में और सुधार होकर यह 2.5 प्रतिशत हो जाएगा।
[9] बड़े उधार खाते से तात्पर्य उन खातों से है जिनमें कुल ऋण 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
[10] एसएमए-1 उन खातों को इंगित करता है जिनमें ब्याज या मूलधन का भुगतान 31-60 दिनों के बीच बकाया है।

सारणी IV.10 : अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव - बैंक-समूह वार

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी	पीवीबी	एफ़बी	एसएफ़बी#	सभी एससीबी
1	2	3	4	5	6
कुल एनपीए					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	4,28,197	1,25,214	9,526	8,608	5,71,546
2023-24 के लिए प्रारंभिक शेष	4,28,197	1,25,214	9,526	8,608	5,71,546
वर्ष 2023-24 के दौरान योग	84,435	1,16,801	5,199	7,152	2,13,587
वर्ष 2023-24 के दौरान कमी (i+ii+iii)	1,73,090	1,12,852	8,202	10,170	3,04,314
i. वसूली	43,018	25,794	3,513	2,348	74,673
ii. उन्नयन	17,558	38,856	1,961	2,159	60,535
iii. बट्टे खाते में	1,12,515	48,202	2,728	5,662	1,69,106
2023-24 के लिए अंतिम शेष	**3,39,541**	**1,29,164**	**6,523**	**5,590**	**4,80,818**
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	5.0	2.3	1.9	4.7	3.9
2023-24 के लिए अंतिम शेष	3.5	1.9	1.2	2.4	2.7
निवल एनपीए					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	1,02,532	29,510	1,656	1,622	1,35,320
2023-24 के लिए अंतिम शेष	72,544	31,594	799	1,796	1,06,732
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2022-23	1.2	0.5	0.3	0.9	0.9
2023-24	0.8	0.5	0.1	0.8	0.6

टिप्पणियां: 1. #: डेटा में अनुसूचित एसएफबी शामिल हैं।
2. *: संबंधित बैंकों के वार्षिक खातों से कुल एनपीए और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की गई है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

पीएसबी दोनों में और साथ ही बड़े उधार खातों में, गिरावट आई (चार्ट IV.17)।

IV.34 महामारी के बाद शुरू की गई समाधान योजनाओं (आरएसए 1.0 और आरएसए 2.0) के कारण 2021-22 में पुनर्रचित खातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसके बाद, पुनर्रचित मानक अग्रिम (आरएसए) की समय-सीमा समाप्त होने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हुए, पीएसबी और पीवीबी दोनों में पुनर्रचित खातों की संख्या में कमी आई। सकल ऋणों और अग्रिमों में पुनर्रचित मानक अग्रिमों (आरएसए) की हिस्सेदारी समग्र रूप से और साथ ही बड़े उधार खातों के लिए कम हो गई। सकल ऋणों और अग्रिमों में आरएसए की हिस्सेदारी पीएसबी की तुलना में पीवीबी के लिए कम रही (चार्ट IV.18)।

सारणी IV.11: बैंक समूह-वार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएसबी	2023	72,86,427	94.8	62,444	0.8	2,28,806	3.0	1,10,054	1.4
	2024	84,24,922	96.3	58,576	0.7	1,78,483	2.0	83,681	1.0
पीवीबी	2023	51,99,732	97.8	34,288	0.6	52,469	1.0	29,033	0.5
	2024	66,96,942	98.2	44,199	0.6	52,944	0.8	26,397	0.4
एफ़बी	2023	4,89,212	98.1	1,697	0.3	6,648	1.3	1,182	0.2
	2024	5,39,598	98.8	1,344	0.2	4,228	0.8	950	0.2
एसएफ़बी**	2023	1,76,199	95.3	3,035	1.6	2,491	1.3	3,082	1.7
	2024	2,24,245	97.6	4,005	1.7	1,514	0.7	71	0.0
सभी एससीबी	2023	1,31,51,571	96.1	1,01,465	0.7	2,90,414	2.1	1,43,351	1.0
	2024	1,58,85,707	97.2	1,08,125	0.7	2,37,169	1.5	1,11,099	0.7

टिप्पणियां : 1. *: कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
2. **: अनुसूचित एसएफबी को संदर्भित करता है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.17 : समग्र दबाव की तुलना में बड़े उधार खातों में दबाव
(मार्च के अंत में)

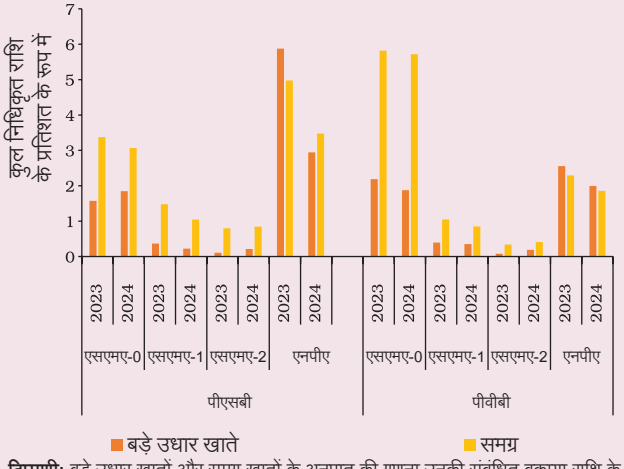

टिप्पणी: बड़े उधार खातों और समग्र खातों के अनुपात की गणना उनकी संबंधित बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
स्रोत: बड़े ऋण से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन) आरबीआई।

चार्ट IV.18: पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात

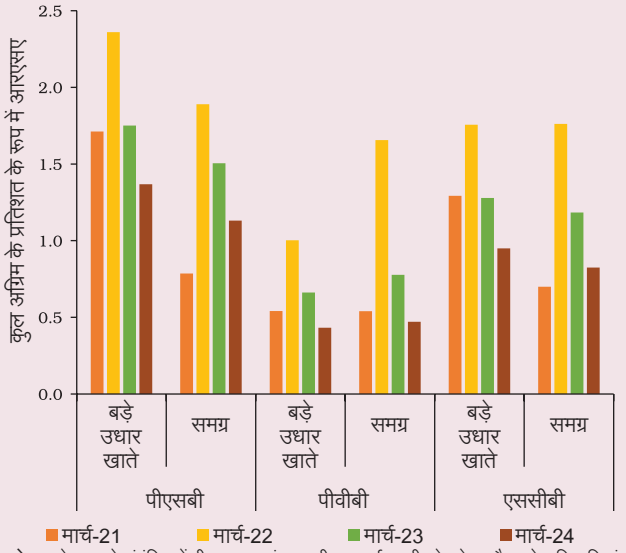

स्रोत: बड़े ऋण से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन) आरबीआई।

4.4 वसूलियां

IV.35 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, सभी चैनलों पर समाधान के लिए भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई है। 2023-24 के दौरान सरफेसी मामलों की संख्या में वृद्धि से निम्न आधार को परिलक्षित हुआ है क्योंकि 2022-23 के दौरान मामलों की संख्या में 24.6 प्रतिशत की कमी आई है। दिवाला एवं ऋण-शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) वसूली का प्रमुख माध्यम बनी रही, जिसकी 2023-24 में वसूली गई कुल राशि में 48.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही (सारणी IV.12)। आईबीसी के अंतर्गत सितंबर 2024 के अंत में प्राप्य मूल्य परिसमापन मूल्य का 161.1 प्रतिशत पर उच्च बना रहा।

IV.36 बैंकों ने आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) को एनपीए की बिक्री के माध्यम से अपनी तुलन पत्र को भी बेहतर किया। 2023-24 के दौरान, जीएनपीए का आस्ति की बिक्री का अनुपात पिछले वर्ष के 9.7 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहों में, एआरसी को अधिक बिक्री के साथ-साथ

सारणी IV.12: विभिन्न माध्यमों से एससीबी के एनपीए की वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2022-23				2023-24 (पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (4), कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (8), कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालतें	1,37,72,958	1,88,135	3,774	2.0	1,26,84,815	1,89,694	3,322	1.8
डीआरटी	56,198	4,02,753	39,785	9.9	31,414	1,06,887	16,202	15.2
सरफेसी अधिनियम	1,87,340	1,11,359	30,957	27.8	2,31,407	1,23,363	30,460	24.7
आईबीसी @	1,262	1,38715	54,161	39.0	1,004	1,63,943	46,340	28.3
कुल	**1,40,17,758**	**8,40,962**	**1,28,676**	**15.3**	**1,29,48,640**	**5,83,887**	**96,325**	**16.5**

टिप्पणियां :1. पी: अनंतिम।
2. *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है, जो दिए गए वर्ष के दौरान और साथ ही पिछले वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के संदर्भ में हो सकता है।
3. डीआरटी – वसूली अधिकरण
4. @: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई और भारतीय दिवाला एवं ऋण-शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

जीएनपीए में कमी के कारण पीएसबी और एफबी से संबंधित अनुपात में वृद्धि हुई। पीवीबी के मामले में, एआरसी को बिक्री में गिरावट, जीएनपीए में कमी से अधिक थी, जिससे अनुपात नीचे आ गया (चार्ट 19ए)। उनके आस्तियों के बही खाता मूल्य के अनुपात के रूप में एआरसी की अधिग्रहण लागत 2023-24 में लगातार दूसरे वर्ष घटी जो आस्ति के प्राप्य मूल्य में कमी का संकेत देती है (चार्ट IV.19बी)।

IV.37 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने मार्च 2024 के अंत में जारी कुल प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में से 59.1 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जो एक साल पहले यह 60.6 प्रतिशत और मार्च 2022 के अंत में 62.5 प्रतिशत था। यह निवेशक आधार के बढ़ते वैविध्य का संकेत है। अधिगृहीत आस्तियों के बही खाता मूल्य की तुलना में जारी एसआर का अनुपात 2022-23 के दौरान 29.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 27.6 प्रतिशत हो गया। पूरी तरह से भुनाए गए एसआर, जो इस माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, पिछले वर्ष के 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान पिछले वर्षों के बकाया एसआर का 37.5 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.13)।

सारणी IV.13 : एआरसी द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24
1	2	3	4
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	29	28	27
1. अर्जित आस्तियों का खाता बही मूल्य	6,29,314	8,39,126	10,25,429
2. एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद	2,04,841	2,46,290	2,83,330
3. द्वारा सब्सक्राइब की गई प्रतिभूति रसीदें			
(ए) बैंक	1,28,007	1,49,253	1,67,483
(बी) एससी/आरसी	41,350	49,519	57,201
(सी) वित्तीय संस्थागत निवेशक	15,069	19,383	21,518
(डी) अन्य (पात्र संस्थागत क्रेता)	20,415	28,135	37,128
4. पूरी तरह से भुनाई गई प्रतिभूति रसीदों की राशि	31,331	41,078	52,332
5. बकाया प्रतिभूति रसीदें	1,25,359	1,39,422	1,48,070

टिप्पणियां : 1. तिमाही के अंत तक कुल (संचयी/स्टॉक आंकड़े)।
2. एससी- प्रतिभूतीकरण कंपनियां और आरसी- पुनर्निर्माण कंपनियां।

स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.38 धोखाधड़ी वित्तीय प्रणाली के लिए प्रतिष्ठा जोखिम, परिचालन और व्यावसायिक जोखिम का कारण बनती है तथा वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को क्षति पहुँचाती है। 2023-24 के दौरान, बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की तिथि के आधार पर, धोखाधड़ी में शामिल राशि एक दशक में सबसे कम थी, जबकि औसत मूल्य 16 वर्षों में सबसे कम था। (परिशिष्ट सारणी IV.7 और सारणी IV.14)।

चार्ट IV.19 : एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री

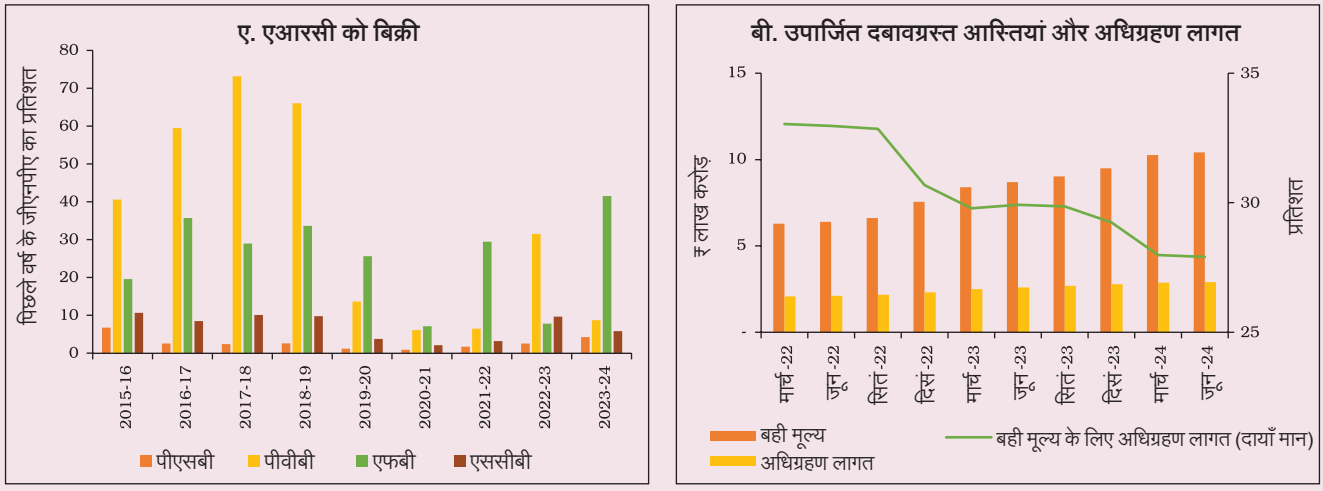

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी और परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.14: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2023-24 (अप्रैल-सितं)		2024-25 (अप्रैल-सितं)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	3,745	41,485	4,063	22,421	4,124	11,017	1,136	1,747	3,531	19,748
तुलन-पत्र से बाहर	21	1,077	14	285	11	256	4	73	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	7	7	13	12	19	38	5	5	6	1
कार्ड/इंटरनेट	3,596	155	6,699	277	29,082	1,457	12,069	630	13,133	514
जमाराशियां	471	493	652	258	2,002	240	915	103	934	363
अंतर-शाखा खाते	3	2	3	-	29	10	0	0	3	1
नकद	649	93	1,485	159	484	78	210	31	205	18
चेक/डीडी, *आदि।*	201	158	118	25	127	42	60	14	49	54
समाशोधन खाते, *आदि।*	16	1	18	3	17	2	2	0	3	1
अन्य	300	100	472	423	171	35	79	20	597	667
कुल	**9,009**	**43,571**	**13,537**	**23,863**	**36,066**	**13,175**	**14,480**	**2,623**	**18,461**	**21,367**

टिप्पणियां : 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग उस वर्ष से कई वर्ष पहले की भी हो सकती है।
4. इसमें शामिल राशि रिपोर्ट के अनुसार है और नुकसान की राशि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, ऋण खातों में शामिल पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।
5. 15 जुलाई 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(बैंकों) के साथ धोखाधड़ी के रूप में हुए हैं।

स्रोत : आरबीआई।

IV.39 धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, वर्ष 2023-24 में कुल में इंटरनेट और कार्ड धोखाधड़ी की हिस्सेदारी बढ़कर राशि के संदर्भ में 44.7 प्रतिशत और मामलों की संख्या के संदर्भ में 85.3 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.15)।

IV.40 वर्ष 2023-24 में पीवीबी द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कुल का 67.1 प्रतिशत थी (चार्ट IV.20ए)। हालांकि, शामिल राशि के संदर्भ में पीएसबी की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी (चार्ट IV.20बी)। वर्ष 2023-24 में सभी बैंक

सारणी IV.15: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2021-22 से पहले		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अप्रैल-सितं)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	7,435	82,256	2,541	8,867	2,942	2,343	2,115	1,127	430	76
तुलन-पत्र से बाहर	40	1,592	2	27	4	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3	1	9	8	21	47	11	2	1	0
कार्ड/इंटरनेट	1,078	165	4,395	173	11,979	626	27,604	1,214	7,454	225
जमाराशियां	519	621	456	122	716	200	1,903	230	465	182
अंतर-शाखा खाते	6	2	8	1	20	1	4	9	0	0
नकद	284	52	941	101	1,047	116	455	71	96	8
चेक/डीडी, *आदि।*	108	156	169	29	107	22	89	36	22	36
समाशोधन खाते, *आदि।*	9	1	19	4	14	1	12	2	0	0
अन्य	314	227	216	84	382	268	177	26	451	619
कुल	**9,796**	**85,073**	**8,756**	**9,416**	**17,232**	**3,624**	**32,370**	**2,717**	**8,919**	**1,146**

टिप्पणियां : 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. घटना की तारीख पर आधारित डेटा कुछ समय के लिए बदल सकता है क्योंकि देर से रिपोर्ट की गई लेकिन पहले हुई धोखाधड़ी को जोड़ा जाएगा।
4. सारणी में आँकड़े वित्त वर्ष 2021-22 से 30 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित है।
5. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशि के अनुसार हैं और हुई हानि की राशि को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर हुई हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, ऋण खातों में शामिल पूरी राशि को जरूरी नहीं कि डायवर्ट किया जाए।
6. 15 जुलाई 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(बैंकों) के साथ की गई धोखाधड़ी के रूप हुए हैं।

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.20 : बैंक समूह-वार धोखाधड़ी

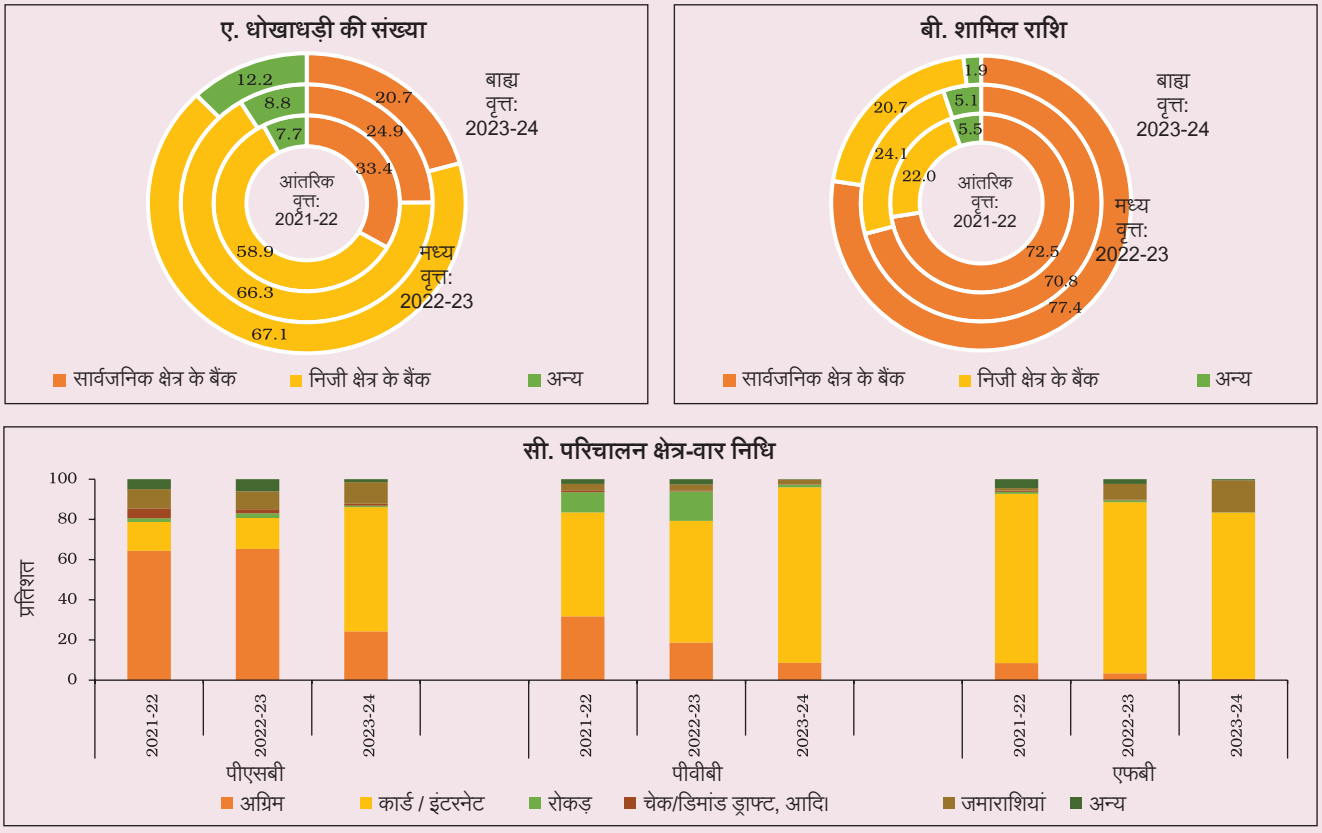

टिप्पणी : 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।
2. अन्य में समाशोधन खाते, विदेशी मुद्रा लेनदेन, अंतर-शाखा खाते, अनिवासी खाते, तुलन पत्र से इतर शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

समूहों में कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ियों की संख्या सर्वाधिक थी (चार्ट IV.20सी)।

4.6 प्रवर्तन कार्रवाइयां

IV.41 वर्ष 2023-24 के दौरान एफबी और एसएफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों में विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लगाए गए जुर्माने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2023-24 में कुल जुर्माने की राशि दोगुनी से अधिक हो गई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या सबसे अधिक थी। सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में इस वर्ष कमी आई, जबकि जुर्माना लगाने की घटनाओं में वृद्धि हुई (सारणी IV.16)।

सारणी IV.16: प्रवर्तन कार्रवाइयां

विनियमित संस्थाएं	2022-23		2023-24	
	जुर्माना लगाने की घटना	कुल जुर्माना (₹ करोड़)	जुर्माना लगाने की घटना	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7	3.6	16	23.7
निजी क्षेत्र का बैंक	7	12.2	12	24.9
सहकारी बैंक	176	14.0	215	12.1
विदेशी बैंक	5	4.7	3	7.0
भुगतान बैंक	-	-	1	5.4
लघु वित्त बैंक	2	1.0	1	0.3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	0.4	4	0.1
एनबीएफसी	11	4.4	22	11.5
एचएफ़सी	2	0.1	3	0.1
सीआईसी	-	-	4	1.0
कुल	**211**	**40.4**	**281**	**86.1**

स्रोत : आरबीआई।

5. क्षेत्रक-वार बैंक ऋण : वितरण और एनपीए

IV.42 वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण वृद्धि आधार व्यापक थी, हालांकि इसका नेतृत्व सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण खंड द्वारा किया गया, जिसके बाद कृषि और उद्योग का स्थान रहा (सारणी IV.17)[11]। उपभोक्ता ऋण के कुछ उप-खंडों में उच्च वृद्धि और बैंकों की उधारी पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता के कारण जोखिम से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को इन क्षेत्रों में ऋण मानदंडों को सख्य बना दिया[12]। उपभोक्ता वस्तुओं, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और एनबीएफसी को उधार, जैसे क्षेत्रकों में बैंक ऋण वृद्धि, जिसके लिए जोखिम भार बढ़ाया गया था, में कमी आई है।

सारणी IV.17: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रक-वार विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	के अंत में बकाया			प्रतिशत भिन्नता (व-द-व)		
	मार्च-23	मार्च-24	अक्टू-24	मार्च-23	मार्च-24	अक्टू-24
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**17,26,410**	**20,71,251**	**22,05,299**	**15.4**	**20.0**	**15.5**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बृहत)	**33,66,406**	**36,52,804**	**37,74,252**	**5.8**	**8.5**	**7.9**
		(36,35,810)	**(37,59,186)**		**(8.0)**	**(8.0)**
2.1. सूक्ष्म और लघु उद्योग	6,33,289	7,26,315	7,49,790	13.1	14.7	10.0
2.2. मध्यम	2,68,286	3,03,998	3,35,822	12.3	13.3	19.6
2.3. बृहत	24,64,831	26,22,490	26,88,640	3.5	6.4	6.0
3. सेवाएं, *जिनमें से*	**37,18,805**	**45,92,227**	**47,84,938**	**19.5**	**23.5**	**12.7**
		(44,90,467)	**(47,04,550)**		**(20.8)**	**(14.1)**
3.1. परिवहन परिचालक	1,92,059	2,30,175	2,46,407	14.7	19.8	15.0
3.2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,924	25,917	30,581	7.1	4.0	24.0
3.3. पर्यटन, होटल और रेस्तरां	69,342	77,513	79,732	3.3	11.8	5.4
3.4. व्यापार	8,72,340	10,25,752	10,79,498	18.5	17.6	12.4
3.5. व्यापारिक स्थावर संपदा	3,22,591	4,69,013	5,07,671	8.4	45.4	13.9
		(4,00,470)	(4,52,869)		(24.1)	(26.0)
3.6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएससी)	13,42,539	15,48,027	15,36,655	29.9	15.3	6.4
4. वैयक्तिक ऋण, जिनमें से	**41,82,767**	**53,31,290**	**56,47,476**	**20.7**	**27.5**	**12.9**
		(49,19,468)	**(52,78,594)**		**(17.6)**	**(15.8)**
4.1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	20,985	23,713	23,640	17.7	13.0	6.6
4.2. आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त आवास सहित)	19,91,164	27,18,715	28,71,845	14.5	36.5	12.1
		(23,31,935)	(25,25,138)		(17.1)	(17.8)
4.3. सावधि जमा के एवज में अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियां,आदि सहित)	1,22,484	1,25,239	1,27,533	46.4	2.2	10.9
4.4. व्यक्तियों को शेयरों, बांडों, आदि की जमानत पर अग्रिम	7,633	8,492	9,060	12.1	11.3	16.0
4.5. क्रेडिट कार्ड बकाया	2,04,708	2,57,016	2,81,392	32.5	25.6	16.9
4.6. शिक्षा ऋण	96,482	1,19,380	1,30,309	15.3	23.7	17.6
4.7. वाहन ऋण	5,01,979	5,89,251	6,16,405	24.0	17.4	11.4
4.8. स्वर्ण आभूषण के एवज में ऋण	89,370	1,02,562	1,54,282	19.6	14.8	56.2
5. बैंक ऋण	**1,36,75,235**	**1,64,32,164**	**1,72,38,250**	**15.0**	**20.2**	**11.5**
		(1,59,01,477)	**(1,67,72,605)**		**(16.3)**	**(12.8)**
5.1 गैर-खाद्य ऋण	**1,36,55,330**	**1,64,09,083**	**1,72,19,596**	**15.4**	**20.2**	**11.5**
		(1,58,78,397)	**(1,67,53,951)**		**(16.3)**	**(12.8)**

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 28 जुलाई 2023 से अब तक के आंकड़ों में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को शामिल किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।
3. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण में लगे एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

[11] बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा पाक्षिक खंड -42 विवरणी पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल करता है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रक-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।

[12] वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण जोखिम (बकाया और नए) के लिए जोखिम भार वैयक्तिक ऋणों के लिए 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया, जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों द्वारा संपार्श्विक ऋण शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, एससीबी के क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के लिए जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया। एनबीएफसी को ऋण देने के लिए जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई।

IV.43 कुल ऋण में सेवाओं और वैयक्तिक ऋण खंडों की हिस्सेदारी मार्च 2013 के अंत में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में क्रमशः 27.9 प्रतिशत और 32.4 प्रतिशत हो गई है[13]। ऋण विविधीकरण बैंकों को उनकी लाभप्रदता में सुधार करने में मदद कर सकता है (बॉक्स IV.3)।

बॉक्स IV.3: बैंकों की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण का प्रभाव

पोर्टफोलियो विविधीकरण बैंकों की वित्तीय मध्यस्थता लागत को कम करता है और उनकी लाभप्रदता को बढ़ा सकता है (डायमंड, 1984)। हालांकि, क्षेत्र-वार ऋण विविधीकरण से मापन अदक्षता भी आ सकती है जो बैंकों की लाभप्रदता को कम कर सकती है (आचार्य, 2006)। इसलिए, बैंक लाभप्रदता पर क्षेत्र-वार ऋण विविधीकरण के प्रभाव का अनुभवजन्य साक्ष्य मिले-जुले हैं (मुलवा, 2018)।

मार्च 2015 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए 12 सार्वजनिक और 19 निजी क्षेत्र के बैंकों के तिमाही डेटा का उपयोग करके एक निश्चित प्रभाव पैनल फ्रेमवर्क (समीकरण 1) में बैंकों की लाभप्रदता पर विविधीकरण के प्रभाव की जांच की जाती है।

$$NIM_{it} = \beta_{i0} + \beta_1 D_{it} + \gamma V_{it} + \epsilon_{it} \qquad \text{(समीकरण 1)}$$

जहाँ, NIM_{it} समय *t* पर बैंक *i* का निवल ब्याज मार्जिन है, D_{it} समय *t* पर बैंक *i* का विविधीकरण माप है, V_{it} बैंक आस्तियों, जीएनपीए अनुपात, ऋण वृद्धि और IIP वृद्धि सहित नियंत्रण चर का एक वेक्टर है। साहित्य से संदर्भ लेकर, दो विविधीकरण सूचकांक बनाए गए हैं - पहला हिर्शमैन-हर्फिंडाहल पद्धति का उपयोग कर और दूसरा शैनन एन्ट्रॉपी का उपयोग कर।

$$HHI_{it} = 1 - \sum_{i=1}^{n} s_{it}^2 \; ; \; Entropy_{it} = -\sum_{i=1}^{n} s_{it} \ln(s_{it})$$

जहाँ s_{it} समय *t* पर बैंक *i* के कुल ऋण में प्रत्येक सेक्टर[14] का हिस्सा है। प्रत्येक सूचकांक का उच्च मूल्य उच्च पोर्टफोलियो विविधीकरण को दर्शाता है। स्कैटर प्लॉट पोर्टफोलियो विविधीकरण और बैंकों की लाभप्रदता के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है (चार्ट IV.3.1)।

परिणाम से पता चलता है कि एनआईएम और विविधीकरण सूचकांकों के बीच धनात्मक और महत्वपूर्ण संबंध हैं, जिसने पोर्टफोलियो विविधीकरण ने लाभप्रदता के मामले में बैंकों को लाभ पहुंचाया है। इसके अधिशेष, जीएनपीए अनुपात द्वारा मापी गई आस्ति गुणवत्ता, एनआईएम के साथ ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है। विविधीकरण सूचकांकों (पीवीबी*एचएचआई और पीवीबी*एंट्रॉपी) के साथ निजी बैंक डमी की अंतःक्रिया द्वारा मापी गई पीवीबी बनाम पीएसबी की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण का विभेदक प्रभाव, नगण्य पाया गया है। यह पीवीबी और पीएसबी दोनों की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण के सममित प्रभाव को दर्शाते हैं (सारणी IV.3.1)।

चार्ट IV.3.1: एचएचआई और निवल ब्याज मार्जिन

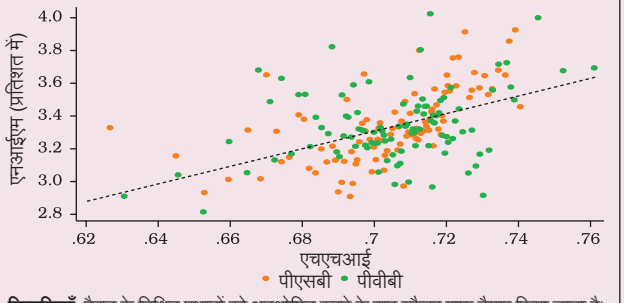

टिप्पणियाँ: पैनल के निश्चित प्रभावों को अवशोषित करने के बाद स्कैटर ग्राफ तैयार किया जाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी IV.3.1: प्रतिगमन परिणाम

चर	आश्रित चर: निवल ब्याज मार्जिन			
	(1)	(2)	(3)	(4)
लैग (एचएचआई)	3.096***	2.201		
	(0.957)	(1.319)		
लैग (एन्ट्रॉपी)			1.712***	1.595*
			(0.423)	(0.790)
लैग (लॉग आस्तियां)	0.0404	-0.000524	-0.0168	-0.0248
	(0.372)	(0.364)	(0.379)	(0.370)
लैग (जीएनपीए अनुपात)	-0.0307***	-0.0309***	-0.0308***	-0.0309***
	(0.00544)	(0.00542)	(0.00548)	(0.00549)
लैग (ऋण वृद्धि) (वर्ष-दर-वर्ष)	0.00392	0.00429	0.00413	0.00419
	(0.00246)	(0.00251)	(0.00246)	(0.00248)
एक्यूआर डमी	-0.183***	-0.190***	-0.189***	-0.190***
	(0.0455)	(0.0494)	(0.0463)	(0.0509)
कोविड डमी	-0.00876	-0.00214	-0.00777	-0.00632
	(0.0366)	(0.0348)	(0.0365)	(0.0353)
लैग (पीवीबी*एचएचआई)		1.345		
		(1.671)		
लैग (पीवीबी*एन्ट्रॉपी)				0.149
				(0.911)
लॉग(आईआईपी)	1.337**	1.402**	1.348**	1.364**
	(0.508)	(0.528)	(0.509)	(0.533)
स्थिरांक	-1.573	-1.441	-1.326	-1.283
	(1.495)	(1.426)	(1.498)	(1.398)
प्रेक्षण	1,081	1,081	1,081	1,081
आर-स्क्वायर्ड	0.738	0.738	0.739	0.739
स्थिर प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बैंकों की संख्या	31	31	31	31

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।
3. कोविड डमी मार्च 2020 से मार्च 2022 तक समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान मूल्य को 1 और अन्यथा शून्य माना है।
4. एक्यूआर डमी सितंबर 2015 से मार्च 2018 तक समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान मूल्य को 1 और अन्यथा शून्य माना है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios. *The Journal of Business*, 79(3), 1355–1412.

Diamond, D. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *The Review of Economic Studies*, 51(3), 393.

Mulwa, J. (2018). Sectoral Credit Diversification, Bank Performance and Monitoring Effectiveness: A Cross-country Analysis of East African Banking Industries. *Journal of Finance and Investment Analysis*, 7(2), 17–36.

[13] मार्च 2024 के डेटा में एक गैर-बैंक का निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय शामिल है। विलय को छोड़कर, मार्च 2024 के अंत में हिस्सेदारी इस प्रकार थी : सेवाएँ 28.2 प्रतिशत और वैयक्तिक ऋण 30.5 प्रतिशत।

[14] क्षेत्रकों में कृषि, उद्योग, सेवाएं और वैयक्तिक ऋण शामिल हैं।

IV.44 सितंबर 2024 के अंत में जीएनपीए अनुपात कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक (6.2 प्रतिशत) और खुदरा ऋणों के लिए सबसे कम (1.2 प्रतिशत) रहा। मार्च 2018 से औद्योगिक क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, सितंबर 2024 के अंत में जीएनपीए अनुपात घटकर 2.9 प्रतिशत रह गया। सभी बैंक समूहों में क्षेत्रक-वार ऋण का जीएनपीए अनुपात पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तित हुआ है (चार्ट IV.21)।

IV.45 शिक्षा ऋणों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 5.8 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 के अंत में 3.6 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत हो गया, लेकिन यह खुदरा ऋणों में सबसे अधिक रहा, इसके बाद क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में था (चार्ट IV.22ए)। सेवा क्षेत्र में, पर्यटन, होटल और रेस्तरां क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात अधिक बना रहा, हालांकि यह मार्च 2023 के अंत में 6.7 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 के अंत में 4.3 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 4.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.22बी)। औद्योगिक उप-क्षेत्रों में, रत्न और आभूषण खंड का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 16.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 6.7 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 5.0 प्रतिशत हो गया, जो आंशिक रूप से उच्च वसूली को दर्शाता है। सितंबर 2024 के अंत में, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग में हाल ही में कुछ सुधार के बावजूद सबसे अधिक 7.3 प्रतिशत जीएनपीए अनुपात था (चार्ट IV.22सी)।

चार्ट IV.21: क्षेत्रक-वार जीएनपीए अनुपात

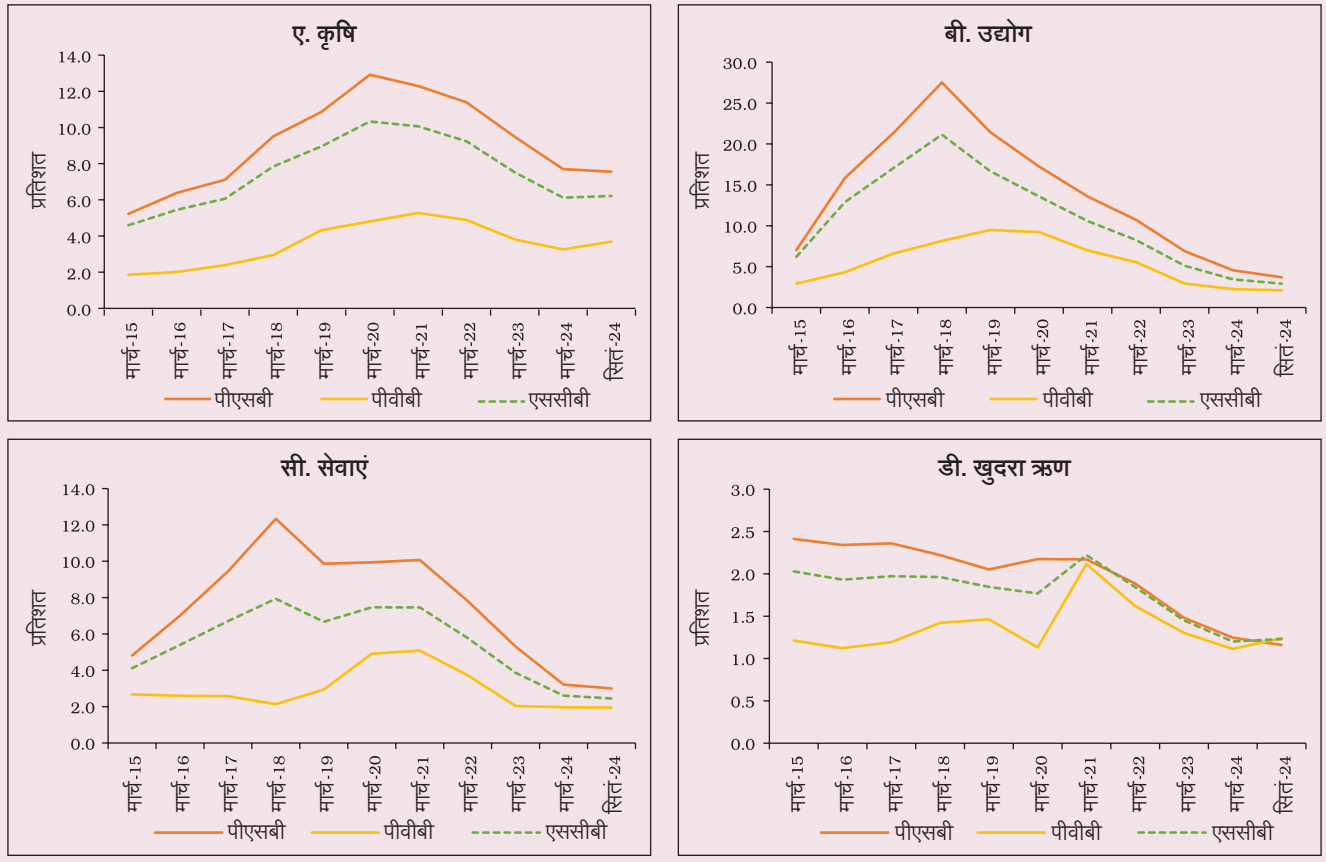

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.22: विभिन्न उद्योगों में जीएनपीए अनुपात

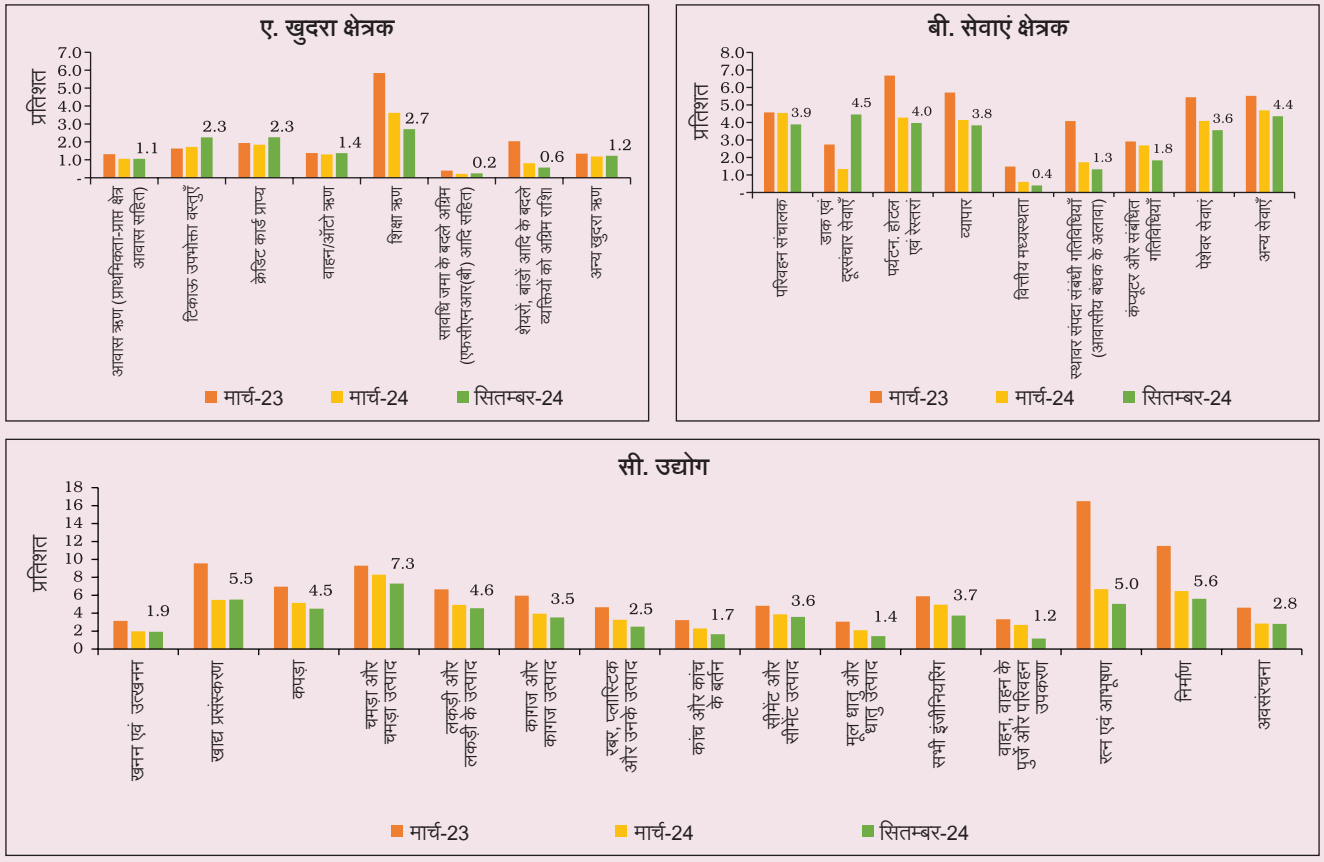

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

5.1 *एमएसएमई क्षेत्र को ऋण*

IV.46 पीवीबी द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार वाले उद्यम क्षेत्रक एमएसएमई क्षेत्र को दिए ऋण में वृद्धि लगातार दोहरे अंकों में बनी हुई है, जो 2023-24 में 28.7 प्रतिशत तक पहुँच गई है। एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया बकाया ऋण बढ़कर ₹27.25 लाख करोड़ हो गया, जो मार्च 2024 के अंत तक कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 19.3 प्रतिशत है।

IV.47 एससीबी के एमएसएमई ऋण खातों की संख्या 2023-24 के दौरान बढ़ी, जो 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रवृत्ति को उलट देती है। एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि, खातों की संख्या में वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप औसत ऋण में वृद्धि हुई (सारणी IV.18)।

5.2 *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण*

IV.48 एससीबी का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार पिछले वर्ष के 10.8 प्रतिशत से बढ़ कर 2023-24 में 16.9 प्रतिशत हो गया, जिसमें पीवीबी (15.7 प्रतिशत से 23.5 प्रतिशत) और पीएसबी (7.1 प्रतिशत से 12.3 प्रतिशत) दोनों में वृद्धि शामिल है। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे (सारणी IV.19)। चालू *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया राशि भी पिछले वर्ष के 8.8 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें मुख्य योगदान दक्षिणी क्षेत्र का रहा। केसीसी के तहत बकाया राशि का सबसे अधिक हिस्सा भी दक्षिणी क्षेत्र का था। यद्यपि इसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के 18.3 प्रतिशत से घटकर

सारणी IV.18: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	111	151	150	139	144
		(-1.9)	(36.1)	(-0.7)	(-7.4)	(4.2)
	बकाया राशि	8,93,315	9,08,659	9,55,860	10,84,953	12,22,687
		(1.5)	(1.7)	(5.2)	(13.5)	(11.3)
निजी क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	271	267	113	73	110
		(31.8)	(-1.4)	(-57.7)	(-35.2)	(50.2)
	बकाया राशि	6,46,988	7,92,042	9,69,844	10,89,833	14,02,324
		(14.8)	(22.4)	(22.4)	(12.4)	(28.7)
विदेशी बैंक	खातों की संख्या	3	3	2	2	3
		(14.1)	(-5.1)	(-19.0)	(-26.3)	(72.9)
	बकाया राशि	73,279	83,224	85,352	85,349	1,00,261
		(9.5)	(13.6)	(2.6)	(0.0)	(17.5)
सभी एससीबी	खातों की संख्या	384	420	265	213	257
		(19.8)	(9.4)	(-37.0)	(-19.4)	(20.5)
	बकाया राशि	16,13,582	17,83,925	20,11,057	22,60,135	27,25,272
		(6.8)	(10.6)	(12.7)	(12.4)	(20.6)

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर को दर्शाते हैं।
स्रोत : आरबीआई।

2023-24 के दौरान 13.2 प्रतिशत हो गई, फिर भी यह अखिल भारतीय विस्तार दर से ऊपर रही (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

IV.49 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल ट्रेडिंग मात्रा 2023-24 के दौरान 25.5 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मुख्य योगदान पीएसएलसी-सामान्य का रहा।

सारणी IV.19: बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

(मार्च 2024 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	**40/75***	**31,85,092**	**42.6**	**24,09,329**	**47.4**	**2,51,550**	**41.6**	**1,31,967**	**90.6**	**59,77,938**	**45.0**
जिसमें से											
सकल कृषि	18.0	14,25,554	19.1	9,51,089	18.7	49,700	18.6	38,964	26.8	24,65,307	19.0
छोटे और सीमांत किसान	10.0	8,32,757	11.2	5,05,484	10.0	29,309	11.0	26,517	18.2	13,94,068	10.8
गैर-कॉरपोरेट व्यक्तिक किसान#	13.8	11,05,493	14.8	7,08,677	14.0	29,435	14.2	36,962	25.4	18,80,568	14.6
सूक्ष्म उद्यम	7.5	5,97,854	8.0	5,17,925	10.2	22,682	8.5	47,494	32.6	11,85,956	9.2
कमजोर वर्ग	12.0	10,53,784	14.1	6,37,014	12.5	32,284	12.1	52,146	35.8	17,75,229	13.7

टिप्पणियां : 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है।
2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत है।
3. #: गैर-कॉरपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू प्रणाली व्यापी औसत आंकड़ा 13.78 प्रतिशत था।
4. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू है।
5. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : आरबीआई।

चार पीएसएलसी श्रेणियों में, छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ) श्रेणी ने सबसे अधिक ट्रेडिंग मात्रा दर्ज की, जो आंशिक रूप से कुछ बैंकों के मामले में विशेषज्ञता और अन्य बैंकों द्वारा उप-लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है (चार्ट IV.23)।

IV.50 पिछले पांच वर्षों में, पीवीबी पीएसएलसी के प्रमुख निवल विक्रेता के रूप में उभरे हैं। 2023-24 में पीवीबी की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 49.2 प्रतिशत है, जबकि पीएसबी के मामले में यह हिस्सेदारी 20.7 प्रतिशत है (चार्ट IV.24)।

IV.51 पिछले तीन वर्षों में, पीएसएलसी-एसएमएफ को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत प्रीमियम (डब्ल्यूएपी) में गिरावट आई है। यह *अन्य बातों के साथ-साथ* पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यमों की कम मांग को दर्शाता है; क्योंकि बैंक इन क्षेत्रकों को ऋण देने में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पीएसएल उप-लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके (सारणी IV.20)।

IV.52 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के ऋण का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 5.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 4.4 प्रतिशत हो गया। फिर भी, गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एनपीए में अधिक तेजी से गिरावट के कारण एससीबी

चार्ट IV.23: पीएसएलसी व्यापार की मात्रा

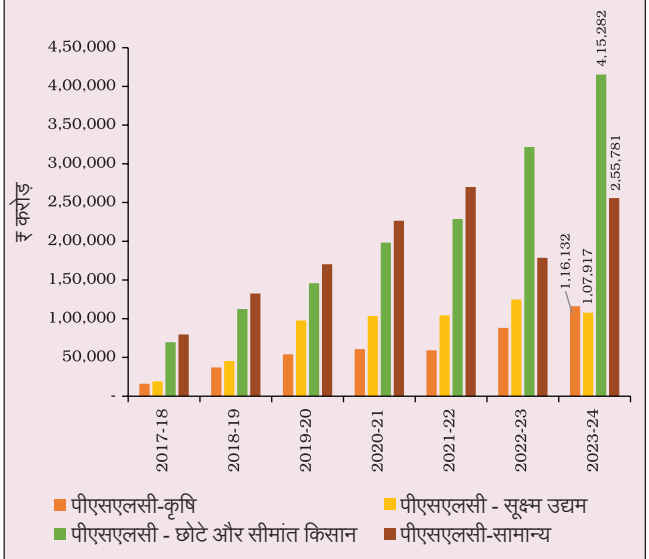

स्रोत : आरबीआई।

के कुल जीएनपीए में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 57.3 प्रतिशत हो गई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एनपीए का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि चूक का रहा।

IV.53 जहाँ, पीएसबी ने अपने एएनबीसी/ तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (सीईओबीई) के ऋण का 42.6 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया, वहीं, इस पोर्टफोलियो का उनके कुल एनपीए में 64.2 प्रतिशत का हिस्सा रहा। एसएफबी के मामले

चार्ट IV.24: पीएसएलसी बाजार में क्रेता और विक्रेता

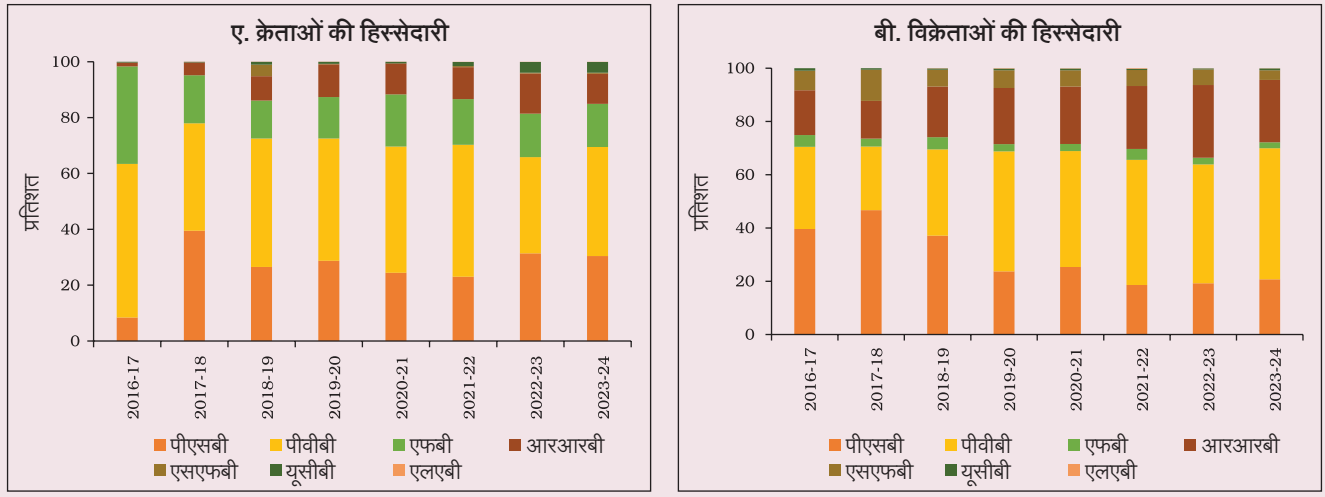

स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.20: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 (अप्रै.-जून)	2024-25 (अप्रै.-जून)
1	2	3	4	5	6	7
पीएसएलसी-कृषि	1.55	1.37	0.62	0.24	0.27	0.24
पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम	0.88	0.95	0.16	0.04	0.12	0.01
पीएसएलसी- लघु और सीमांत किसान	1.74	2.01	1.68	1.74	1.98	1.97
पीएसएलसी- सामान्य	0.46	0.6	0.19	0.02	0.02	0.01

स्रोत : आरबीआई।

में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उनके एएनबीसी/सीईओबीई का 90.6 प्रतिशत है; उनके कुल एनपीए में इसका हिस्सा पिछले वर्ष के 42.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 72.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.21)।

5.3 *संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण*

IV.54 पूंजी बाजार और अचल संपत्ति में बैंकों के निवेश को आस्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव में निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील माना जाता है। बैंकों के वार्षिक लेखा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2024 के अंत में, इन क्षेत्रों में पीएसबी का निवेश उनके कुल ऋण और अग्रिमों का 22.1 प्रतिशत था, जो एक साल पहले के 21.7 प्रतिशत से अधिक था। संवेदनशील क्षेत्रों में पीवीबी का निवेश एक वर्ष पहले के 27.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर उनके कुल ऋण और अग्रिमों का 34.7 प्रतिशत हो गया, जो काफी हद तक विलय के प्रभाव को दर्शाता है। एससीबी के पूंजी बाजार जोखिम में वृद्धि पिछले वर्ष के 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 31.3 प्रतिशत हो गई, जिसमें दोनों बैंक समूहों का योगदान रहा। (चार्ट IV.25ए और बी और परिशिष्ट सारणी IV.9)।

सारणी IV.21: बैंकों के क्षेत्रक-वार जीएनपीए

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		*जिनमें*						गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पीएसबी												
2023	2,25,638	56.2	1,14,409	28.5	80,577	20.1	30,652	7.6	1,75,666	43.8	4,01,304	100.0
2024	2,05,777	64.2	1,06,451	33.2	75,278	23.5	24,049	7.5	1,14,963	35.8	3,20,740	100.0
पीवीबी												
2023	42,321	36.5	19,999	17.3	14,569	12.6	7,752	6.7	73,470	63.5	1,15,791	100.0
2024	49,986	40.5	21,211	17.2	18,340	14.8	10,435	8.4	73,553	59.5	1,23,540	100.0
एफबी												
2023	2,149	22.6	221	2.3	1,542	16.2	386	4.1	7,377	77.4	9,526	100.0
2024	1,795	27.5	162	2.5	1,315	20.2	318	4.9	4,728	72.5	6,523	100.0
एसएफबी												
2023	3,621	42.1	1,397	16.2	1,054	12.2	1,170	13.6	4,987	57.9	8,608	100.0
2024	4,031	72.1	1,878	33.6	1,137	20.3	1,015	18.2	1,560	27.9	5,590	100.0
सभी एससीबी												
2023	2,73,729	51.1	1,36,026	25.4	97,742	18.3	39,960	7.5	2,61,500	48.9	5,35,229	100.0
2024	2,61,589	57.3	1,29,701	28.4	96,070	21.0	35,817	7.8	1,94,804	42.7	4,56,393	100.0

टिप्पणी : प्रतिशत: कुल एनपीए का प्रतिशत।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.25: संवेदनशील क्षेत्रकों में एक्सपोजर
(मार्च-अंत में)

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

5.4 *गैर-जमानती ऋण*

IV.55 संपार्श्विक की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के कारण गैर-जमानती ऋण चूक की स्थिति में बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम उत्पन्न करते हैं। एससीबी के कुल ऋण में गैर-जमानती ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत से बढ़ रही थी, जो मार्च 2023 के अंत तक 25.5 प्रतिशत को छू गई। यह हिस्सा मार्च 2024 के अंत में मामूली रूप से घटकर 25.3 प्रतिशत हो गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा पीवीबी का रहा, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* इन क्षेत्रों में जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक के नवंबर 2023 के उपायों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट IV.26ए)। विभिन्न बैंक समूहों में, पीएसबी के पास गैर-जमानती अग्रिमों का सबसे कम हिस्सा था, उसके बाद पीवीबी थे। गैर-जमानती ऋणों के लिए बैंक-वार जोखिम का माध्य, माध्यिका और विसरण एफबी में सबसे अधिक था (चार्ट IV.26बी)।

6. वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप

IV.56 बैंकों का स्वामित्व पैटर्न बैंकों के अभिशासन, स्थिरता और समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023-

चार्ट IV.26: गैर-जमानती अग्रिमों की हिस्सेदारी

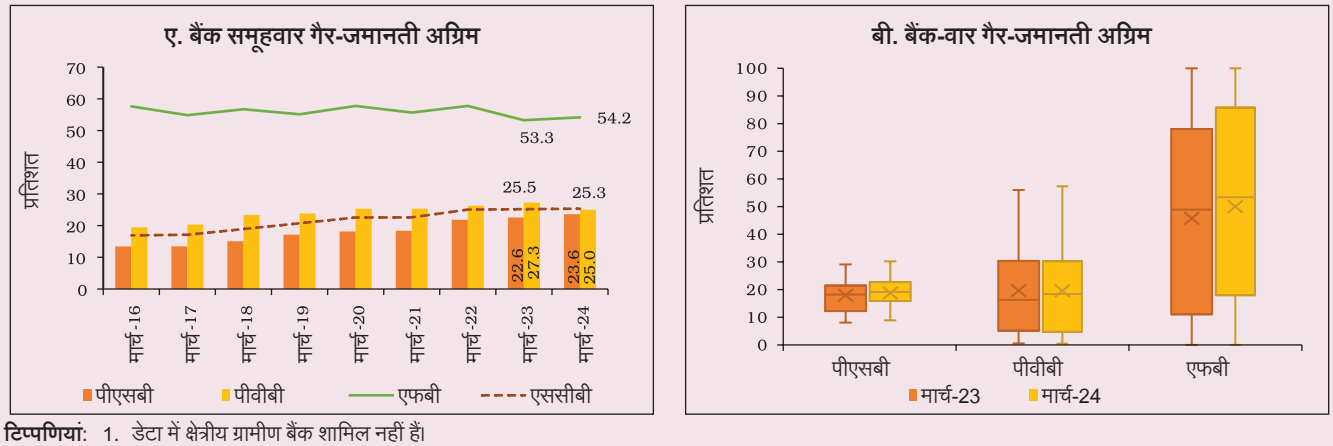

टिप्पणियां: 1. डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं।
2. बॉक्स प्लॉट की व्हिसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मानों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले क्वांटाइल और तीसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाता है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

24 के दौरान, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत से नीचे कर दी (चार्ट IV.27ए)। इसके साथ ही, मार्च 2024 के अंत में सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा कर लिया। सरकार ने 19 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अभी तक उक्त मानदंड को पूरा नहीं कर पाने वाले पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 अगस्त, 2026 तक छूट प्रदान की है। पीवीबी का स्वामित्व स्वरूप अधिक विविध है (चार्ट IV.27बी)।

IV.57 2023-24 के दौरान, बैंकों में अनिवासी स्वामित्व पीवीबी, एलएबी और एसएफबी के लिए 74 प्रतिशत तथा पीएसबी के लिए 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहा (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

IV.58 कॉरपोरेट अभिशासन संसाधनों के आवंटन में दक्षता, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल, 2021 को बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना; बोर्ड की अध्यक्षता और बैठकों; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक; और बैंकों में मजबूत और पारदर्शी जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए।[15]

7.1 निदेशक मंडल का गठन

IV.59 स्वतंत्र निदेशक विशेष रूप से कार्यनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानदंड संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके बोर्ड के विचार-विमर्श में योगदान देते हैं। मार्च 2024 के अंत में, पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए, बोर्ड और इसकी समिति में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी निर्धारित सीमा से बहुत अधिक थी (सारणी IV.22)।[16]

चार्ट IV.27: बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप

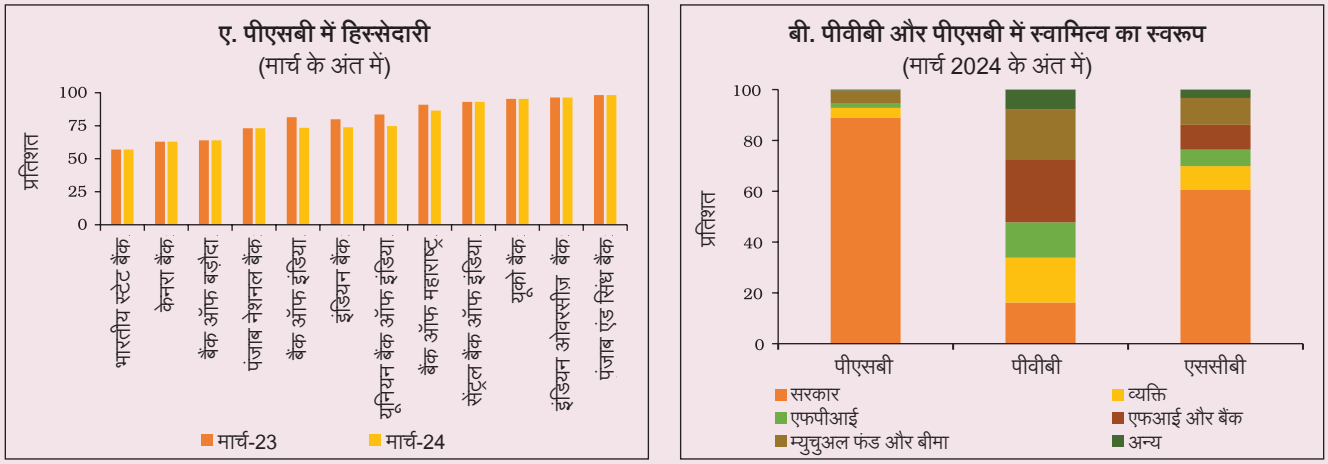

टिप्पणि: एससीबी में 12 पीएसबी, 21 पीवीबी, 12 एसएफबी और 6 पीबी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई और बीएसई वेबसाइट।

[15] ये निर्देश सभी पीवीबी (एसएफबी सहित) और एफबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर लागू किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, इन दिशा-निर्देशों को केवल इस सीमा तक लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था कि वे उन पर लागू विशिष्ट क़ानूनों के प्रावधानों या क़ानूनों के तहत जारी किए गए निर्देशों के साथ असंगत न हों।

[16] रिज़र्व बैंक द्वारा 26 अप्रैल, 2021 को कॉरपोरेट अभिशासन पर जारी किए गए अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ , यह अनिवार्य किया गया है कि बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे; बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होगी; एनआरसी की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक आरएमसीबी का सदस्य होगा; एसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

सारणी IV.22: बोर्ड और उसकी समितियों के स्वतंत्र निदेशक
(मार्च के अंत में)

प्रतिशत में हिस्सेदारी

	बोर्ड		बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)		नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)		बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीवीबी	65	65	67	70	78	85	83	87
एसएफबी	68	67	76	73	83	79	83	82

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट और बैंकों के वेबसाइट।

IV.60 बैंकों को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन करना आवश्यक है, जिसमें गैर-कार्यकारी निदेशकों का बहुमत हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। पीवीबी का अनुपात, जिसमें अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2024 के अंत में 38 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। एसएफबी के लिए, अनुपात मार्च 2023 के अंत में 42 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 33 प्रतिशत हो गया।

7.2 कार्यपालकों को मुआवजा

IV.61 अल्पकालिक जोखिम लेने और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, नवंबर 2019 के रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा (कम से कम 50 प्रतिशत) परिवर्तनीय होना चाहिए और इसका भुगतान प्रदर्शन को पर्याप्त रूप से मापने वाले व्यक्तिगत, व्यवसाय-इकाई और फर्म-व्यापी संकेतकों के आधार पर किया जाना चाहिए।[17] इसके अलावा दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि लक्ष्य परिवर्तनीय वेतन (टीवीपी) निर्धारित वेतन का 200 प्रतिशत (200 प्रतिशत से अधिक) है, तो टीवीपी का न्यूनतम 50 प्रतिशत (67 प्रतिशत) गैर-नकद घटकों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। 2022-23 के दौरान, कुल पारिश्रमिक में वास्तविक वीपी की हिस्सेदारी पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए बेहतर हुई है (चार्ट IV.28ए)। वास्तविक वीपी में गैर-नकद घटक की हिस्सेदारी पीवीबी के लिए घटकर 52 प्रतिशत और एसएफबी के लिए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.28बी)।

चार्ट IV.28: एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक
(मार्च के अंत में)

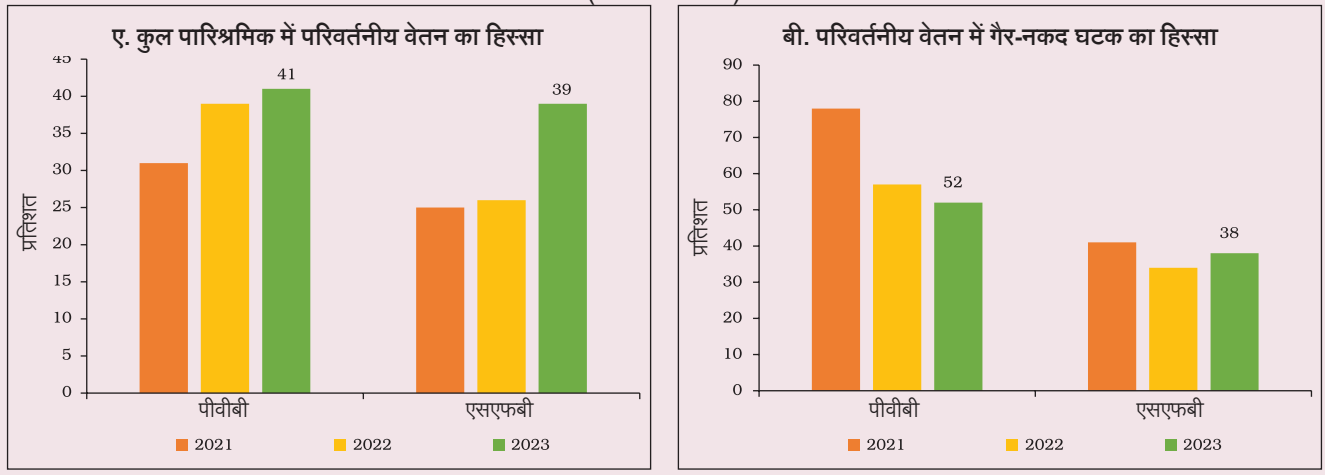

स्रोत : आरबीआई।

[17] पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के मुआवजे पर 4 नवंबर, 2019 को जारी दिशानिर्देश, 01 अप्रैल, 2020 से/उसके बाद शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए प्रभावी हो गए हैं। ये दिशानिर्देश एलएबी, एसएफबी और पीबी सहित पीवीबी और शाखाओं और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से भारत में परिचालन करने वाले एफबी पर लागू हैं।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

IV.62 2023-24 के दौरान, भारत में कार्यरत एफबी की संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि विदेशी बैंकों में से एक, जिसका पहले केवल एक प्रतिनिधि कार्यालय था, ने पूरी तरह से कार्यशील बैंक शाखा खोली। हालाँकि, लगातार तीसरे वर्ष एफबी की शाखाओं की संख्या में गिरावट आई, जो वैश्विक रणनीति का पुनःसंरेखण और व्यवसाय मूल्य अनुकूलन को दर्शाती है (सारणी IV.23)।

IV.63 भारतीय बैंक अपना विदेशी परिचालन मुख्य रूप से शाखाओं के माध्यम से करते हैं (चार्ट IV.29)। 2023-24 के दौरान, पीएसबी ने अव्यवहार्य शाखाओं को बंद करके अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाया, जबकि पीवीबी की विदेशी उपस्थिति अपरिवर्तित रही (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

9. भुगतान प्रणालियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.64 भारत की भुगतान प्रणालियां तेजी से विकसित हुई हैं, जिसमें विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवोन्मेष और समावेशन दोनों को अपनाया गया है, साथ ही उच्च सुरक्षा मानकों को भी बनाए रखा गया है। यह परिदृश्य पारंपरिक बैंकिंग चैनलों को अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों के साथ जोड़ता है, जिससे सुरक्षित, त्वरित और सुविधाजनक लेनदेन संभव हो पाता है। यह परिवर्तन तकनीकी प्रगति, एक

सारणी IV.23: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

	शाखाओं/डबल्यूओएस के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएँ#	
1	2	3	4
मार्च-21	45	874	36
मार्च-22	45	861	34
मार्च-23	44	782	33
मार्च-24	45	780	31

टिप्पणी : #: इसमें दो विदेशी बैंक शामिल हैं अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डबल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं।
स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.29: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन
(मार्च के अंत में)

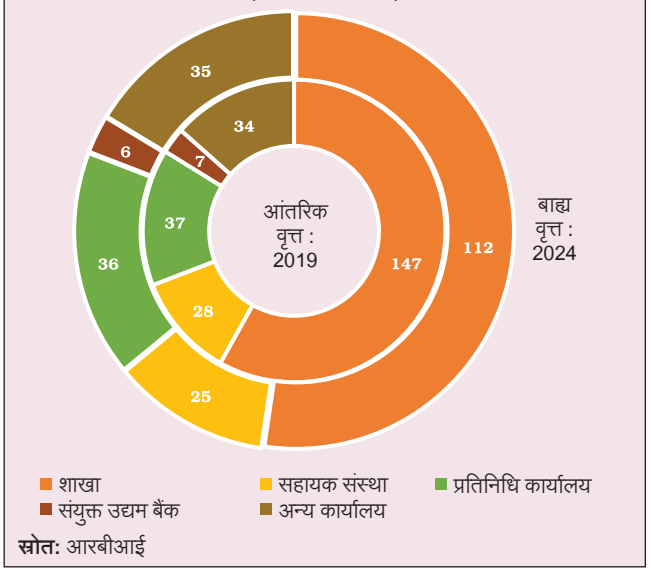

स्रोत: आरबीआई

मजबूत विनियामकीय ढांचे और नकद रहित लेनदेन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों द्वारा प्रेरित है।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.65 2021-2024 के दौरान, डिजिटल भुगतान विधियों ने मात्रा के आधार पर 49.9 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर 14.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त की। इसके विपरीत, चेक और डिमांड ड्राफ्ट जैसे कागज़-आधारित लिखतों में संकुचन हुआ, जिसमें मात्रा के आधार पर (-)10.1 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर (-)1.6 प्रतिशत की सीएजीआर रही। छोटे मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, खुदरा डिजिटल भुगतान का औसत मूल्य मार्च 2021 में ₹8,769 से घटकर मार्च 2024 में ₹4,560 हो गया है (चार्ट IV.30)

IV.66 मार्च 2024 के अंत में मूल्य के संदर्भ में कुल भुगतानों में से 97.1 प्रतिशत डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए। लेन-देन की मात्रा के मामले में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि मूल्य के मामले में तत्काल

चार्ट IV.30: खुदरा डिजिटल भुगतान बनाम कागज आधारित लिखतों का औसत मान

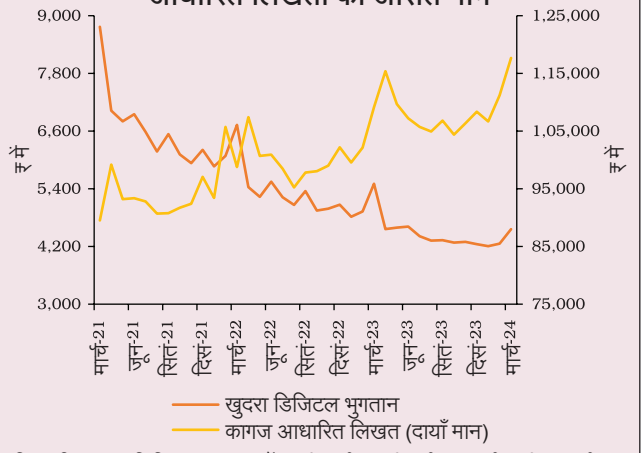

टिप्पणी: खुदरा डिजिटल भुगतान में एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एनएसीएच, भीम आधार पे, एईपीएस निधि अंतरण, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और प्रीपेड भुगतान साधन शामिल हैं। कागज़ आधारित लिखतों में चेक, डिमांड ड्राफ्ट और अन्य शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

सकल निपटान (आरटीजीएस) का सबसे बड़ा हिस्सा है (सारणी IV.24)।

IV.67 रिज़र्व बैंक ने डिजिटलीकरण की प्रगति को मापने और डिजिटल भुगतान की गहनता और पैठ का आकलन करने के लिए जनवरी 2021 में एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया, जिसमें पाँच व्यापक मापदंड शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक; भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान प्रदर्शन; और उपभोक्ता केन्द्रीयता । सूचकांक की गणना अर्ध-वार्षिक रूप से मार्च 2018 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। मार्च 2024 के अंत में, सूचकांक एक वर्ष पहले के 395.6 की तुलना में 445.5 पर था, जो पूरे देश में भुगतान प्रदर्शन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित था (चार्ट IV.31)।

सारणी IV.24: भुगतान प्रणाली संकेतक

	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
1. वृहत मूल्य ऋण अंतरण- आरटीजीएस	2,078	2,426	2,700	12,86,57,516	14,99,46,286	17,08,86,670
2. ऋण अंतरण	5,77,935	9,83,621	14,86,107	4,27,28,006	5,50,09,620	6,75,42,859
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	10	6	4	575	356	261
2.2 एपीबीएस	12,573	17,834	25,888	1,33,345	2,47,535	3,90,743
2.3 ईसीएस	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	46,625	56,533	60,053	41,71,037	55,85,441	64,95,652
2.5 एनएसीएच	18,758	19,257	16,227	12,81,685	15,41,815	15,25,104
2.6 एनईएफटी	40,407	52,847	72,640	2,87,25,463	3,37,19,541	3,91,36,014
2.7 यूपीआई	4,59,561	8,37,144	13,11,295	84,15,900	1,39,14,932	1,99,95,086
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	12,189	15,343	18,250	10,34,444	12,89,611	16,87,658
3.1 भीम आधार पे	228	214	194	6,113	6,791	6,112
3.2 ईसीएस डीआर	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच	10,755	13,503	16,426	10,26,641	12,80,219	16,78,769
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,207	1,626	1,629	1,689	2,601	2,777
4. कार्ड भुगतान	61,783	63,325	58,470	17,01,851	21,52,245	24,23,563
4.1 क्रेडिट कार्ड	22,399	29,145	35,610	9,71,638	14,32,255	18,31,134
4.2 डेबिट कार्ड	39,384	34,179	22,860	7,30,213	7,19,989	5,92,429
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	65,783	74,667	78,775	2,79,416	2,87,111	2,83,048
6. कागज़ी लिखत	6,999	7,109	6,632	66,50,333	71,72,904	72,12,333
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**7,19,768**	**11,39,382**	**16,44,302**	**17,44,01,233**	**20,86,84,872**	**24,28,23,799**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	**7,24,689**	**11,44,065**	**16,48,234**	**5,23,94,049**	**6,59,11,490**	**7,91,49,461**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	**7,26,767**	**11,46,491**	**16,50,934**	**18,10,51,565**	**21,58,57,776**	**25,00,36,131**

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.31: डिजिटल भुगतान सूचकांक

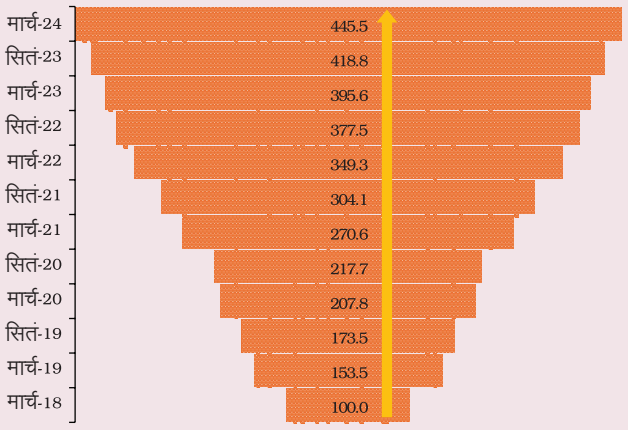

स्रोत: आरबीआई।

9.2 एटीएम

IV.68 2023-24 के दौरान, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) (ऑन-साइट और ऑफ-साइट) की कुल संख्या में मामूली गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण पीएसबी और व्हाइट-लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) थे। मार्च 2024 के अंत में, पीएसबी और पीवीबी की हिस्सेदारी सभी एससीबी द्वारा लगाए गए कुल एटीएम में क्रमशः 61.6 प्रतिशत और 36.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.25 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.25 : एटीएम की संख्या
(मार्च अंत में)

बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
	2023	2024	2023	2024	2023 (2+4)	2024 (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
पीएसबी	78,777	77,033	59,646	57,661	1,38,423	1,34,694
पीवीबी	41,426	45,438	35,549	34,446	76,975	79,884
एफबी	612	603	612	566	1,224	1,169
एसएफबी*	2,797	3,042	24	26	2,821	3,068
पीबी	1	0	62	0	63	0#
सभी एससीबी	**1,23,613**	**1,26,116**	**95,893**	**92,699**	**2,19,506**	**2,18,815**
डब्ल्यूएलए	0	0	35791	34602	35,791	34,602
कुल	**1,23,613**	**1,26,116**	**1,31,684**	**1,27,301**	**2,55,297**	**2,53,417**

टिप्पणियाँ : 1. *: आंकड़े 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित है।
2. #: पीबी द्वारा एटीएम बंद करने के कारण बड़ी गिरावट।
स्रोत : आरबीआई।

IV.69 मार्च 2024 के अंत में, महानगरीय एटीएम में पीएसबी और पीवीबी की हिस्सेदारी लगभग बराबर थी। इसके विपरीत, पीएसबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 78.7 प्रतिशत एटीएम संचालित किए। अधिकांश डब्ल्यूएलए (83.9 प्रतिशत) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे (सारणी IV.26)।

सारणी IV.26: एटीएम का भौगोलिक वितरण: बैंक समूह-वार
(मार्च 2024 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	28,784 (78.7)	39,773 (63.9)	34,100 (62.1)	32,037 (49.2)	1,34,694 (61.6)
निजी क्षेत्र बैंक	7,400 (20.2)	21,207 (34.1)	19,607 (35.7)	31,670 (48.7)	79,884 (36.5)
विदेशी बैंक	112 (0.3)	317 (0.5)	320 (0.6)	420 (0.6)	1,169 (0.5)
लघु वित्त बैंक*	282 (0.8)	938 (1.5)	896 (1.6)	952 (1.5)	3,068 (1.4)
भुगतान बैंक	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
सभी एससीबी	36,578 (100)	62,235 (100)	54,923 (100)	65,079 (100)	2,18,815 (100)
सभी एससीबी (व-द-व वृद्धि)	0.15	0.97	-0.84	-1.25	-0.29
डब्ल्यूएलए	17,496	11,550	3,766	1,790	34,602
डब्ल्यूएलए (व-द-व वृद्धि)	-4.63	-0.28	-1.23	-12.64	-3.32

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक भौगोलिक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम का प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं।
2. *: आंकड़े 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित है।
स्रोत : आरबीआई।

10. प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.70 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हुई प्रगति के कारण हुआ है। डिजिटल भुगतान से लेकर अन्य तकनीकों तक, जिन्होंने वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनएआई) में बढ़ती रुचि और वित्तीय क्षेत्र में इसके एकीकरण से वित्तीय क्षेत्र के लाभ के लिए आगे की प्रगति, नवोन्मेष, दक्षता और सुदृढ़ता को बढ़ावा देने की क्षमता है। हाल ही में रिज़र्व बैंक के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में बैंक जीएआई को अपनाने के मामले में अभी शुरुआती चरण में हैं, हालांकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसके संभावित लाभों को पहचाना है (बॉक्स IV.4)।

11. उपभोक्ता संरक्षण

IV.71 प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों के आगमन और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा इन उत्पादों के बढ़ते उपयोग के साथ, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण ने अभूतपूर्व महत्व हासिल कर लिया है। इस उद्देश्य के लिए, रिज़र्व बैंक वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर)[18] तंत्र का संचालन करता है और आरई में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (आईजीआर) को विनियमित करता है।

11.1 शिकायत निवारण

IV.72 2023-24 के दौरान, केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) को 9.34 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि है। इन शिकायतों में से 31.5 प्रतिशत का समाधान ओआरबीआईओ द्वारा किया गया और शेष का निपटान सीआरपीसी में किया गया। वर्ष के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त अधिकांश शिकायतें पीएसबी से संबंधित थीं, हालांकि कुल में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई (चार्ट IV.32)।

IV.73 नवंबर 2021 से लागू रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) में संरचनात्मक परिवर्तन ने शिकायतों की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाया, जिसमें बहिष्करणों की एक निर्दिष्ट सूची को शामिल करते हुए 'सेवा में कमी' को शिकायत दर्ज करने का एकमात्र आधार बनाया गया। इसलिए,

बॉक्स IV.4: विनियमित संस्थाओं द्वारा जनरेटिव एआई को अपनाना

जेनएआई नियमित और दोहराए जाने वाले कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, और संचालन की दक्षता को बढ़ा सकता है, उत्पादकता में सुधार कर सकता है और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है। साथ ही, यह गोपनीयता के उल्लंघन, जानबूझकर दुरुपयोग, पूर्वग्रहों की शुरूआत या साइबर सुरक्षा और तीसरे पक्ष की निर्भरता जैसे मौजूदा जोखिमों के प्रवर्धन जैसे नए जोखिम भी पेश कर सकता है। अक्तूबर 2024 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 45 प्रतिशत उत्तरदाता आरई ने संकेत दिया कि वे कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने और दस्तावेज़ सारांश जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग कर रहे थे (चार्ट IV.4.1ए) । 55 प्रतिशत उत्तरदाता, जो सर्वेक्षण किए जाने के समय जेनएआई का लाभ नहीं उठा रहे थे, निकट भविष्य में इसी तरह के कार्यों के लिए इसे अपनाने पर विचार कर रहे थे (चार्ट IV.4.1बी)।

अपनाने वालों में से 20 प्रतिशत ने बताया कि वे विशिष्ट उपयोगों के लिए बिल्कुल नए सिरे से मॉडल बनाना पसंद करते हैं। फाइन ट्यूनिंग और डेटा रिट्रीवल के माध्यम से मौजूदा मॉडलों का विस्तार करना सबसे स्वीकार्य तरीका था (चार्ट IV.4.2)। ये रणनीतियाँ आरई को विशिष्ट उपयोग मामलों के लिए जेनएआई मॉडल को अनुकूलित करने, प्रदर्शन को बढ़ाने और मौजूदा वर्कफ़्लो में एआई क्षमताओं को सहजता से शामिल करने की अनुमति देती हैं।

(*जारी*)

[18] रिज़र्व बैंक के एजीआर ढांचे में आरबीआई लोकपाल (आरबीआईओ), उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) तथा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) शामिल हैं। आरबीआईओ आरबी-आईओएस, 2021 के ढांचे के तहत काम करते हैं। सीईपीसी आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में नहीं आने वाले आरई के विरुद्ध शिकायतें लेता है। सीईपीडी आरबी-आईओएस के तहत अपीलीय प्राधिकरण (एए) को सहायता प्रदान करता है और अपील के मामलों को संसाधित करता है।

चार्ट IV.4.1: विनियमित संस्थाओं में जेनएआई को अपनाना

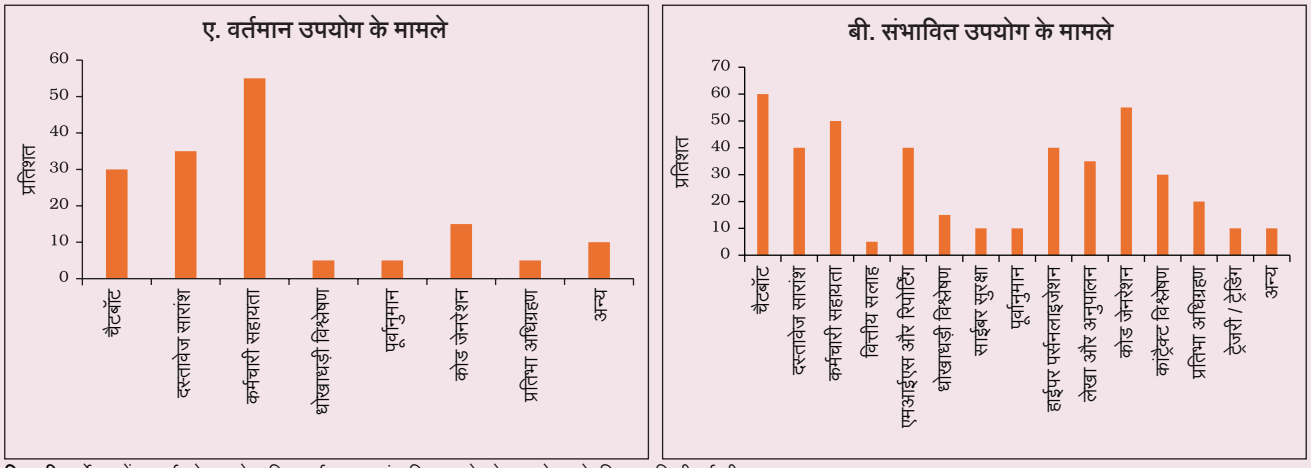

टिप्पणी: सर्वेक्षण में, आरई को एक से अधिक वर्तमान या संभावित उपयोग के मामले चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.4.2: जेनएआई अपनाने के दृष्टिकोण

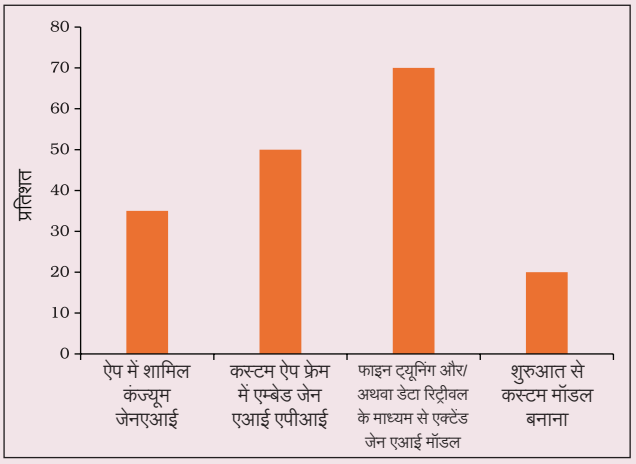

टिप्पणी : सर्वेक्षण में, आरई को अपने वर्तमान या संभावित उपयोग मामलों के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.4.3: आरई द्वारा अनुभव किए गए जोखिम

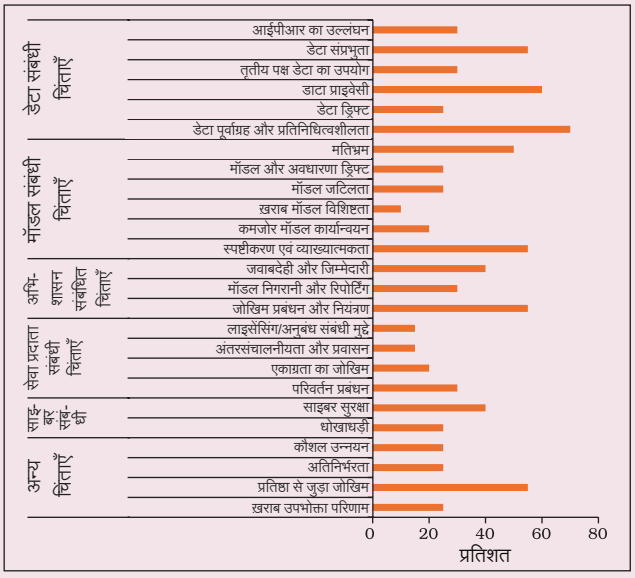

टिप्पणी : सर्वेक्षण में, विनियमित संस्थाओं को अनेक जोखिम चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई.

चिंताओं के बीच, अधिकांश आरई ने डेटा पूर्वाग्रह और प्रतिनिधित्व को चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया, इसके बाद डेटा गोपनीयता और मॉडलों की व्याख्या का स्थान रहा (चार्ट IV.4.3)। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए, अधिकांश आरई ने ह्यूमन-इन-द-मिडल (एचआईटीएम) दृष्टिकोण[19] को अपनाया। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए, आरई ने जेनएआई-आधारित उपकरणों को प्रशिक्षित करने या उन्हें बेहतर बनाने के लिए गोपनीय या संवेदनशील डेटा का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या छद्म नाम वाली आंतरिक जानकारी का उपयोग करने की सूचना दी। सर्वेक्षण प्रतिभागियों में से 90 प्रतिशत ने कोर बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए जेनएआई का उपयोग नहीं करना पसंद किया।

शिकायतों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्षों में आकड़ों को कड़ाई से तुलनीय नहीं बनाया जा सकता है। उक्त चेतावनी के साथ, ऋण और अग्रिम, मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और जमा खातों से संबंधित शिकायतें 2023-24 के दौरान सबसे अधिक थीं, जो कुल शिकायतों का 64 प्रतिशत थीं (सारणी IV.27)।

[19] एचआईटीएम एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसके तहत एआई प्रणालियों के उपयोग में निरंतर मानवीय निरीक्षण, निर्णय और नियंत्रण को एकीकृत किया जाता है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ एआई-जनरेटेड आउटपुट की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और नैतिक संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

चार्ट IV.32: ओआरबीआईओ में प्राप्त इकाई प्रकार-वार शिकायतें

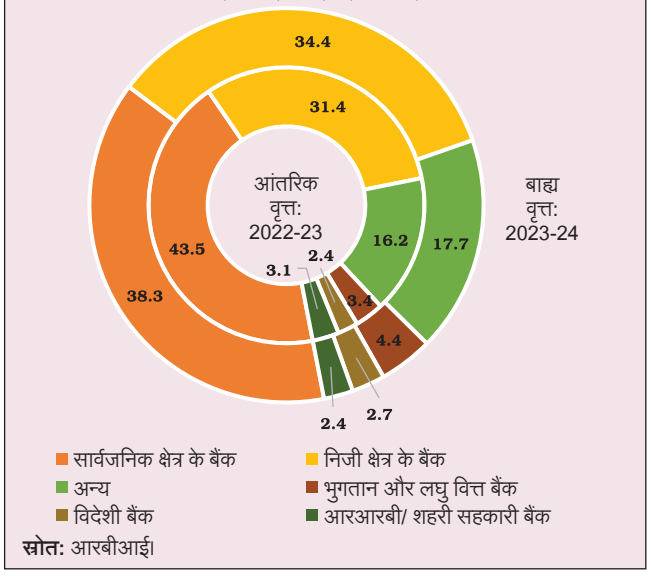

स्रोत: आरबीआई।

IV.74 वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में शहरी और महानगरीय क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का हिस्सा 71.6 प्रतिशत था, जो इन क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता को दर्शाता है (चार्ट IV.33ए)। आरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में पीएसबी और पीवीबी का हिस्सा 72.7 प्रतिशत था। पेंशन से संबंधित लगभग सभी शिकायतें पीएसबी के विरुद्ध दर्ज की गईं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पेंशनभोगी पसंद करते हैं।

सारणी IV.27: आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति

	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4
ऋण और अग्रिम	30,734	59,762	85,281
मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	42,271	43,167	57,242
जमा खाते	16,989	34,481	46,358
क्रेडिट कार्ड	34,828	34,151	42,329
एटीएम/डेबिट कार्ड	41,849	29,929	25,231
अन्य	36,607	22,551	24,355
परा बैंकिंग	1,608	2,782	4,380
पेंशन भुगतान	6,206	4,380	4,108
प्रेषण	3,443	2,940	4,101
नोट और सिक्के	302	511	539
उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	37,880	20	-
बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना	14,519	3	-
डीएसए और रिकवरी एजेंट	1,640	7	-
प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता	22,420	5	-
बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	5,069	1	-
बीओ योजना के दायरे से बाहर	8,131	-	-
कुल	**3,04,496***	**2,34,690^**	**2,93,924@**

टिप्पणियाँ : 1. *: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 1,13,688 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।
2. ^: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 4,68,854 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।
3. @ सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 6,40,431 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : आरबीआई।

दूसरी ओर, क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा (60.1 प्रतिशत) पीवीबी के विरुद्ध दर्ज किया गया (चार्ट IV.33बी)।

11.2 जमा बीमा

IV.75 जमा बीमा वित्तीय सुरक्षा-जाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो बैंकिंग क्षेत्र में जनता के विश्वास को, विशेष

चार्ट IV.33: शिकायतों का वितरण

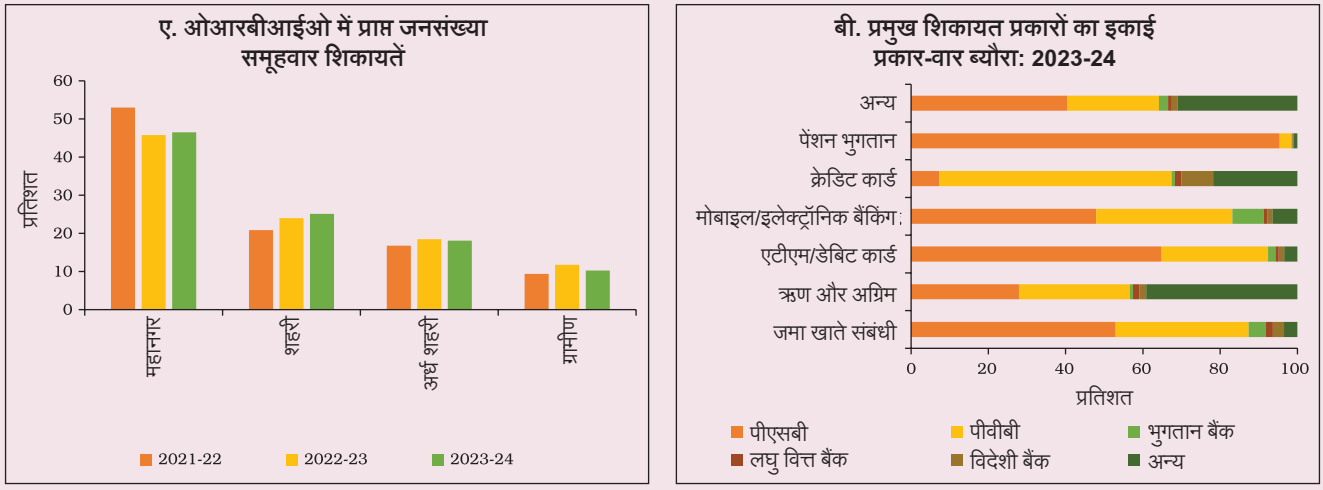

स्रोत: आरबीआई।

रूप से छोटे जमाकर्ताओं के बीच, बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। भारत में, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करते हुए जमा बीमा का प्रबंधन करती है। मार्च 2024 के अंत में डीआईसीजीसी द्वारा 1,997 बैंकों का बीमा किया गया था। वर्तमान में, भारत में जमा बीमा कवरेज सीमा प्रति खाता प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख है। यह सीमा 97.7 प्रतिशत जमा खातों को कवर करती है और मूल्य के संदर्भ में, 43.1 प्रतिशत मूल्यांकन योग्य जमाराशियों का बीमा किया जाता है (सारणी IV.28)।

IV.76 2023-24 में मूल्यांकन योग्य जमाराशियों में बीमाकृत जमाराशियों का अनुपात घट गया, जो बढ़ते जमा आधार को दर्शाता है (चार्ट IV.34)।

IV.77 डीआईसीजीसी के साथ मिलकर जमा बीमा निधि (डीआईएफ) का गठन किया जाता है, ताकि परिसमापन या सर्वसमावेशी निर्देश (एआईडी) लागू होने की स्थिति में बीमित

चार्ट IV.34: कर योग्य जमाराशियों के प्रतिशत के अनुसार बैंक समूहवार बीमित जमाराशियां
(मार्च के अंत में)

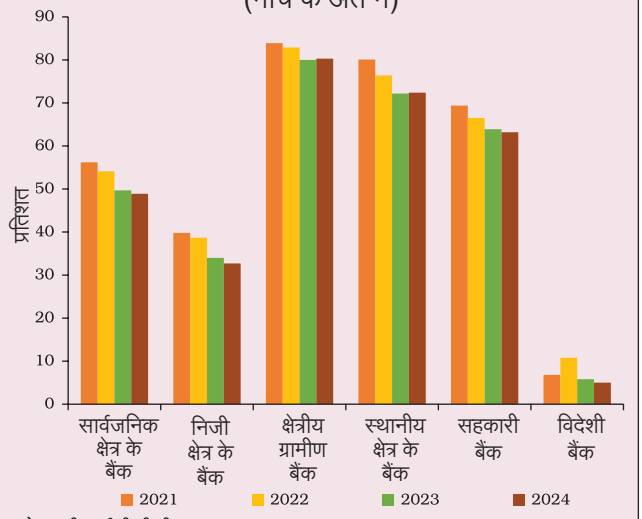

स्रोत: डीआईसीजीसी।

जमाराशियों के दावों का निपटान किया जा सके। 2023-24 के दौरान, डीआईएफ के माध्यम से ₹1,432 करोड़ के दावों का निपटान किया गया। मार्च 2024 के अंत में, डीआईएफ में जमाशेष राशि ₹1,98,753 करोड़ थी। बीमित जमाराशियों (9.1 प्रतिशत) की तुलना में डीआईएफ (17.2 प्रतिशत) की

सारणी IV.28: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशि

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	31 मार्च 2023 के अंत में				31 मार्च 2024 के अंत में (पी			
	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमित जमा	निर्धारणीय जमा	आईडीआर {(3) / (4)}	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमित जमा	निर्धारणीय जमा	आईडीआर {(3) / (4)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. वाणिज्यिक बैंक (i to vii)	**139**	**79,22,120**	**1,83,48,838**	**43.2**	**140**	**86,66,416**	**2,06,73,077**	**41.9**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	52,20,324	1,05,07,639	49.7	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	21,20,937	62,37,833	34.0	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) विदेशी बैंक	43	50,037	8,62,909	5.8	44	50,568	10,08,506	5.0
iv) लघु वित्तीय बैंक	12	66,745	1,63,183	40.9	12	89,532	2,15,426	41.6
v) भुगतान बैंक	6	12,533	12,694	98.7	6	16,794	16,937	99.2
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,50,675	5,63,377	80.0	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	869	1,204	72.2	2	937	1,295	72.4
II. सहकारी बैंक (i to iii)	**1,887**	**7,09,139**	**11,10,076**	**63.9**	**1,857**	**7,46,290**	**11,79,084**	**63.3**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,502	3,62,991	5,34,413	67.9	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	64,041	1,46,931	43.6	33	64,202	1,48,080	43.4
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,82,107	4,28,733	65.8	352	3,10,242	4,74,041	65.4
कुल (I+II)	**2,026**	**86,31,259**	**1,94,58,915**	**44.4**	**1,997**	**94,12,705**	**2,18,52,160**	**43.1**

टिप्पणी: आईडीआर: बीमाकृत जमा अनुपात
स्रोत : डीआईसीजीसी।

वृद्धि के साथ, आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)[20] मार्च 2024 के अंत में यह एक साल पहले के 1.96 प्रतिशत से बढ़कर 2.11 प्रतिशत हो गया। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 21 के तहत, निगम को बीमा भुगतान की वसूली करने का अधिकार है। 2023-24 के दौरान, डीआईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान ₹883 करोड़ की तुलना में ₹901 करोड़ के दावों की कुल वसूली की।

12. वित्तीय समावेशन

IV.78 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय पहुँच में सुधार के लिए अपनी पहल जारी रखी, जिसमें समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित नवोन्मेषों का लाभ उठाना भी शामिल है। भारत में तेज़ गति से हो रहे डिजिटलीकरण के बावजूद, 2010 से 2023 की अवधि के दौरान प्रति एक लाख की आबादी पर वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई (चार्ट IV.35ए)। भारत में प्रति व्यक्ति एटीएम की उपलब्धता भी 2010 से तीन गुना बढ़ गई है (चार्ट IV.35बी)।

12.1 वित्तीय समावेशन योजनाएं

IV.79 वित्तीय समावेशन योजनाएँ (एफआईपी) बैंकिंग और बीसी आउटलेट्स की संख्या, बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में प्राप्त ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएँ, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) में लेन-देन और व्यवसाय संवाददाताओं - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से लेन-देन जैसे मापदंडों पर बैंकों की उपलब्धियों को दर्शाती हैं। मार्च 2024 के अंत में, बीसी मोड के माध्यम से बीएसबीडीए में जमा राशि शाखाओं के माध्यम से जमा राशि से अधिक हो गई, जो जमीनी स्तर पर बीसी मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाता है (सारणी IV.29)।

12.2 वित्तीय समावेशन सूचकांक

IV.80 रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआईआई) देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति पर नज़र रखता है। यह तीन आयामों *अर्थात्* पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता पर आधारित 97 संकेतकों पर जानकारी एकत्र करता है। यह सूचकांक मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.36)। 2023-24 में एफआईआई में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम द्वारा किया गया था, जो वित्तीय समावेशन के प्रसार को दर्शाता है।

चार्ट IV.35: चुनिंदा देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति

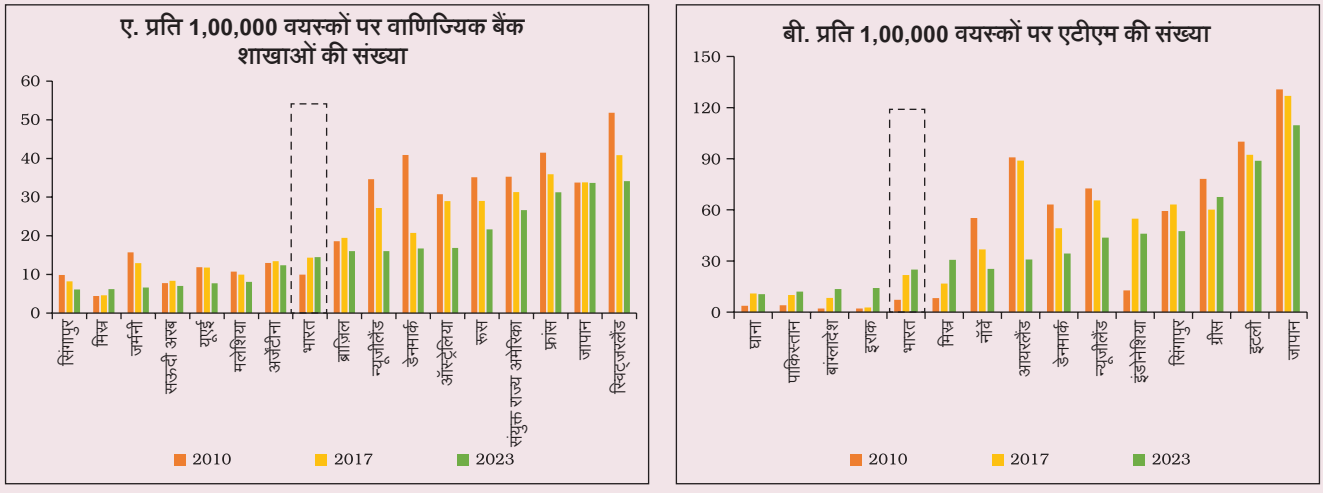

स्रोत: वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण, 2023, आईएमएफ।

[20] बीमाकृत जमाराशि से जमा बीमा निधि का अनुपात।

सारणी IV.29: वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति
(मार्च के अंत में)

क्र. सं.		2015	2020	2021	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6	7	8
बैंकिंग की पहुँच							
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- शाखाएं	49,571	54,561	55,112	53,287	53,802	54,198
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट>2000-बीसी	90,877	1,49,106	8,50,406	18,92,462	13,48,038	12,66,756
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट<2000-बीसी	4,08,713	3,92,069	3,40,019	3,26,008	2,77,844	2,80,922
4	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – कुल बीसी	4,99,590	5,41,175	11,90,425	22,18,470	16,25,882	15,47,678
5	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	96,847	6,35,046	4,26,745	12,95,307	4,15,218	3,06,658
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)							
6	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	2,103	2,616	2,659	2,661	2,750	2,768
7	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	36,498	95,831	1,18,392	1,20,464	1,33,661	1,46,306
8	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	1,878	3,388	3,796	4,015	4,105	4,290
9	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	7,457	72,581	87,623	1,07,415	1,29,531	1,53,489
10	बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	3,981	6,004	6,455	6,677	6,856	7,059
11	बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	43,955	1,68,412	2,06,015	2,27,879	2,63,192	2,99,795
12	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा प्राप्त (संख्या लाख में)	76	64	60	68	51	48
13	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ (राशि करोड़ में)	1,991	529	534	516	572	564
केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)							
14	केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	426	475	466	473	493	515
15	केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	4,38,229	6,39,069	6,72,624	7,10,715	7,68,339	8,47,237
16	जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	92	202	202	96	66	23
17	जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,31,160	1,94,048	1,55,826	1,70,203	1,90,568	34,340
व्यावसायिक संवाददाता							
18	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	4,770	32,318	30,551	28,533	34,055	36,388
19	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	85,980	8,70,643	8,49,771	9,05,252	11,39,521	13,10,973

टिप्पणीयाँ : 1. *: अनंतिम
2. #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।

स्रोत : पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणी।

चार्ट IV.36: आरबीआई – वित्तीय समावेशन सूचकांक

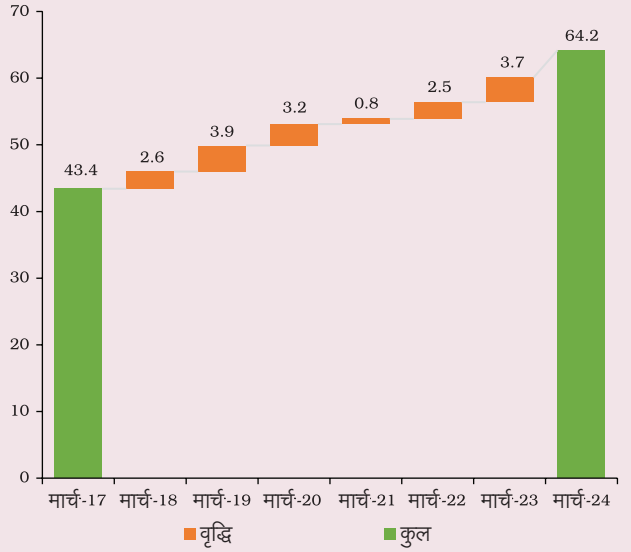

स्रोत: आरबीआई।

12.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.81 समाज के हाशिए पर पड़े क्षेत्रों और वर्गों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पीएमजेडीवाई ने अगस्त 2024 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे करेगी। पीएमजेडीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या 54.2 करोड़ तक पहुँच गई, जिसमें 11 दिसंबर, 2024 तक ₹2.4 लाख करोड़ की जमा राशि थी और 66.6 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे (चार्ट IV.37ए)। हाल ही में कुछ नरमी के बावजूद, पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि इसके लॉन्च के बाद से चार गुना बढ़ गई है, जो बढ़ते उपयोग और पहले से बैंक रहित व्यक्तियों के औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सफल एकीकरण को दर्शाता है (चार्ट IV.37बी)।

चार्ट IV.37: पीएमजेडीवाई में प्रगति

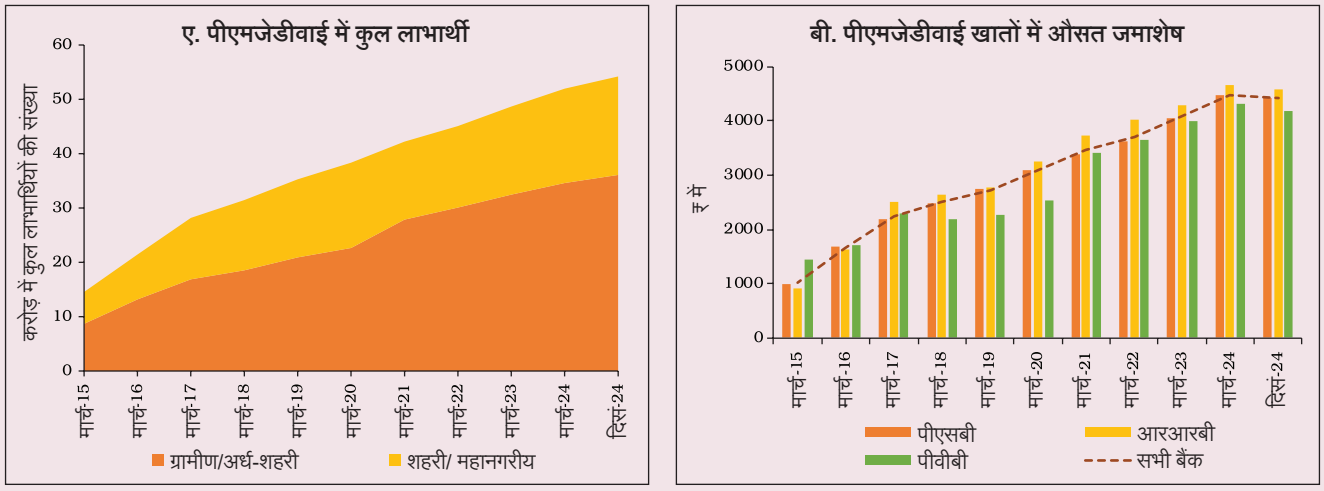

स्रोत: पीएमजेडीवाई, भारत सरकार।

12.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नई बैंक शाखाएं

IV.82 यद्यपि बैंक डिजिटल चैनलों पर अधिक जोर दे रहे हैं, तथापि, भौतिक शाखाएँ ग्राहक जुड़ाव का मुख्य आधार बनी हुई हैं। 2023-24 के दौरान, 41.9 प्रतिशत बैंक शाखाएँ 50,000 से कम आबादी वाले केंद्रों में खोली गईं, जिससे छोटे शहरों और गाँवों में बैंकिंग की पहुँच में सुधार हुआ (सारणी IV.30)।

सारणी IV.30: एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विवरण

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
स्तर 1	1,545 (50.0)	1,558 (47.9)	2,285 (43.1)	2,675 (49.7)
स्तर 2	278 (9.0)	233 (7.2)	468 (8.8)	452 (8.4)
स्तर 3	475 (15.4)	427 (13.1)	812 (15.3)	683 (12.7)
स्तर 4	265 (8.6)	292 (9.0)	545 (10.3)	433 (8.0)
स्तर 5	179 (5.8)	229 (7.0)	424 (8.0)	368 (6.8)
स्तर 6	347 (11.2)	512 (15.7)	768 (14.5)	768 (14.3)
कुल	3,089 (100.0)	3,251 (100.0)	5,302 (100.0)	5,379 (100.0)

टिप्पणियाँ : 1. केंद्रों का स्तर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है: 'स्तर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 2' में 50,000 से 99,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 3' में 20,000 से 49,999 तक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 4' में 10,000 से 19,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 5' में 5,000 से 9,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, और 'स्तर 6' में 5000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं।
2. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
3. सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े किसी विशेष क्षेत्र में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या के अनुपात को दर्शाते हैं।

स्रोत : सीआईएसबीआई, आरबीआई। सीआईएसबीआई डेटा गतिशील प्रकृति का है और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

IV.83 2023-24 के दौरान खोली गई नई शाखाओं में से 65.5 प्रतिशत पीवीबी द्वारा खोली गईं, जिनमें से 44.1 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं (चार्ट IV.38)।

चार्ट IV.38: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खुली बैंक शाखाओं का वितरण

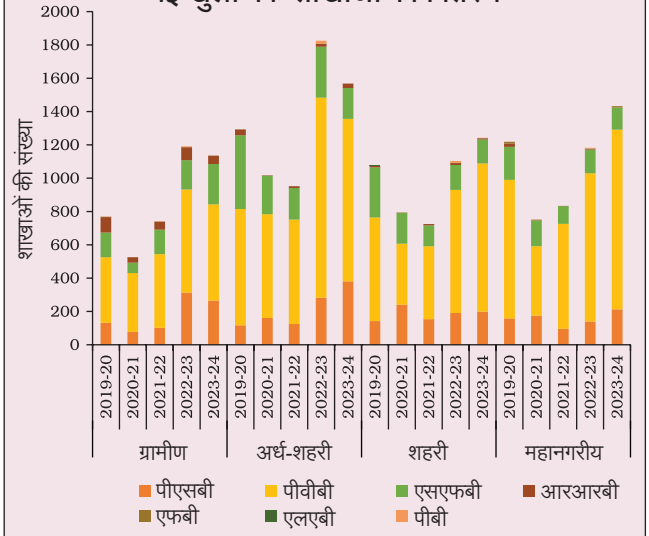

स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई।

12.5 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.84 सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें कम मूल्य के ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी आबादी के वंचित और बैंक रहित वर्गों तक होती है, जिससे सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 2023-24 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण की डिलीवरी में लगातार प्रगति देखी गई। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले एसएचजी की संख्या 2022-23 में 43.0 लाख से बढ़कर 2023-24 में 54.8 लाख हो गई। एसएचजी के बकाया ऋण में पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एसएचजी को ऋण वितरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित रहा (चार्ट IV.39)। संयुक्त देयता समूहों को वितरित ऋण में पिछले वर्ष के 18.3 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान 41.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

चार्ट IV.39: स्वयं सहायता समूह - ऋण का क्षेत्रीय वितरण और औसत ऋण आकार
(मार्च 2024 के अंत में)

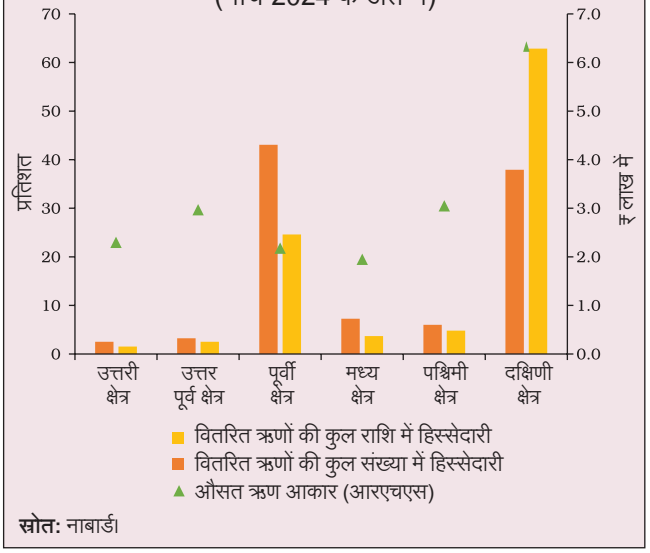

स्रोत: नाबार्ड।

12.6 व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस)

IV.85 टीआरईडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करता है। ये प्राप्तियां कॉरपोरेट और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीददारों से देय हो सकती हैं। 7 जून, 2023 को टीआरईडीएस दिशानिर्देशों में संशोधन ने वित्तपोषकों को चूक जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए बीमा सक्षम बनाया, वित्तपोषकों के समूह का विस्तार किया और फैक्टरिंग इकाइयों के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम किया। इन परिवर्तनों को दर्शाते हुए, 2023-24 में अपलोड और वित्तपोषित चालान की संख्या और मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। वित्तपोषित चालान की सफलता दर 2022-23 में 93.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 94.4 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.31)।

12.7 क्षेत्रीय बैंकिंग व्यापन

IV.86 पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रति बैंक शाखा जनसंख्या के आधार पर बैंकिंग पहुँच में सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। प्रति हज़ार जनसंख्या पर जमा खातों की संख्या के आधार पर उपयोग में सुधार सबसे ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र में स्पष्ट हुआ (चार्ट IV.40)।

सारणी IV.31: टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

वित्तीय वर्ष	अपलोड किया गया बीजक		वित्तपोषित बीजक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2020-21	8,61,560	19,670	7,86,555	17,080
2021-22	17,33,553	44,112	16,40,824	40,309
2022-23	27,24,872	83,955	25,58,531	76,646
2023-24	44,04,148	1,51,343	41,58,554	1,38,241

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.40: बैंकों की क्षेत्रीय पहुंच

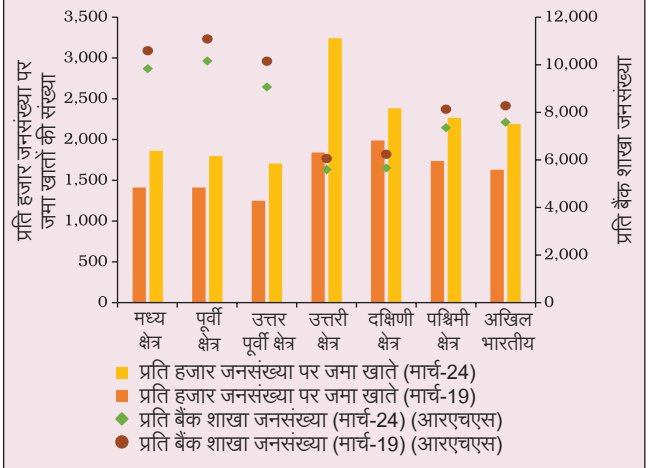

टिप्पणियाँ: 1 कुल जमा खातों में अंतर-बैंक जमा खाते शामिल नहीं हैं।
2. आंकड़े एससीबी से संबंधित डेटा।

स्रोत: आरबीआई और रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। भारत, गृह मंत्रालय।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक[21]

IV.87 मार्च 2024 के अंत में, 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख) में 22,078 शाखाओं के माध्यम से संचालित 12 एससीबी द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी थे। अपने अधिदेश के अनुरूप, आरआरबी की 91.8 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक है, और इस क्षेत्र ने आरआरबी के कुल लाभ में लगभग आधा योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

13.1 तुलन पत्र विश्लेषण

IV.88 देयताओं के पक्ष में उधारी में मंदी के कारण आरआरबी की संयुक्त तुलन पत्र में वृद्धि पिछले वर्ष के 9.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 8.9 प्रतिशत हो गई, जबकि जमा और ऋण वृद्धि में तेजी आई (सारणी IV.32) ।

सारणी IV.32: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मद	मार्च अंत में		व-द-व संवृद्धि प्रतिशत में	
		2023	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	17,232	19,042	15.8	10.5
2	आरक्षित निधियाँ	40,123	46,659	16.8	16.3
3	जमाराशियाँ	6,08,509	6,59,815	8.2	8.4
	3.1 चालू खाते	11,945	11,952	-0.8	0.1
	3.2 बचत खाते	3,19,572	3,47,193	8.5	8.6
	3.3 सावधि जमा	2,76,992	3,00,670	8.2	8.5
4	उधार	84,712	92,444	14.7	9.1
	4.1 नाबार्ड से	73,119	77,166	9.0	5.5
	4.2 प्रायोजक बैंक	3,408	4,293	-12.1	26.0
	4.3 अन्य	8,185	10,986	177.7	34.2
5	अन्य देयताएं	20,885	22,120	5.8	5.9
	कुल देयताएं / आस्तियां	**7,71,462**	**8,40,080**	**9.4**	**8.9**
6	उपलब्ध नकद	2,888	2,933	-7.4	1.6
7	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	29,332	30,990	32.3	5.7
8	चालू खाते में शेष राशि	7,150	8,173	-12.0	14.3
9	निवेश	3,13,401	3,19,099	6.0	1.8
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	3,86,951	4,45,286	13.0	15.1
11	स्थावर सम्पदा	1,406	1,581	12.0	12.4
12	अन्य आस्तियां, *जिनमें से*	30,333	32,019	-6.9	5.6
	12.1 संचित हानि	9,841	8,921	8.6	-9.4

टिप्पणी : पी: अनंतिम
स्रोत : नाबार्ड।

IV.89 आरआरबी के कुल निधिगत स्रोतों में जमाराशि का हिस्सा 78.5 प्रतिशत था, हालांकि 2023-24 के दौरान उनकी जमा वृद्धि एससीबी से कम रही। 2023-24 के दौरान आरआरबी की कुल जमाराशि में कम लागत वाली सीएएसए जमाराशि का हिस्सा 54.4 प्रतिशत था, जो पीबी को छोड़कर एससीबी की सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है।[22] आरआरबी में प्रति खाता औसत पीएमजेडीवाई जमा राशि ₹4,667 थी, जो अन्य श्रेणियों के बैंकों के लिए ₹4,432 से अधिक थी। मार्च 2024 के अंत में आरआरबी का सी -डी अनुपात बढ़कर 71.4 प्रतिशत हो गया, जो 33 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है, क्योंकि ऋण और अग्रिम की वृद्धि ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।

[21] आरआरबी की स्थापना छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण वितरण के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक चैनल के रूप में की गई थी। उनके कार्यात्मक फोकस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य और लघु उद्योग रहे हैं।

[22] पी.बी. को सावधि जमा जुटाने की अनुमति नहीं है।

13.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.90 2018-20 के दौरान निवल घाटे के बाद, आरआरबी ने 2023-24 के दौरान ₹ 7,571 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक समेकित निवल लाभ दर्ज किया। उच्च आय वृद्धि और परिचालन व्यय (विशेष रूप से स्टाफ लागत) में कमी ने लाभप्रदता को बढ़ावा दिया (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		व-द-व परिवर्तन प्रतिशत में	
		2022-23	2023-24(पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए	**आय (i + ii)**	**59,427**	**70,443**	**5.0**	**18.5**
	i. ब्याज आय	53,640	61,341	11.6	14.4
	ii. अन्य आय*	5,787	9,101	-32.2	57.3
बी	**व्यय (i+ii+iii)**	**54,454**	**62,872**	**2.0**	**15.5**
	i. खर्च किया गया ब्याज	26,704	33,237	7.6	24.5
	ii. परिचालन व्यय	21,878	21,267	2.7	-2.8
	जिनमें से, वेतन बिल	16,683	15,305	2.1	-8.3
	iii. प्रावधान और आकस्मिकताएं*	5,872	8,368	-19.1	42.5
	जिनमें से, आय कर	1,424	2,430	11.4	70.7
सी	**लाभ**				
	i. परिचालन लाभ	10,845	15,938	4.9	47.0
	ii. निवल लाभ	4,974	7,571	54.5	52.2
डी	**कुल औसत आस्तियां**	**7,16,796**	**7,90,902**	**7.5**	**10.3**
ई	**वित्तीय अनुपात #**				
	i. परिचालन लाभ	1.5	2.0		
	ii. निवल लाभ	0.7	1.0		
	iii. आय (ए + बी)	8.3	8.9		
	ए) ब्याज आय	7.5	7.8		
	बी) अन्य आय	0.8	1.2		
	vi. व्यय (ए+बी+सी)	7.6	7.9		
	ए) खर्च किया गया ब्याज	3.7	4.2		
	बी) परिचालन व्यय	3.1	2.7		
	जिनमें से, वेतन बिल	2.3	1.9		
	ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.8	1.1		
एफ	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**				
	सकल एनपीए अनुपात	7.3	6.2		
	सीआरएआर	13.4	14.2		

टिप्पणियाँ : 1. पी: अनंतिम
2. #: औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
3. *: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर रिज़र्व बैंक के मौजूदा मास्टर निदेशों के अनुसार, निवेश में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, जिसे पहले व्यय के प्रावधान और आकस्मिकता शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाता था, अब अन्य आय से घटाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, एमटीएम घाटे के लिए आरआरबी द्वारा प्रावधानित ₹ 2,204.4 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अन्य आय से घटा दिया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

IV.91 मार्च 2024 के अंत में आरआरबी का जीएनपीए अनुपात दस साल के निचले स्तर 6.2 प्रतिशत पर पहुँच गया (चार्ट IV.41)। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ प्रावधान बफर में भी वृद्धि हुई।

IV.92 2021-23 के दौरान ₹10,890 करोड़ की पूंजीगत अंतर्वेशन के परिणामस्वरूप, 9 प्रतिशत के विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर से कम सीमा वाले आरआरबी की संख्या में कमी आई (चार्ट IV.42ए)। मार्च 2024 के अंत में समेकित सीआरएआर 14.2 प्रतिशत के सार्वकालिक उच्च स्तर पर था (चार्ट IV.42बी)। घाटे में चल रहे आरआरबी की संख्या 2019-20 में 18 से लगातार घटकर 2023-24 में 3 हो गई है (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

IV.93 2023-24 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण आरआरबी के कुल ऋण का 87 प्रतिशत रहा और सभी बैंकों ने अपने एएनबीसी/सीईओबीई का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य पूरा किया (सारणी IV.34 और परिशिष्ट सारणी IV.15)।

चार्ट IV.41: आरआरबी की आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)

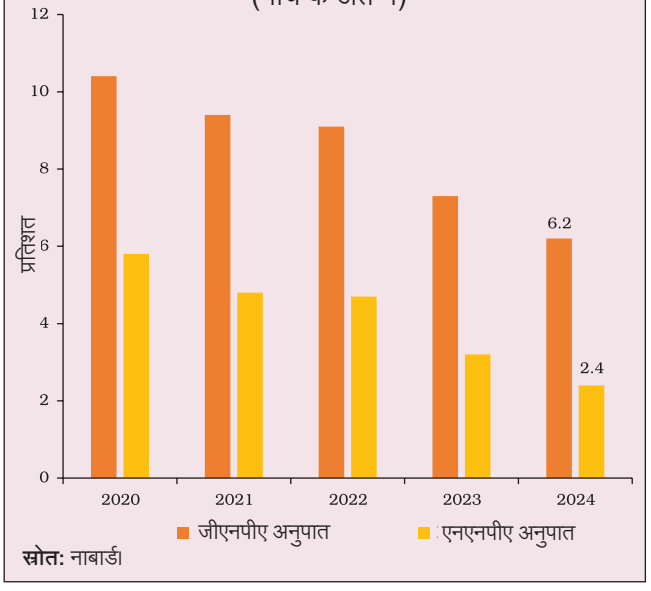

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट IV.42: आरआरबी का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
(मार्च के अंत में)

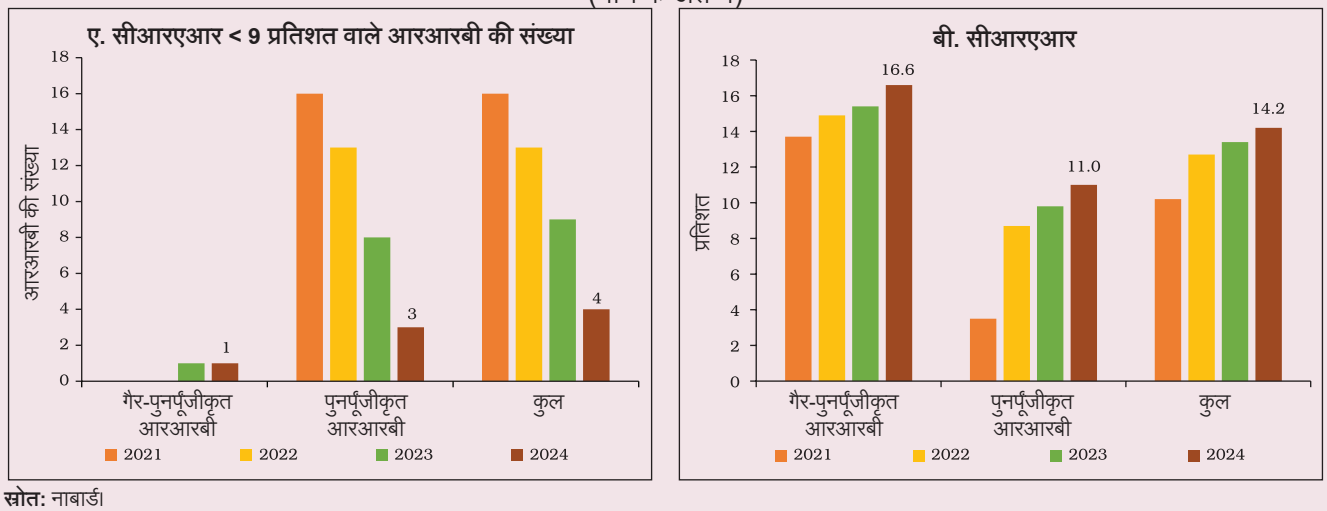

स्रोत: नाबार्ड।

14. स्थानीय क्षेत्र बैंक[23]

IV.94 मार्च 2024 के अंत में, दो एलएबी (मार्च 2004 के अंत में चार से कम) थे, जिनकी 79 शाखाएँ परिचालन में थीं। वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण के साथ-साथ जमा वृद्धि में गिरावट आने से एलएबी के समेकित तुलन पत्र वृद्धि में कमी आई। जमा वृद्धि से अधिक ऋण वृद्धि होने से, सी-डी अनुपात एक वर्ष पहले के 81.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 81.4 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.35)।

सारणी IV.34: आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	उद्देश्य	2023	2024(P)
1	2	3	4
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**3,62,503**	**4,08,810**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	88.3	87.0
	i. कृषि	2,81,971	3,16,671
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	49,323	57,639
	iii. शिक्षा	1,744	1,609
	vi. आवास	24,503	2,6047
	v. अन्य	4,963	6,843
II	**गैर-प्राथमिकता (i से vi)**	**48,236**	**61,300**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	*11.7*	*13.0*
	i. कृषि	16	17
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	84	187
	iii. शिक्षा	218	343
	iv. आवास	9,100	13,620
	v. व्यक्तिगत ऋण	12,985	17,788
	vi. अन्य	25,833	29,345
	कुल (I+II)	**4,10,738**	**4,70,109**

टिप्पणी : पी: अनंतिम।
स्रोत : नाबार्ड।

14.1 एलएबी का वित्तीय प्रदर्शन

IV.95 वर्ष 2023-24 के दौरान एलएबी का लाभ, ब्याज आय वृद्धि में धीमापन और ब्याज व्यय वृद्धि में तेजी के कारण गिरा (सारणी IV.36)।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2023	2024
1	2	3
1. आस्तियां	1,474 (15.7)	1,584 (7.5)
2. जमाराशियां	1,190 (16.6)	1,271 (6.8)
3. सकल अग्रिम	965 (15.1)	1,034 (7.2)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

[23] स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) छोटे, निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं, जिनकी स्थापना कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान की जा सकें। एलएबी के पास परिचालन का एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो विशेष रूप से तीन समीपवर्ती जिलों को शामिल करते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को लक्षित करता है।

सारणी IV.36: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

क्र. सं.		राशि (₹ करोड़ में)		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए.	**आय** (i+ii)	**179**	**197**	**12.6**	**10.1**
	i. ब्याज आय	153	172	17.1	12.8
	ii. अन्य आय	26	25	-7.6	-5.7
बी.	**व्यय (i+ii+iii)**	**143**	**162**	**7.7**	**13.7**
	i. ब्याज व्यय	63	79	8.8	25.9
	ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	21	15	-6.8	-26.0
	iii. परिचालनगतगत व्यय	59	68	12.5	14.6
	जिनमें से, वेतन बिल	29	33	14.6	13.5
सी.	**लाभ**				
	i. परिचालनगतगत लाभ/हानि	57	50	17.3	-11.9
	ii. निवल लाभ/ हानि	36	35	37.7	-3.9
डी.	**निवल ब्याज आय**	**90**	**93**	**23.6**	**3.7**
ई.	**कुल आस्तियां**	**1,474**	**1,584**	**15.7**	**7.5**
एफ.	**वित्तीय अनुपात** (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
	i. परिचालनगतगत लाभ	3.9	3.2		
	ii. निवल लाभ	2.5	2.2		
	iii. आय	12.1	12.4		
	iv. ब्याज आय	10.4	10.9		
	v. अन्य आय	1.8	1.6		
	vi. व्यय	9.7	10.2		
	vii. ब्याज व्यय	4.3	5.0		
	viii. परिचालनगतगत व्यय	4.0	4.3		
	ix. वेतन बिल	1.9	2.1		
	x. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.4	1.0		
	xi. निवल ब्याज आय	6.1	5.9		

टिप्पणी : 'वेतन बिल' को कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान के रूप में लिया जाता है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालनगत) भारतीय रिज़र्व बैंक।

15. लघु वित्त बैंक[24]

IV.96 फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के बाद, जून 2024 के अंत में भारत में 7,230 घरेलू शाखाओं के साथ 11 एसएफबी परिचालन में थे।

15.1 तुलन-पत्र

IV.97 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसएफबी की संयुक्त तुलन-पत्र में वृद्धि दोहरे अंकों में थी, जो उनकी स्थापना के बाद से देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप थी। वर्ष 2023-24 के दौरान एसएफबी की ऋण वृद्धि में कमी आई और जमा वृद्धि में तेजी आई, जिससे उधार पर उनकी निर्भरता कम हुई। एसएफबी का सी-डी अनुपात एक वर्ष पहले के 93.0 प्रतिशत से मार्च 2024 के अंत में 90.1 प्रतिशत हो गया, हालांकि यह एससीबी से अधिक रहा (सारणी IV.37)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.98 वर्ष 2023-24 के दौरान लगातार तीसरे वर्ष एसएफबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। आय अनुपात में लाभ, व्यय अनुपात से अधिक होने के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ अनुपात में भी वृद्धि हुई। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	7,811	7,844	8.6	0.4
2	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	23,557	32,957	38	39.9
3	टियर II बॉण्ड और टियर II कर्ज	1,926	2,458	-15.7	27.6
4	जमाराशियां	1,91,372	2,50,896	28	31.1
	4.1 चालू मांग जमा	7,456	10,895	22.7	46.1
	4.2 बचत	54,667	59,691	16.2	9.2
	4.3 सावधि	1,29,248	1,80,310	34.1	39.5
5	उधारियां (टियर-II बॉण्ड सहित)	31,170	28,261	10.8	-9.3
	5.1 बैंक	4,241	4,500	-6.3	6.1
	5.2 अन्य	26,929	23,761	14.1	-11.8
6	अन्य देयताएं और प्रावधान	13,606	15,326	14.1	12.6
	कुल देयताएं और आस्तियां	**2,67,517**	**3,35,284**	**25.1**	**25.3**
7	नकद	1,371	1,333	9.7	-2.8
8	आरबीआई के पास शेष राशि	16,468	16,170	115.8	-1.8
9	अन्य बैंक शेष/ वित्तीय संस्थानों के पास शेष	4,484	6,261	-69	39.6
10	निवेश	58,115	74,283	30.8	27.8
11	ऋण और अग्रिम	1,77,887	2,26,148	28.7	27.1
12	अचल आस्तियां	2,734	3,353	18.7	22.6
13	अन्य आस्तियां	6,455	7,736	15.5	19.8

टिप्पणी : आंकड़े 12 एसएफबी से संबंधित हैं।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालनगत) भारतीय रिज़र्व बैंक।

[24] लघु वित्त बैंक (एसएफबी) विशेष संस्थाएं हैं जो आबादी में से वंचित और कम वंचित वर्गों को औपचारिक बचत के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। एसएफबी का उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी और कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से छोटे व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण प्रदान करना है।

प्रावधान और आकस्मिकताएं (कुल आस्तियों के प्रतिशत के अनुसार) कम हो गईं (सारणी IV.38)।

16. भुगतान बैंक[25]

IV.99 मार्च 2024 के अंत में, 82 शाखाओं के साथ छह पीबी परिचालन में थे। इनमें से, पाँच पीबी ने 2023-24 के दौरान परिचालनगत लाभ की सूचना दी।

सारणी IV.38: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए	**आय** (i + ii)	**33,827**	**45,437**	**35.1**	**34.3**
	i. ब्याज आय	29,806	39,588	34.7	32.8
	ii. अन्य आय	4,022	5,848	38.1	45.4
बी	**व्यय** (i+ii+iii)	**29,663**	**39,214**	**23.3**	**32.2**
	i. ब्याज व्यय	12,139	17,473	27.6	43.9
	ii. परिचालनगतगत व्यय	13,153	17,186	34.0	30.7
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	6,707	8,494	26.4	26.6
	iii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	4,371	4,555	-7.6	4.2
सी	**लाभ (कर पूर्व)**	**5,417**	**7,835**	**321.9**	**44.6**
	i. परिचालनगतगत लाभ (ईबीपीटी)	8,534	10,774	49.7	26.2
	ii. निवल लाभ (पीएटी)	4,162	6,219	327.3	49.4
डी	**कुल आस्तियां**	**2,67,517**	**3,35,284**	**31.8**	**25.3**
ई	**वित्तीय अनुपात #**				
	i. परिचालनगत लाभ	3.2	3.2		
	ii. निवल लाभ	1.6	1.9		
	iii. आय (ए + बी)	12.6	13.6		
	ए. ब्याज आय	11.1	11.8		
	बी. अन्य आय	1.5	1.7		
	iv. व्यय (ए+बी+सी)	11.1	11.7		
	ए. ब्याज व्यय	4.5	5.2		
	बी. परिचालनगत व्यय	4.9	5.1		
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	2.5	2.5		
	सी. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.6	1.4		
एफ़	**विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत में)**				
	सकल एनपीए अनुपात	4.7	2.4		
	सीआरएआर	22.5	21.6		
	कोर सीआरएआर	19.9	19.4		

टिप्पणी : #: कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

16.1 तुलन-पत्र

IV.100 वर्ष 2023-24 के दौरान, भुगतान बैंकों की संयुक्त तुलन-पत्र की वृद्धि में कमी आई, जो मुख्य रूप से देनदारियों के पक्ष में जमा वृद्धि में मंदी के साथ-साथ आस्ति पक्ष में आरबीआई के पास नकदी और शेष राशि की वृद्धि में मंदी के कारण हुई। पीबी की जमा राशि देनदारियों की 62.4 प्रतिशत थी (सारणी IV.39)।

16.2 *वित्तीय प्रदर्शन*

IV.101 वर्ष 2022-23 के दौरान पीबी अपने स्थापना के बाद पहली बार लाभ में रहे और यह गति 2023-24 के दौरान भी जारी रही, हालांकि इसकी गति धीमी रही (सारणी IV.40)। पीबी की कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा 2021-22 के दौरान 91.3 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 81.7 प्रतिशत हो गया।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	मद	राशि (₹ करोड़ में)			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल पूंजी एवं आरक्षित निधि	2,485	2,938	3,440	41	18.2	17.1
2	जमाराशियां	7,859	12,222	16,330	69.9	55.5	33.6
3	अन्य देयताएं और प्रावधान	7,771	8,380	6,385	28	7.8	-23.8
	कुल देयताएं/ आस्तियां	**18,115**	**23,540**	**26,155**	**45**	**29.9**	**11.1**
1	आरबीआई के पास नकदी और शेष राशि	1,560	2,453	3,094	24.3	57.3	26.1
2	बैंकों और मुद्रा बाजार के पास शेष राशि	3,322	5,008	4,350	39	50.7	-13.1
3	निवेश	10,178	12,397	14,627	43	21.8	18.0
4	अचल आस्तियां	372	562	1,266	4.7	51.1	125.3
5	अन्य आस्तियां	2,683	3,120	2,819	98.8	16.3	-9.6

टिप्पणी : आंकड़े 6 पीबी से संबंधित है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

[25] भुगतान बैंक (पीबी) विशेष वित्तीय संस्थान हैं जिनकी स्थापना तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

क्र. सं.		राशि (₹ करोड़ में)			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
ए	**आय**						
	i. ब्याज आय	460	877	1,441	27.5	90.7	64.3
	ii. गैर-ब्याज आय	4,801	5,630	6,416	34.8	17.3	14.0
बी	**व्यय**						
	i. ब्याज व्यय	157	247	356	56.0	57.5	44.1
	ii. परिचालनगत व्यय	5,216	6,154	7,292	13.8	18.0	18.5
	iii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	20	15	115	-44.4	-25.5	688.6
	जिसमें से,						
	जोखिम प्रावधान	21	4	11	133.3	-81.7	185.3
	कर प्रावधान	-2	8	68	-111.0	415.8	773.4
सी	**निवल ब्याज आय**	**303**	**630**	**1,085**	**15.7**	**107.7**	**72.2**
डी	लाभ						
	i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	-111	106	209	85.4	195.4	97.0
	ii. निवल लाभ / हानि	-131	92	94	83.6	170.0	3.0

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

IV.102 उनका एनआईएम मार्च 2023 के अंत में 3.7 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2024 के अंत में 5.7 प्रतिशत हो गया, जो ब्याज व्यय के सापेक्ष ब्याज आय में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट IV.43)। मार्च 2024 के अंत में पीबी का आरओए और आरओई धनात्मक रहा।

चार्ट IV.43 : भुगतान बैंकों का लाभप्रदता संकेतक

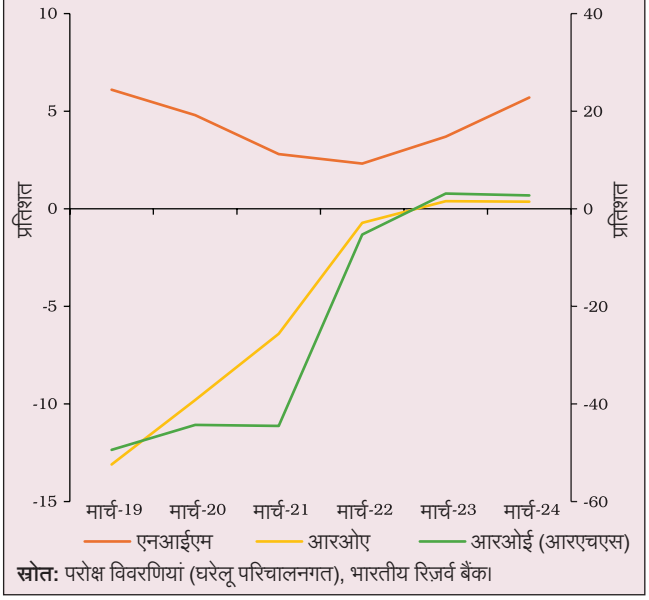

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

IV.103 वर्ष 2023-24 के दौरान पीबी का लागत-से-आय अनुपात और कम हुआ, जो दक्षता में सुधार को दर्शाता है (सारणी IV.41)।

17. समग्र मूल्यांकन

IV.104 वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों के समेकित तुलन-पत्र में मजबूत जमा और ऋण वृद्धि के कारण स्वस्थ गति से विस्तार हुआ। व्यक्तिगत ऋण तथा सेवा क्षेत्रों को दिए गए ऋण से बड़े पैमाने पर ऋण में वृद्धि हुई। बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि चलनिधि और प्रावधान बफर संतोषजनक रहें। कम स्लीपेज से सभी क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता मजबूत हुई। कुल अग्रिमों में गैर-जमानती अग्रिमों की हिस्सेदारी में कमी आई, जो इन क्षेत्रों में जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक के उपायों को दर्शाता है।

IV.105 नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ नई चुनौतियों के साथ-साथ अभिनव समाधान लाकर बैंकिंग उद्योग को नया रूप

सारणी IV.41: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात
(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	मद	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	आस्तियां पर प्रतिलाभ	-0.7	0.4	0.4
2	इक्वटी पर प्रतिलाभ	-5.3	3.1	2.7
3	कुल आस्तियों की तुलना में निवेश	56.1	52.7	55.9
4	निवल ब्याज मार्जिन	2.3	3.7	5.7
5	दक्षता (लागत-आय अनुपात)	102.2	98.3	97.2
6	कार्यशील निधि की तलना में परिचालनगत लाभ	-0.6	0.5	0.8
7	लाभ का अंतर	-2.6	1.5	1.3

टिप्पणी : आंकड़े 6 पीबी से संबंधित है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

दे रही हैं। उत्पादकता और दक्षता लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हुए, भारतीय बैंक डिजिटलीकरण में सबसे आगे हैं। हालाँकि, नई तकनीक को अपनाने के साथ, साइबर हमलों, डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और परिचालन विफलताओं के जोखिम भी बढ़ गए हैं।

IV.106 भविष्य में, बैंकों के लिए अपने जोखिम प्रबंधन मानकों, आईटी गवर्नेंस व्यवस्थाओं और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तथा लेनदेन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है, ताकि संदिग्ध और असामान्य लेनदेन सहित अनैतिक गतिविधियों की जांच रखी जा सके।